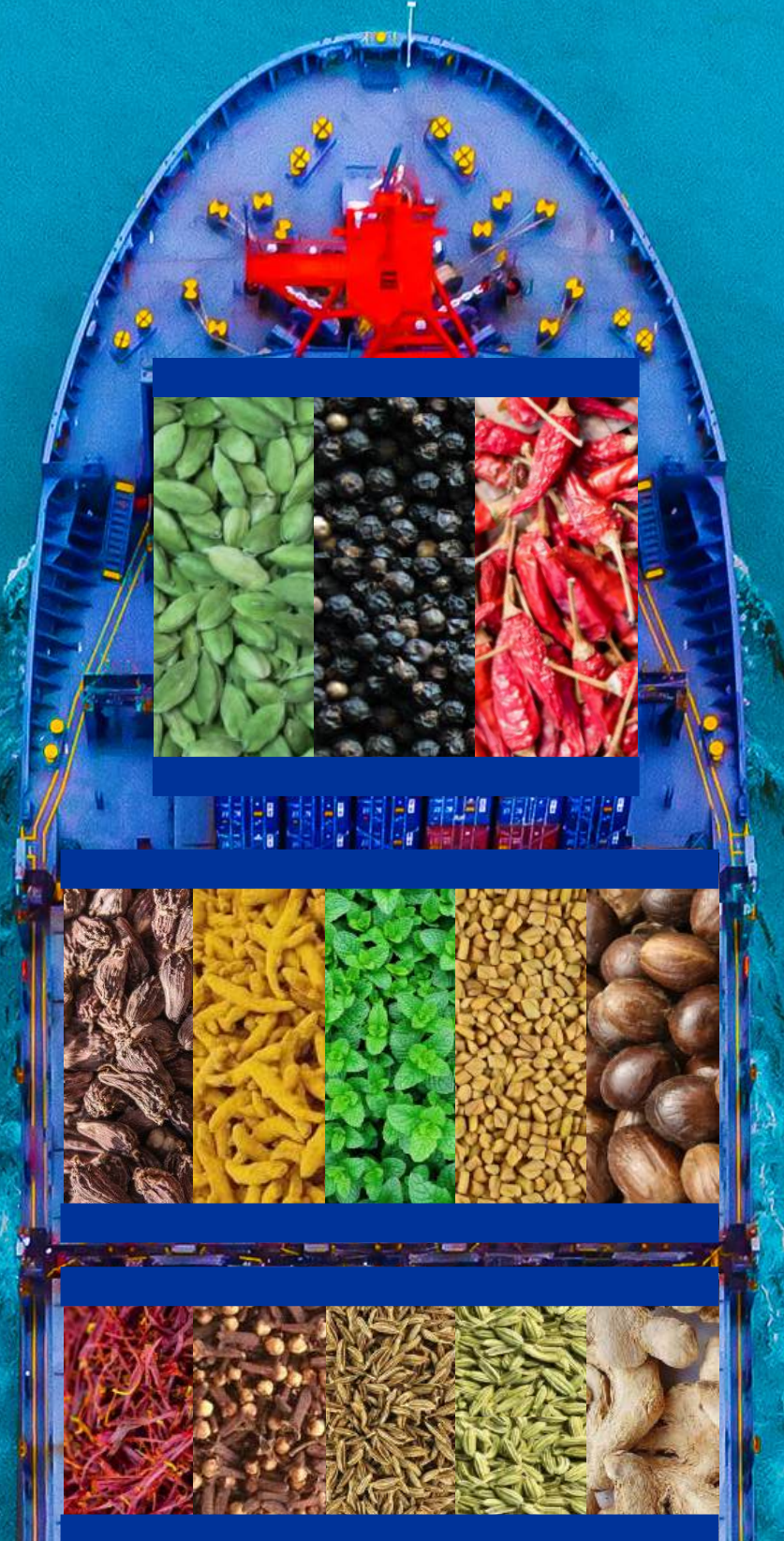


वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2024-25



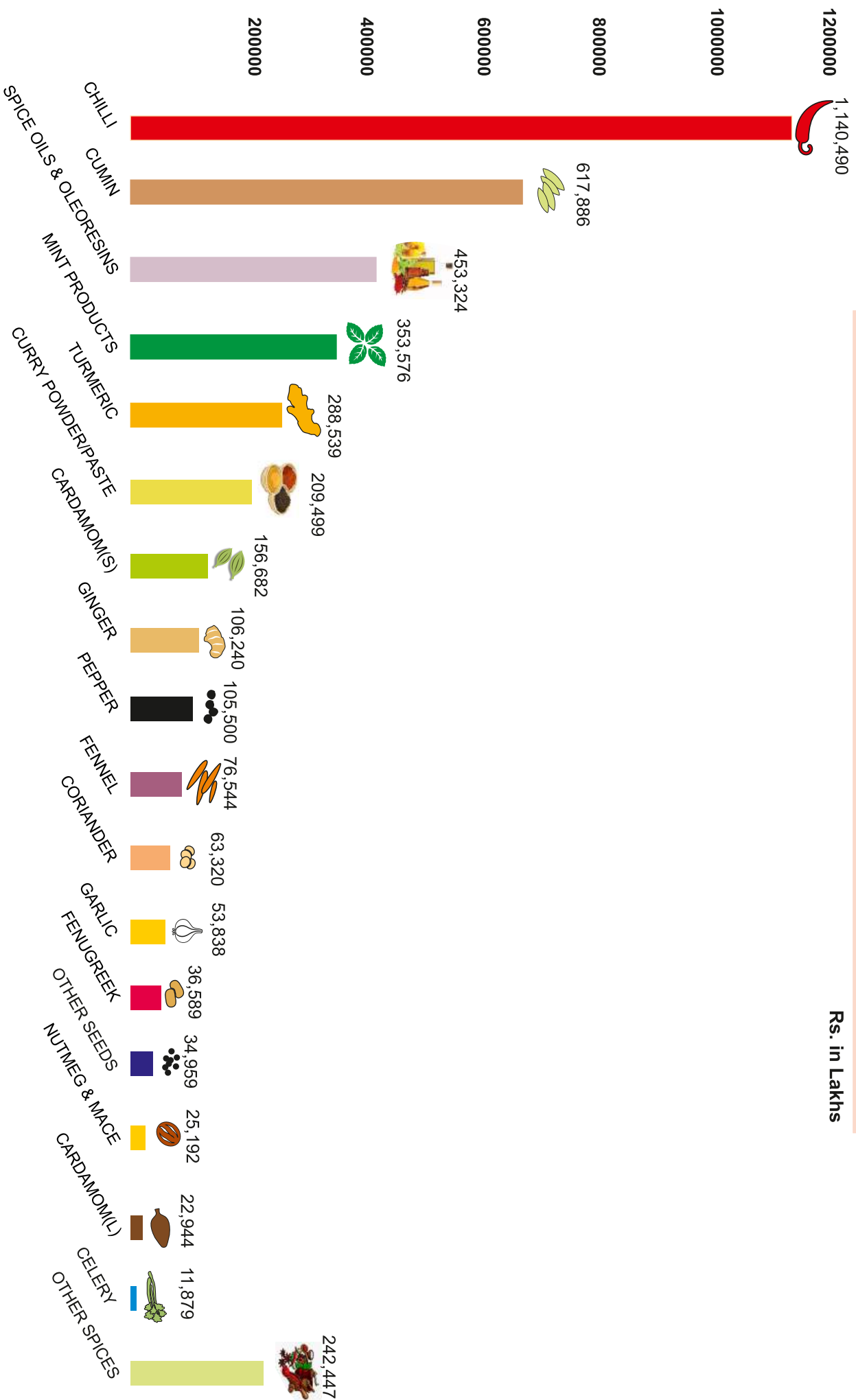
स्पाइसेस बोर्ड
भारत

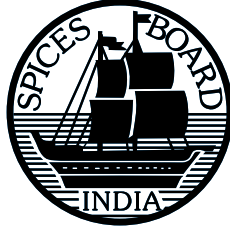
स्पाइसेस बोर्ड भारत
SPICES BOARD INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
भारत सरकार
Government of India
कोचिन / Cochin - 682 025

EXPORT OF SPICES FROM INDIA DURING 2024-25 (VALUE)

Rs. in Lakhs





स्पाइसेस बोर्ड
भारत

वार्षिक रिपोर्ट

2024 - 25



संकलन व सम्पादन:

श्री नितिन जो

उप निदेशक

श्री कनगधिलीपन के.

सहायक निदेशक

श्री बीजू डी. षेणाई

सहायक निदेशक

सुश्री रेशमी ई.जी.

फार्म प्रबंधक

सुश्री अनीनामोल पी.एस.

संपादक

तकनीकी सहायता:

श्री आर. जयचंद्रन

ईडीपी सहायक

कार्यकारी सारांश

1. संघटन एवं प्रकार्य
2. प्रशासन
3. वित्त और लेखा
4. मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन और फसलोत्तर सुधार
5. निर्यात विकास और संवर्धन
6. व्यापार सूचना सेवा
7. प्रचार एवं संवर्धन
8. गुणवत्ता सुधार
9. कोडेक्स सेल एवं हस्तक्षेप
10. निर्यातोन्मुखी अनुसंधान
11. सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग
12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

भविष्य की ओर

परिशिष्ट

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2024-25 में पैरा



कार्यकारी सारांश

स्पाइसेस बोर्ड, भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार हेतु भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन है। बोर्ड भारतीय मसालों की उत्कृष्टता के लिए गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा है ताकि भारतीय मसाला उद्योग को वैश्विक मसाला बाजार के औद्योगिक, खुदरा और खाद्य सेवा क्षेत्रों में स्वच्छ एवं मूल्यवर्धित मसालों और शाकों का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र और प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। बोर्ड ने गुणवत्ता और स्वच्छता को अपनी विकास और प्रचार रणनीतियों का आधार बनाया है।

भारत से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत ने ₹ 39,994.48 करोड़ (4,722.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 17,99,267 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया, जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 14,899.67 करोड़ (2432.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 8,93,920 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था। इस प्रकार, मात्रा में 101 प्रतिशत, रुपये के मूल्य में 168 प्रतिशत और डॉलर के मूल्य में 94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2014-15 से मसालों के निर्यात में मात्रा में सात प्रतिशत, मूल्य (भारतीय रुपये में) में दस प्रतिशत और मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) में सात प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई है।

भारतीय मसाला निर्यात बास्केट में 225 मसाले और मसाला उत्पाद शामिल हैं, जिनका निर्यात रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर 180 से अधिक गंतव्यों को किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, मूल्य की दृष्टि से मसाला निर्यात बास्केट में प्रमुख योगदानकर्ता मिर्च (28%), जीरा (16%), मसाला तेल और तैलीराल (11%), पुदीना उत्पाद (9%), हल्दी (7%), करी पाउडर/पेस्ट (5%), छोटी इलायची (4%), अदरक और काली मिर्च (3%), सौंफ और धनिया (2%) थे, जिनका कुल मिलाकर मसालों से होने वाली कुल निर्यात आय में 90 प्रतिशत

से अधिक योगदान रहा।

वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय मसालों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य चीन (16%), यूएसए (15%), यूईई (9%), बांग्लादेश (8%), मलेशिया (4%), थाईलैंड (3%), यूके (3%), सऊदी अरब (3%), इंडोनेशिया (3%), श्रीलंका (2%), जर्मनी (2%), नीदरलैंड (2%), कनाडा (2%), नेपाल (2%), ऑस्ट्रेलिया (1%), जापान (1%), रूस (1%), सिंगापुर (1%), फ्रांस (1%), मैक्सिको (1%), वियतनाम (1%), मोरोक्को (1%), दक्षिण अफ्रीका (1%) और कोरिया (1%) थे, जो देश से मसालों की कुल निर्यात आय का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं।

वर्ष 2024-25 में, काली मिर्च, इलायची (छोटी और बड़ी), अदरक, हल्दी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, इमली, मसाला तेल और तैलीराल, तथा करी पाउडर और पेस्ट के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि होने की संभावना है। हालाँकि वर्ष 2024-25 में मिर्च के निर्यात में मात्रा की दृष्टि से 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन रुपये के संदर्भ में इसके मूल्य में नौ प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में 11 प्रतिशत की गिरावट आई। पुदीना उत्पादों के मामले में, निर्यात की मात्रा में एक प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, निर्यात मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में रुपये के संदर्भ में तीन प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। धनिया के निर्यात में मात्रा के हिसाब से 44 प्रतिशत, रुपये के हिसाब से 33 प्रतिशत तथा डॉलर के मूल्य के हिसाब से 35 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि जायफल और जावित्री के निर्यात में मात्रा के हिसाब से 8 प्रतिशत, रुपये के हिसाब से 12 प्रतिशत तथा डॉलर के मूल्य के हिसाब से 14 प्रतिशत की गिरावट आई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड द्वारा मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के कुल 4,106 प्रमाण पत्र (सीआरईएस) जारी किए गए थे। इनमें से 3,713 प्रमाण पत्र व्यापारी निर्यातकों को और 393 निर्माता निर्यातकों को जारी किए गए थे। बोर्ड ने 705 इलायची डीलर लाइसेंस जारी किए हैं, जिसमें 688 छोटी



बैठकें आयोजित कर रहा है। साथ ही, मसाला व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए प्रगतिशील हितधारकों को आकर्षित, प्रेरित और सुसज्जित करने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड पूरे भारत के प्रतिभागियों को शामिल करते हुए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित कर रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने 12 क्रेता-विक्रेता बैठकें और चार उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में इलायची (छोटी और बड़ी) के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होने के नाते स्पाइसेस बोर्ड ने स्पाइस्टड (SPICED) योजना के तहत इलायची क्षेत्र की बेहतरी के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, पुनरोपण/नए रोपण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से, तमिलनाडु और केरल राज्यों में 2670 उत्पादकों को लाभान्वित करते हुए 746.67 हेक्टेयर छोटी इलायची के पुनरोपण के लिए ₹ 366.68 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई और कर्नाटक में 364 उत्पादकों को लाभान्वित करते हुए 153.7 हेक्टेयर छोटी इलायची के पुनरोपण के लिए ₹ 61.99 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 3,472 उत्पादकों को लाभान्वित करते हुए 771.18 हेक्टेयर बड़ी इलायची के पुनरोपण/नए रोपण के लिए ₹ 265.36 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, कर्नाटक क्षेत्र में बोर्ड की पाँच विभागीय नर्सरियों द्वारा कुल 74,304 इलायची रोपण सामग्री, 3,84,507 जड़युक्त मिर्च की कलमों, 13,377 मिर्च की केंद्रक रोपण सामग्रियाँ, और 34,132 इलायची की अंतर्भूस्तरियाँ का उत्पादन किया गया। ये रोपण सामग्रियाँ 659 उत्पादकों को वितरित की गईं। प्रमाणित नर्सरी योजना के अंतर्गत, ₹ 141.77 लाख की वित्तीय सहायता से 216.03 छोटी इलायची इकाइयाँ (10,80,500 रोपण सामग्री) और 342.4 बड़ी इलायची इकाइयाँ (17,12,050 रोपण सामग्री) स्थापित की गईं।

‘जल स्रोतों का विकास एवं सूक्ष्म सिंचाई पर ध्यान’ कार्यक्रम के अंतर्गत, छोटी इलायची में 78 जल संग्रहण संरचनाएँ, 53 वर्षा जल संग्रहण संरचनाएँ, 67 सिंचाई पंप सेट और 22 सिप्रंकलर प्रणालियाँ स्थापित की गईं, जिससे 220 किसानों को ₹ 61.56 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। बड़ी इलायची में आठ जल संग्रहण संरचनाएँ, 16 वर्षा जल संचयन संरचनाएँ और 36 सिंचाई पंप सेट स्थापित किए गए, जिससे 60 किसानों को

₹ 15.37 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

छोटी इलायची उत्पादकों को प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाओं, जैसे कम या ज्यादा बारिश, गर्मी (तापमान), सापेक्षिक आर्द्रता आदि, जो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, से बचाने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड छोटी इलायची के लिए मौसम आधारित बीमा कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रीमियम का 75 प्रतिशत स्पाइसेस बोर्ड और 25 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, 670 किसानों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकित किया गया, जिसमें 370 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया और बोर्ड के हिस्से के रूप में ₹ 62.22 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

मसालों की कटाई उपरांत गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के तहत, स्पाइसेस बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान जीआई केसर मेला सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और जीआई केसर के प्रचार के लिए ₹ 1.64 लाख की राशि का उपयोग किया; मसाला क्षेत्र में 42 किसान समूहों को ₹ 236.32 लाख की वित्तीय सहायता के साथ विभिन्न कटाई के बाद मशीनें स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई, जिससे गुणवत्ता अंतर पाट ने वाले समूह (क्यूजीबीजी) घटक के तहत 16,186 किसान लाभान्वित हुए। दूरदराज के क्षेत्रों/उत्तर पूर्वी क्षेत्र/ हाशिए पर पड़े समुदायों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, प्रमुख निर्यात/उत्पादन केंद्र के किसानों के लिए कटाई के बाद की मशीनरी के घटक के तहत, 66 बिजली चालित बीज मसाला श्रेणर, 492 काली मिर्च श्रेणर, 84 हल्दी भाप उबालने वाली इकाइयाँ, 153 मसाला पॉलिशिंग इकाइयाँ (इलायची पॉलिशर और हल्दी पॉलिशर), आठ पुदीना आसवन इकाइयाँ, 153 मसाला क्लीनर/ग्रेडर/सर्पिल ग्रेविटी सेपरेटर, 39 मसाला वॉशिंग मशीन, दस मसाला स्लाइसिंग मशीनें, और 320 मसाला ड्रायर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई, जिससे 1325 किसानों को ₹ 617.07 लाख की वित्तीय सहायता मिली।

निर्यात योग्य अधिशेष उत्पन्न करने हेतु चिन्हित क्लस्टरों में समूहों या एफपीओ द्वारा प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन इकाइयाँ स्थापित करने हेतु एफपीओ को सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए दो एफपीओ को ₹ 15.73 लाख की वित्तीय सहायता

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

प्रदान की गई, जिससे 405 उत्पाद

वैश्विक प्रमाणन ₹ 34.48 लाख की वित्तीय सहायता

से 29 उत्पादों को प्रमाणित किया

गए, जिससे 12 लाख की

₹ 12 लाख की

₹ 4 लाख की

किया गया। इनमें 40

सोनी प्रमाणन प्रणाली के लिए ₹ 8.00 लाख।

वर्ष 2024-25 के दौरान तमिल

नाचल प्रमाणन प्रणाली

के लिए

(छोटे और मध्यम) बु

₹ 4 लाख की

प्रस्तावित किया गया।

थ।

विज्ञान केंद्र, आईसाआरआई

से क्षमता निर्माण का

दौरान, पाँच राज्यों

में ऐसे छह

उत्पादकों

द्वारा

पाइसेस के लिए राज्य के

अधिकारियों के साथ सरकार के सदस्यों आदि

के लिए निर्माण प्रमाणन प्रणाली के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

(एचडीपी) आयोजित किए गए थे। उन्हें कटाई-पूर्व और

कटाई-पश्चात तैयारी के लिए तकनीकों के वैज्ञानिक तरीकों और

मुख्य समस्याओं के बारे में

शिक्षण किया गया। 2024-25 के दौरान 215 प्रशिक्षण

कार्यक्रमों में 771 कर्मियों को प्रशिक्षित किया

गया। इन कार्यक्रमों में ₹ 2 लाख खर्च हुए।

₹ 38 लाख के उपलक्ष्य में 25 फरवरी 2025

प्रमाणन चलाया गया।



मसालों में स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) समस्याओं के समाधान के लिए, स्पाइसेस बोर्ड ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत मानक और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ) को 'भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और क्षमता निर्माण और अभिनव हस्तक्षेपों के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार' शीर्षक से एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो विकासशील देशों को उनके मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच हासिल करने या बनाए रखने की क्षमता के साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों को लागू करने की क्षमता के निर्माण में सहायता करता है। परियोजना को एसटीडीएफ ने 2018 में मंजूरी दी थी। एफएओ इंडिया परियोजना का कार्यान्वयन भागीदार और बजट धारक रहा और परियोजना के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार रहा। स्पाइसेस बोर्ड परियोजना का स्थानीय भागीदार रहा और उसे परियोजना के तहत सभी स्थानीय गतिविधियों के कार्यान्वयन और उनके समन्वय को सुनिश्चित करता रहा।

त्रिपुरा में काली मिर्च के उत्पादन एवं कटाई-पश्चात प्रबंधन पर एकीकृत परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान काली मिर्च किसानों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का आयोजन स्पाइसेस बोर्ड द्वारा त्रिपुरा सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 492 किसानों को ₹ 4.00 लाख की लागत से प्रशिक्षित किया गया।

'बाजार विस्तार के लिए क्षमता संवर्धन, 'व्यापार संवर्धन' और 'तकनीकी हस्तक्षेप' घटकों के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य निर्यातकों को बुनियादी ढाँचे के विकास और भारतीय मसालों व मसाला उत्पादों को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करना है, ताकि प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित मसालों का निर्यात बढ़ाया जा सके, जो आयातक देशों के उभरते खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने और प्रक्रिया उन्नयन को प्रोत्साहित करने के अलावा, बोर्ड ने मसालों की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उपर्युक्त घटकों के अंतर्गत प्रमुख ज़ोर वाले क्षेत्र हैं - व्यापार संवर्धन, उत्पाद विकास और अनुसंधान, बुनियादी

ढाँचे का विकास, विदेशों में भारतीय मसाला ब्रांडों का प्रचार, प्रमुख मसाला उत्पादक/विपणन केंद्रों में सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थापना, मसाला पार्क जैविक मसालों/जीआई मसालों का प्रचार, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना आदि।

'मसालों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी और अवसंरचनात्मक हस्तक्षेप (टीआईआईपीएस)' कार्यक्रम के तहत, जिसका उद्देश्य मसालों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए सुविधाएं स्थापित करने, मसाला प्रसंस्करण में उच्च तकनीक वाले बुनियादी ढाँचे को अपनाने, प्रक्रिया उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप करने आदि के लिए निर्यातकों को समर्थन देना है। वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 100.00 लाख की सहायता प्रदान की गई।

इन-हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 1.60 लाख की सहायता प्रदान की गई। किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने और व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड ने प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में आठ फसल-विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं। सभी पार्कों में मसालों और मसाला उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और भंडारण के लिए अच्छी तरह से स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं और सभी पार्कों में इकाइयां वर्तमान में बोर्ड द्वारा पहचाने गए ऑपरेटरों के माध्यम से कार्य कर रही हैं। 31 मार्च 2025 तक, मसाला पार्क, जोधपुर में 21 निर्यातकों को 25 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 13 इकाइयां कार्य कर रही हैं; मसाला पार्क, गुना में 21 निर्यातकों को 37 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से तीन इकाइयां कार्य कर रही हैं। स्पाइसेस पार्क, गुंटूर में 26 निर्यातकों को 51 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से सात इकाइयां कार्यरत हैं; स्पाइसेस पार्क, शिवगंगा में 12 निर्यातकों को 17 भूखंड और स्पाइसेस पार्क, रायबरेली में 3 निर्यातकों को सात भूखंड आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, स्पाइसेस पार्क, जोधपुर में एक इकाई ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

वर्ष 2024-2025 के दौरान, मसाला पार्कों में निर्यातकों द्वारा स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों एवं इकाइयों में ₹ 89,951.70 लाख मूल्य के 68774.08 मीट्रिक टन मसालों का प्रसंस्करण किया गया है, जिनमें से ₹ 35,326 लाख



द्वारा 12 नवंबर 2024 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित अपनी 29 वीं बैठक के दौरान जारी किया गया।

स्पाइसेस बोर्ड ने 11 सितंबर 2024 को आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में आयोजित 'स्पाइस अप योर बिज़नेस: स्टेकहोल्डर्स कॉन्क्लेव एंड बायर-सेलर मीट' के दौरान ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसा प्रणाली वाला एक एप्लिकेशन 'कार्डूसऐप' लॉन्च किया। ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसा प्रणाली वाला यह ऐप, उडुम्बनचोला और इडुक्की तालुकों के 19 गाँवों से एकत्र किए गए नमूनों से मृदा उर्वरता मानचित्र सहित महत्वपूर्ण मृदा परीक्षण परिणाम प्रदान करता है' ये क्षेत्र इलायची की खेती की संभावनाओं के लिए जाने जाते हैं। यह परियोजना रबड़ बोर्ड और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से शुरू की गई थी। इस दौरान एक समर्पित किसान सुविधा केंद्र, आईसीआरआई-किसान सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में 11 सितंबर 2024 को 'अपने व्यवसाय को और बेहतर बनाएँ: हितधारकों का सम्मेलन और क्रेता-विक्रेता सम्मेलन' आयोजित किया गया। आईसीआरआई-किसान सेवा केंद्र का उद्देश्य मसाला किसानों का समर्थन करना और कृषि क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों का समाधान प्रदान करना है। मसाला उत्पादकों के लाभ के लिए आईसीआरआई-किसान सेवा केंद्र के माध्यम से आईसीआर-आईआईएसआर, कोझिकोड से विभिन्न जैव नियंत्रण कारकों और रोपण सामग्री की आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए स्पाइसेस बोर्ड और आईसीआर-आईआईएसआर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के इडुक्की जिले के कार्डमम हिल रिजर्व के 935 मृदा नमूनों से लगभग 7332 मृदा उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया और उर्वरकों के उचित प्रयोग के लिए सिफारिशें दी गईं। इसके अतिरिक्त, सिक्किम के 44 मृदा नमूनों से 528 मृदा उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया और मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए रिपोर्ट प्रदान की गईं। 226 किसानों से प्राप्त कुल 377 मृदा नमूनों का उपलब्ध नाइट्रोजन के लिए विश्लेषण किया गया।

मसाला किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, केरल राज्य बागवानी मिशन की सहायता से, आईसीआरआई ने सिंचाई के लिए स्वचालन के साथ-साथ काली मिर्च के गुणन

के लिए सापेक्ष आर्द्रता नियंत्रण और इलायची चूसने वाली नर्सरी के साथ बारह उच्च तकनीक वाले पॉलीहाउस स्थापित किए।

वर्ष 2024-25 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड की 95 वीं बोर्ड बैठक 29 जून 2024 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। स्वीकृत 31 सदस्यों में से कुल 16 सदस्यों की नियुक्ति की गई। श्री अमरदीप सिंह भाटिया, आईएएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, 12 जुलाई 2023 से 10 अक्टूबर 2024 तक बोर्ड के अध्यक्ष रहे। श्री एल . सत्य श्रीनिवास, आईआरएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, को 11 अक्टूबर 2024 को छह महीने की अवधि के लिए बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

डॉ. के.जी. जगदीशा आईएएस ने 18 मार्च 2024 से स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का पदभार ग्रहण किया और 23 अक्टूबर 2024 तक इस पद पर बने रहे। सुश्री पी. हेमलता आईएएस ने 24 अक्टूबर 2024 को स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का पदभार ग्रहण किया और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस पद पर बने रहे।

वार्षिक कार्यक्रम के साथ-साथ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग के संबंध में जारी आदेशों के अनुरूप, राजभाषा अनुभाग ने वर्ष 2024-25 के दौरान राजभाषा नीति कार्यान्वयन को और अधिक फलदायी और प्रभावी बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे।

बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को प्रभावी ढंग से लागू किया और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का पालन किया। बोर्ड ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) द्वारा सूचना के प्रसार में समन्वय हेतु पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी को समन्वयकारी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया। बोर्ड ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, प्रकट की जाने वाली प्रत्येक आवश्यक जानकारी को ऐसे रूप और तरीके से प्रकट किया, जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ हो [आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1)]। 2024-25 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कुल 104 आरटीआई आवेदन (भौतिक और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से) और 13 अपीलें प्राप्त हुईं और सभी मामलों में निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान की गई। इस अवधि के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की तीन सुनवाईयाँ हुईं।



वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

01

एक

स्पाइसेस ब

द्वारा अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया है (1987)।
स्पाइसेस ब (1987) अधिनियम का प्रावधान है।

भारतीय सरकार ने स्पाइसेस ब (1987) से अस्तित्व में

(इ) बोर्ड का

इस अधिनियम द्वारा 1986
निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा लागू

(क) ब

(i) इस अधिनियम का विधान विनियमन करें;

(ii) मसालों के उत्पादन के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करें;

(iii) मसालों के उत्पादन के संवर्धन के लिए कार्यक्रम व प्रावधानों को लागू करें;

(iv) मसालों के उत्पादन, गुणवत्ता, श्रेणीकरण के क्षेत्र में सुधार के लिए अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहित करें एवं उसका प्रोत्साहन करें;

(v) निम्नलिखित मसालों की कीमतों के स्थिरीकरण



ख) साथ ही, बोर्ड:-

- (i) इलायची कृषकों के बीच सहकारिता प्रयासों को बढ़ावा दें;
- (ii) इलायची कृषकों के लिए लाभकारी पारिश्रमिक सुनिश्चित करें;
- (iii) इलायची की खेती और प्रसंस्करण के उन्नत तकनीकों के लिए इलायची पुनरोपण तथा इलायची खेती इलाकों के विस्तारण के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करें;
- (iv) इलायची के विक्रय और इलायची की कीमतों के स्थिरीकरण का विनियमन करें;
- (v) इलायची की जाँच तथा उसके श्रेणीमानदण्ड नियत करने में प्रशिक्षण की व्यवस्था करें;
- (vi) इलायची के उपभोग में वृद्धि और उस प्रयोजन के लिए प्रचार करें;
- (vii) इलायची के दलालों (जिनके अंतर्गत नीलामकर्त्ता

हैं) एवं इलायची के कारोबार में लगे व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत और अनुज्ञप्त करें;

- (viii) इलायची के विपणन में वृद्धि करें;
- (ix) कृषकों, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों से जो विहित किए गए जाए, इलायची उद्योग से संबंधित किसी विषय पर आँकड़ों का संग्रह करें; ऐसे संगृहीत आँकड़ों या उनके भागों या उनसे उद्धरणों का प्रकाशन भी करें;
- (x) कर्मचारियों के लिए अधिक अच्छी कार्यकारी दशाओं और सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित करें और
- (xi) वैज्ञानिक, तकनीक और आर्थिक अनुसंधान आरंभ करें, उसमें प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करें।

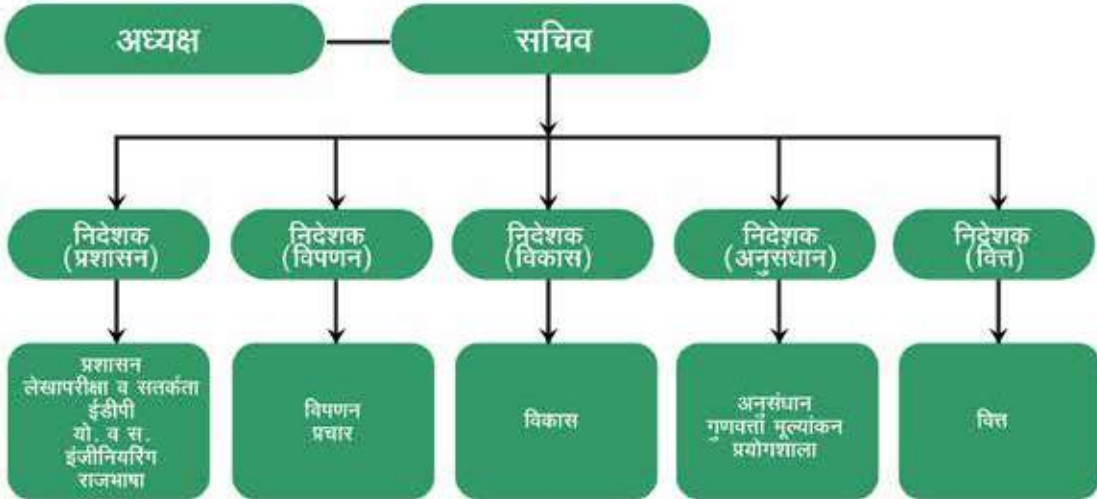
ग) बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले मसाले

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित 52 मसाले आते हैं :-

| | | | | | |
|----|-----------------------|----|-----------------------|----|---------------|
| 1 | इलायची | 19 | कोकम | 37 | जूनिपर बेरी |
| 2 | कालीमिर्च | 20 | पुदीना | 38 | बे-पत्ता |
| 3 | मिर्च | 21 | सरसों | 39 | लूवेज |
| 4 | अदरक | 22 | अजमोद | 40 | मजोरम |
| 5 | हल्दी | 23 | अनारदाना | 41 | जायफल |
| 6 | धनिया | 24 | केसर | 42 | जावित्री(मेस) |
| 7 | जीरा | 25 | वैनिला | 43 | तुलसी |
| 8 | बडी सौंफ | 26 | तेजपात | 44 | खसखस |
| 9 | मेथी | 27 | पीपला | 45 | ऑलस्पाइस |
| 10 | अजवाइन | 28 | स्टार एनीज़ | 46 | रोज़मेरी |
| 11 | सौंफ | 29 | घोंड बच (स्वीट फ्लैग) | 47 | सेज |
| 12 | अजोवन (मसाले का पौधा) | 30 | महा गलेजा | 48 | सेवरी |
| 13 | काला जीरा | 31 | होर्स-रैडिश | 49 | थाइम |
| 14 | सोआ | 32 | केपर | 50 | ओरगेनो |
| 15 | दालचीनी | 33 | लौंग | 51 | टेरागन |
| 16 | अमलतास (कैसिया) | 34 | हींग | 52 | इमली |
| 17 | लहसुन | 35 | केंबोज | | |
| 18 | करी पत्ता | 36 | हिस्सप | | |

(करी पाउडर, मसाले तेल, तैलीराल एवं अन्य मिश्रण सहित किसी भी रूप में हो, जहाँ मसाला घटक प्रमुख है)

स्पाइसेस बोर्ड का ऑर्गेनोग्राम



स्वीकृत स्टाफ की संख्या - 379
वर्तमान स्थिति - 211 (जैसे कि 31.03.2025 को है)



प्रशासन

अ) प्रशासन

श्री अमरदीप सिंह भाटिया आईएएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 12 जुलाई 2023 से 10 अक्टूबर 2024 तक स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। श्री एल सत्य श्रीनिवास आईआरएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार को छह महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक 11 अक्टूबर 2024 को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉ के जी जगदीश आईएएस ने 18 मार्च 2024 से स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का पदभार ग्रहण किया और 23 अक्टूबर 2024 तक बने रहे। सुश्री पी हेमलता आइएएस ने 24 अक्टूबर 2024 से स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का पदभार ग्रहण किया और रिपोर्ट धीन अवधि के दौरान बने रहे। डॉ रेमा श्री ए. बी. ने निदेशक (अनुसंधान) के रूप में कार्य जारी रखा और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाला। श्री जिजेश टी दास, उप निदेशक (ईडीपी), श्री बी. एन. झा, उप निदेशक (विपणन) और श्री धर्मेन्द्र दास उप निदेशक (विकास) ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान क्रमशः निदेशक (प्रशासन), निदेशक (विपणन) और निदेशक (विकास) का कार्यभार संभाला।

स्पाइसेस बोर्ड ने पहले ही पुनर्गठन प्रस्ताव में स्वीकृत लक्षित कर्मचारियों की संख्या हासिल कर ली है। जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, 379 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले, स्पाइसेस बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 211 है जिसमें 64 वर्ग 'क', 72 वर्ग 'ख' और 75 वर्ग 'ग' कर्मचारी शामिल हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने दो कर्मचारियों को पदोन्नति दी है और पात्र 14 कर्मचारी को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपी) के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया है। बोर्ड ने निर्यात संवर्धन और विकास गतिविधियों के समर्थन के लिए तीन विपणन कार्यपालकों और आठ विकास

कार्यपालकों को नियुक्त किया है।

बोर्ड ने स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 57 से अधिक बेरोजगार युवाओं को गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में विश्लेषणात्मक सेवाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और अनुसंधान स्टेशनों में कृषि विस्तार सेवा और लेखा तथा पुस्तकालय अनुभाग में शासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त किया है।

क) नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अ.जा/अ.

ज.जा/अ.पि.व. के लिए आरक्षण

बोर्ड अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए पद-आधारित आरक्षण रोस्टर का उचित रूप से कार्यान्वयन करता है। सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। जैसे कि 31 मार्च, 2025 को है, अ.जा/अ.ज.जा और अ.पि.व. की श्रेणियों में 128 पदाधिकारी(अ.पि.व.-76, अ.जा-31 और अ.ज. जा-21) थे।

स्पाइसेस बोर्ड के भर्ती विनियम की स्वीकृति लम्बित होने के कारण वाणिज्य विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुसार, रिपोर्ट धीन अवधि के दौरान कोई नियुक्ति नहीं हुई है। मंत्रालय ने पत्र संख्या 5/6/2018-प्लांट-डी दिनांक 04.02.2020 के माध्यम से बोर्ड को निदेश दिया है कि जब तक मंत्रालय द्वारा भर्ती नियम को मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक वह कोई भर्ती न करें।

ख) महिला कल्याण

जैसे कि 31 मार्च 2025 को है, बोर्ड की 'क', 'ख' व 'ग' श्रेणियों की महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या 59 है। महिला पदाधिकारियों की शिकायतों पर समय पर और उचित तौर पर ध्यान जाता है। बोर्ड की वर्ग 'क' स्तर की एक महिला अधिकारी



| | | |
|----|---------------------|----------|
| 4 | कट्टुप्पना | केरल |
| 5 | कुमली | केरल |
| 6 | नेदुंकण्डम | केरल |
| 7 | पांपाडुम्पारा | केरल |
| 8 | पीरमेड | केरल |
| 9 | पुट्टुडी | केरल |
| 10 | राजाक्काड | केरल |
| 11 | राजकुमारी | केरल |
| 12 | शांतनपारा | केरल |
| 13 | उडुन्पनचोला | केरल |
| 14 | बोडिनायकन्नूर | तमिलनाडु |
| 15 | इरोड | तमिलनाडु |
| 16 | बल्लगुंडु | तमिलनाडु |
| 17 | आइगूर (फार्म) | कर्नाटक |
| 18 | बेलगोला (फार्म) | कर्नाटक |
| 19 | बेलिगेरी (फार्म) | कर्नाटक |
| 20 | बेट्टुडामने (फार्म) | कर्नाटक |
| 21 | सकलेशपुर | कर्नाटक |
| 22 | हावेरी | कर्नाटक |
| 23 | कोप्पा | कर्नाटक |
| 24 | मडिक्केरी | कर्नाटक |
| 25 | मुडिगेरे | कर्नाटक |
| 26 | शिवमोगा | कर्नाटक |
| 27 | सिरसी | कर्नाटक |
| 28 | सोमवारपेट | कर्नाटक |
| 29 | वनगूर | कर्नाटक |
| 30 | येसलूर (फार्म) | कर्नाटक |

| | | |
|----|-------------|--------------|
| 6 | दीमापुर | नागालैंड |
| 7 | कोहिमा | नागालैंड |
| 8 | गान्तोक | सिक्किम |
| 9 | गेयसिंग | सिक्किम |
| 10 | जोरथांग | सिक्किम |
| 11 | मंगन | सिक्किम |
| 12 | कलिम्पोंग | पश्चिम बंगाल |
| 13 | सुखियापोखरी | पश्चिम बंगाल |
| 14 | चुराचंदपुर | मणिपुर |

(iii) अनुसंधान स्टेशनें

| क्रम सं. | स्थान | राज्य/संघ शासित प्रदेश |
|----------|-----------------|------------------------|
| 1 | मैलाडुंपारा | केरल |
| 2 | डोनिगल-सकलेशपुर | कर्नाटक |
| 3 | ताडियनकुडिशि | तमिलनाडु |
| 4 | तादोंग | सिक्किम |

(iv) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यू ई एल)

| क्रम सं. | स्थान | राज्य/संघ शासित प्रदेश |
|----------|-----------|------------------------|
| 1 | गुंटूर | आंध्र प्रदेश |
| 2 | काण्डला | गुजरात |
| 3 | कोच्ची | केरल |
| 4 | मुम्बई | महाराष्ट्र |
| 5 | नरेला | नई दिल्ली |
| 6 | चेन्नई | तमिलनाडु |
| 7 | तूतिकोरिन | तमिलनाडु |
| 8 | कोलकाता | पश्चिम बंगाल |

(v) मसाला पार्क

| क्रम सं. | स्थान | राज्य/संघ शासित प्रदेश |
|----------|--------------------|------------------------|
| 1 | गुंटूर | आंध्र प्रदेश |
| 2 | पुट्टुडी | केरल |
| 3 | छिंदवाडा | मध्य प्रदेश |
| 4 | गुना | मध्य प्रदेश |
| 5 | जोधपुर | राजस्थान |
| 6 | रामगंज मंडी (कोटा) | राजस्थान |
| 7 | शिवगंगा | तमिलनाडु |
| 8 | राय बरेली | उत्तर प्रदेश |

| बड़ी इलायची का अनुसंधान व विकास | | |
|---------------------------------|---------|------------------------|
| क्रम सं. | स्थान | राज्य/संघ शासित प्रदेश |
| 1 | इटानगर | अरुणाचल प्रदेश |
| 2 | नमसाई | अरुणाचल प्रदेश |
| 3 | पासीघाट | अरुणाचल प्रदेश |
| 4 | रोइंग | अरुणाचल प्रदेश |
| 5 | ज़िरो | अरुणाचल प्रदेश |

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

च) वर्ष 2024-25 के दौरान

19 अक्टूबर 2024 से 17 सितंबर 2024 तक अगले

i. ... की अधिप्राप्ति

उत्पादन के स्पाइसेस बोर्ड

सुरक्षा के लिए (सक) ...

दिये सुझाव

सभी आ

कोच

अधीन वा ...

मी

कम्प्यूटर प्रिंटर, ...

और

... खरी

...

...

...

... का कार्यान्वयन

अनुर

भाग के रूप में

काच्ची ... सेस ब ... और देश

... स्पाइसेस

भारत 82 ... जिन ... सर्वर्धन कार्यालय,

... स्वीरों

विकास के ... गुण ... ल्यांकन प्रयोगशालाएं

(यूईए), ... धान स्टेशन और आठ स्पाइस पार्क

शामिल ... किया गया।

... का मनाया जाना :

... द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के

... 2024-25 के दौरान ऐसे निम्नलिखित

...



कार्यन्वयन हेतु उत्तरदायी नॉडल पॉइंट है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और आदेशों के अनुरूप, राजभाषा अनुभाग, सचिव और बोर्ड की राजभाषा कार्यन्वयन समिति की सहमति और अनुमोदन से वर्ष 2024-25 के दौरान भी राजभाषा नीति के कार्यन्वयन को अधिक कारगर और प्रभावी बनाने में राजभाषा अनुभाग प्रयासरत रहा।

प्रमुख कार्यकलाप और उपलब्धियां:

(i) अनुवाद

निम्नलिखित का अनुवाद कार्य (अंग्रेजी से हिन्दी और उल्टे:) किया गया:

- ❖ राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज जैसे कि सामान्य आदेश (परिपत्र), निविदा दस्तावेज, विज्ञापन, प्रेस विज्ञापित, अधिसूचना, वीआईपी संदर्भ आदि
- ❖ वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट व लेखापरीक्षा रिपोर्ट और संसद के समक्ष प्रस्तुत बोर्ड की अन्य प्रशासनिक रिपोर्टें
- ❖ हिन्दी में प्राप्त पत्र और उनके हिन्दी में उत्तर
- ❖ सेवारत कार्मिकों के लिए विजिटिंग कार्ड, रबड़ मुहर और बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को स्मृति-चिह्न के लिए सामग्री
- ❖ बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी समारोहों के लिए सामग्रियाँ, बैनर, बैकड्रॉप, निमंत्रण-कार्ड, कार्यक्रम शीट आदि

(ii) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित करने के अनुरूप चार बैठकें क्रमशः 27 जून, 2024 (अप्रैल - जून, 2024), 30 सितंबर, 2024 (जुलाई - सितंबर, 2024), 31 दिसंबर, 2024 (अक्तूबर - दिसंबर, 2024) और 26 मार्च, 2025 (जनवरी - मार्च, 2025) को आयोजित की गईं।

ख) हिन्दी कार्यशाला

बोर्ड के स्टाफ सदस्यों के लिए प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से चार हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं और प्रतिभागियों को

कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें राजभाषा नीति के साथ-साथ चेक-प्वाइंट के प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ राजभाषा नीति को लागू करने के लिए बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराया गया।

ग) हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लिए चंदा

बोर्ड ने, हिन्दी अखबार 'डेली हिन्दी मिलाप' और सरिता व वनिता नामक हिन्दी पत्रिकाओं के लिए चंदा देना जारी रखा।

घ) राजभाषा निरीक्षण

श्री परमानंद उप निदेशक (रा.भा), वाणिज्य विभाग और उनकी टीम ने 14 नवंबर 2024 को स्पाइसेस बोर्ड, मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया और राजभाषा निरीक्षण किया। निरीक्षण दल ने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में बोर्ड द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। निरीक्षण/बैठक के दौरान समिति ने राजभाषा नीति के बेहतर क्रियान्वयन हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये। अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई की जा रही है।

ङ) हिन्दी दिवस/पखवाड़ा समारोह 2024

बोर्ड में 14 सितंबर, 2024 को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया। बोर्ड की ओर से, सहायक निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय कोच्ची ने 14-15 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। उसी दिन को बोर्ड भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 14 से 29 सितंबर, 2024 के दौरान आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह में पूरे भारत के अधिकारियों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा समारोह 2024 के संबंध में स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

च) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड को कार्यालय में राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कोच्ची टोलिक द्वारा स्थापित रोलिंग ट्रॉफी (तृतीय स्थान) से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 23 अक्तूबर, 2024 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी), कोच्ची की आवधिक

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

बैठक के दौरान प्रभारी निदेशक (प्रशासन) ने निम्नलिखित संदर्भ सूची का प्रदान किया।

इस बैठक के निदेशक (अनुसंधान और विकास प्रभारी) को आयोजित करने के लिए प्रस्तावित किया गया।

वैकल्पिक प्राप्ति

प्रति वर्ष के लिए प्रदान किया गया।

सिद्धिप

पीयूएसएटी) के माध्यम से प्रदान किया गया।

अलावा जैविक कृषि, जलवायु

पुस्तकें, संदर्भ सूची का प्रदान किया गया।

प्रदान किया गया।

करंट एवेयरनेस

समाचार सेवा' जैसी नियमित

अलावा जैविक कृषि, जलवायु

मसाले, वृक्ष मसाले, तेल व



वित्त और लेखा

बोर्ड की योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता द्वारा की जाती है। प्रशासन के खर्च मुख्यतः सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान और बोर्ड के विविध कार्यकलापों से अर्जित आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईबीआर) के जरिए किए जाते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड के लिए अनुमोदित बजट ₹13,000.00 लाख है। ₹13,000.00 लाख की अनुदान सहायता का विस्तृत आवंटन निम्नानुसार था:

| क्रमांक | सहायता अनुदान का आबंटन | ₹ लाख रुपयों में |
|---------|---|------------------|
| 1 | अनुदान सहायता सामान्य, पूंजीगत व्यय, वेतन, अन्य व्यय और स्वच्छ भारत | 7153.00 |
| 2 | इमदाद/वित्तीय सहायता के लिए सहायता अनुदान | 4200.00 |
| 3 | पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान | 849.00 |
| 4 | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए सहायता अनुदान | 249.00 |
| 5 | जनजातीय उपयोजना के लिए सहायता अनुदान | 549.00 |
| | कुल | 5847.00 |

बोर्ड ने 2024-25 में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता परीक्षण सेवाओं के लिए विश्लेषणात्मक शुल्क, नर्सरी से पौध और अनुसंधान फार्मों के कृषि उत्पादों, सदस्यता और विज्ञापन शुल्क, निर्यातकों के पंजीकरण शुल्क, अग्रिम पर ब्याज, अल्पकालिक जमा पर ब्याज आदि से 3751.59 लाख रुपये का राजस्व (आईईबीआर) उत्पन्न किया।

स्पाइसेस बोर्ड को मसालों (52 अनुसूचित मसालों और उसके उत्पादों) के निर्यात संवर्धन और इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन, अनुसंधान, विकास और घरेलू विपणन और निर्यात के

लिए मसालों के गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रमाणन का अधिदेश प्राप्त है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र योजना - निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता (स्पाइसड) के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को लागू कर रहा है। इस योजना में इलायची की उत्पादकता में सुधार, मसालों की कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, बाजार व्यय के लिए क्षमता बढ़ाना, व्यापार संवर्धन और तकनीकी हस्तक्षेप, छोटी और बड़ी इलायची पर अनुसंधान, क्षमता निर्माण और कौशल विकास जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड का कुल व्यय 13,343.85 लाख रुपये था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

| लेखा शीर्ष | व्यय (₹ लाख रुपयों में) |
|--|-------------------------|
| उत्पादकता में सुधार-इलायची | 1031.49 |
| मसालों की कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन | 1157.20 |
| गुणवत्ता सुधार | 1044.65 |
| बाजार विस्तार के लिए क्षमताओं में वृद्धि | 1021.65 |
| व्यापार संवर्धन | 1302.48 |
| तकनीकी हस्तक्षेप | 44.68 |
| छोटी और बड़ी इलायची पर शोध | 296.25 |
| क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास | 89.16 |
| स्थापना | 7356.29 |
| कुल | 13343.85 |

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

बोर्ड अन्य सरकारी विभागों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदानों से कुछ कार्य चालू रखे गए हैं। वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्त अनुदानों एवं व्यय का विवरण निम्न है।

| कार्यक्रम | प्राप्त अनुदान (लाख रूपयों में) | व्यय (लाख रूपयों में) (*) |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| क्षेत्र व्यापी आईपीएम काली मिर्च | - | 2.00 |
| आई सी ए आर - ए आई सी आर पी एस | 21.31 | 33.25 |
| बेयर परियोजना | - | 3.03 |
| फ्लूपाईरिमिन का मूल्यांकन | - | 4.33 |
| डब्ल्यूटीओ - एसटीडीएफ़ | - | 16.89 |
| डीयूएस जांच केंद्र | 0.75 | 0.15 |
| पॉलीसल्फेट का मूल्यांकन | 6.00 | 5.09 |
| स्पिनेटोरम का मूल्यांकन | - | 11.71 |

| | | |
|---------------------------|--------------|---------------|
| नैनो उर्वरक का मूल्यांकन | 2.40 | 1.70 |
| एस एच एं है-टेक पौधशाला | - | 71.41 |
| सिंजेंटा कवकनाशी | - | 2.64 |
| सिंजेंटा कीटनाशी | - | 1.21 |
| महिला वैज्ञानिक योजना | - | 0.03 |
| एएसआईडीई-टीआईडीएस-सिक्कम | - | 98.47 |
| जिंजर प्रोजेक्ट बस्तर | - | 0.88 |
| म्यांमार बड़ी इलायची | - | 2.62 |
| आर के वी वाई आंध्र प्रदेश | - | 5.93 |
| एं आई डी एच | - | 28.30 |
| नबार्ड सिक्कम | - | 0.94 |
| कुल | 30.46 | 290.58 |

वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय वर्ष में लाया गया अनुदान शामिल है।

2024-25 के



मसालों का निर्यातान्मुख उत्पादन और फसलोत्तर सुधार

स्पाइसेस बोर्ड उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के मामले में इलायची (छोटी और बड़ी) के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड निर्यात के लिए गुणवत्ता पूर्ण मसालों के उत्पादन के लिए फसलोत्तर सुधार कार्यक्रम भी लागू कर रहा है। इसके अधिदेश के अनुरूप, स्पाइसेस बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र की योजना “निर्यात विकास हेतु प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता(एसपीआईसीईडी)” का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें विभिन्न विकास कार्यक्रम और फसलोत्तर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शामिल है, अर्थात् घटक-I) इलायची (छोटी और बड़ी) की उत्पादकता में सुधार और घटक-II) मसालों का फसलोत्तर गुणवत्ता उन्नयन।

विकास कार्यक्रमों को बोर्ड के विस्तार नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें उसके क्षेत्रीय कार्यालय, मंडल कार्यालय और क्षेत्र कार्यालय शामिल हैं। बोर्ड मसाला उत्पादकों की रोपाई के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक के प्रमुख इलायची उत्पादक क्षेत्रों में पांच विभागीय नर्सरी का रखरखाव कर रहा है।

अ) इलायची की उत्पादकता में सुधार (छोटी और बड़ी)

छोटी और बड़ी इलायची के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यान्वित प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है:

क) इलायची (छोटी) की उत्पादकता में सुधार

छोटी इलायची की खेती मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में की जाती है। छोटी इलायची के अधिकांश जोतें छोटे और सीमांत हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान छोटी इलायची की खेती का कुल क्षेत्रफल 70,411 हेक्टेयर (हे) और अनुमानित उत्पादन 20696 मीट्रिक टन था। छोटी इलायची के विकास हेतु क्रियान्वित कार्यक्रम नीचे दिये गये हैं:

1) पुनःरोपण/नया रोपण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में छोटी इलायची के उत्पादकों को रोगग्रस्त, पुराने, बूढ़े और अलाभकारी खेती की व्यवस्थित पुनः रोपाई के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रेरित करना और सीमांत उत्पादकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें पुनरोपण/नए रोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के द्वारा छोटी इलायची की खेती के क्षेत्रफल में विस्तार करना है।

(i) पुनःरोपण/नया रोपण (तमिलनाडु और केरल)

केरल और तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर सामान्य वर्ग के किसानों को ₹ 1,00,000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ₹ 2,10,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है जो परियोजना की अवधि के दौरान पुनः रोपण और रखरखाव की लागत के मद में क्रमशः 33.33 प्रतिशत और 75 प्रतिशत है, जिसका भुगतान दो समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। पंजीकृत छोटे और सीमांत इलायची उत्पादक जिनके पास चार (4) हेक्टेयर तक खेत हैं, इस कार्यक्रम के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 746.67 हेक्टेयर छोटी इलायची की पुनःरोपण के लिए 366.68 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई (जिसमें वर्ष 2024-25 के दौरान 468.15 हेक्टेयर पुनःरोपण की पहली किस्त के लिए 236.14 लाख रुपये, वर्ष 2023-24 के दौरान 278.52 हेक्टेयर पुनःरोपण की दूसरी किस्त के लिए ₹ 130.54 लाख और वर्ष 2023-24 के बैकलॉग मामले शामिल हैं), जिससे 2670 उत्पादक (महिला: 801, ट्रांसजेंडर: 0, एससी: 43, एसटी: 33) लाभान्वित हुए।

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

(ii) पुनःरोपण/नया रोपण (क) चार (4) हेक्टर से अधिक क्षेत्रों में

के किसानों को

₹.75,00,000 तक की राशि तक

के किसानों को

की है जो

खरखानों की ल

में

जिस

चार (4) हेक्टर तक खेत

के पात्र हैं।

छोटी इलायची

सहायता

83.65

ख

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

(ii) पुनःरोपण/नया रोपण (क) चार (4) हेक्टर से अधिक क्षेत्रों में

के किसानों को

₹.75,00,000 तक की राशि तक

के किसानों को

की है जो

खरखानों की ल

में

जिस

चार (4) हेक्टर तक खेत

के पात्र हैं।

छोटी इलायची

सहायता

83.65

ख

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹

₹



करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 घन मीटर होनी चाहिए। कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 30,000 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या ₹ 45,000 जो भी कम हो दी जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 23.67 लाख की वित्तीय सहायता से 78 जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिससे 78 किसानों (महिला: 24, ट्रांसजेंडर: 0 एससी: 1, एसटी: 0) को लाभ हुआ।

ii) वर्षा जल संचयन संरचनाएं

पंजीकृत इलायची कृषक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कोई भी किसान जिसने पहले यह लाभ प्राप्त कर लिया है, वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत के 33.33 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता, जो ₹18,000 तक सीमित है, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत के 75 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता, जो ₹40,000 तक सीमित है, जो भी कम हो, 200 घन मीटर क्षमता वाले टैंक के निर्माण हेतु प्रदान की जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 53 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिससे 53 किसानों (महिला: 16, ट्रांसजेंडर: 0, एससी: 1, एसटी 0) को ₹ 8.55 लाख की वित्तीय सहायता से लाभ हुआ।

iii) सिंचाई पंप सेट

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि वाले इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। सामान्य वर्ग के लिए दी जाने वाली सहायता राशि वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 30,000 जो भी कम हो, है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत, जो ₹ 45,000 तक सीमित है, है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 67 सिंचाई उपकरण स्थापित किए गए, जिससे 67 किसानों (महिला 21 ट्रांसजेंडर 0 एससी:2, एसटी:0) को ₹ 16.98 लाख की वित्तीय

सहायता से लाभ हुआ।

iv) सूक्ष्म सिंचाई / स्प्रिंकलर / आईसीटी सक्षम सिंचाई उपकरण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि वाले इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। सामान्य वर्ग के लिए दी जाने वाली सहायता राशि वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 63,000 जो भी कम हो, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या ₹ 95,000 जो भी कम हो।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 22 स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किए गए, जिससे 22 किसानों (महिला: 7 ट्रांसजेंडर: 0 एससी: 0, एसटी: 0) को ₹12.36 लाख की वित्तीय सहायता से लाभ हुआ।

4) इलायची (छोटी) के लिए मौसम आधारित बीमा

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटी इलायची उत्पादकों को प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाओं, जैसे कम या ज्यादा बारिश, गर्मी (तापमान), सापेक्ष आर्द्रता आदि से बचाना है, जो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटी इलायची के पंजीकृत इलायची उत्पादक इस कार्यक्रम में नामांकन के पात्र हैं। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (AIC), स्पाइसेस बोर्ड के तत्वावधान में इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है। इस कार्यक्रम में प्रीमियम का 75 प्रतिशत स्पाइसेस बोर्ड द्वारा और 25 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। बोर्ड अधिकतम ₹ 16,040/हेक्टेयर (जीएसटी सहित) की सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 670 किसानों को कार्यक्रम के तहत नामांकित किया गया, जिसमें 370 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया, जिसमें बोर्ड के हिस्से के रूप में ₹ 62.22 लाख की वित्तीय सहायता शामिल है (महिला:135)

ख) इलायची (बड़ी) की उत्पादकता में विकास

बड़ी इलायची मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के उ-हिमालयी इलाकों में उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में वर्ष 2024-25 के दौरान बड़ी इलायची का कुल क्षेत्रफल

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

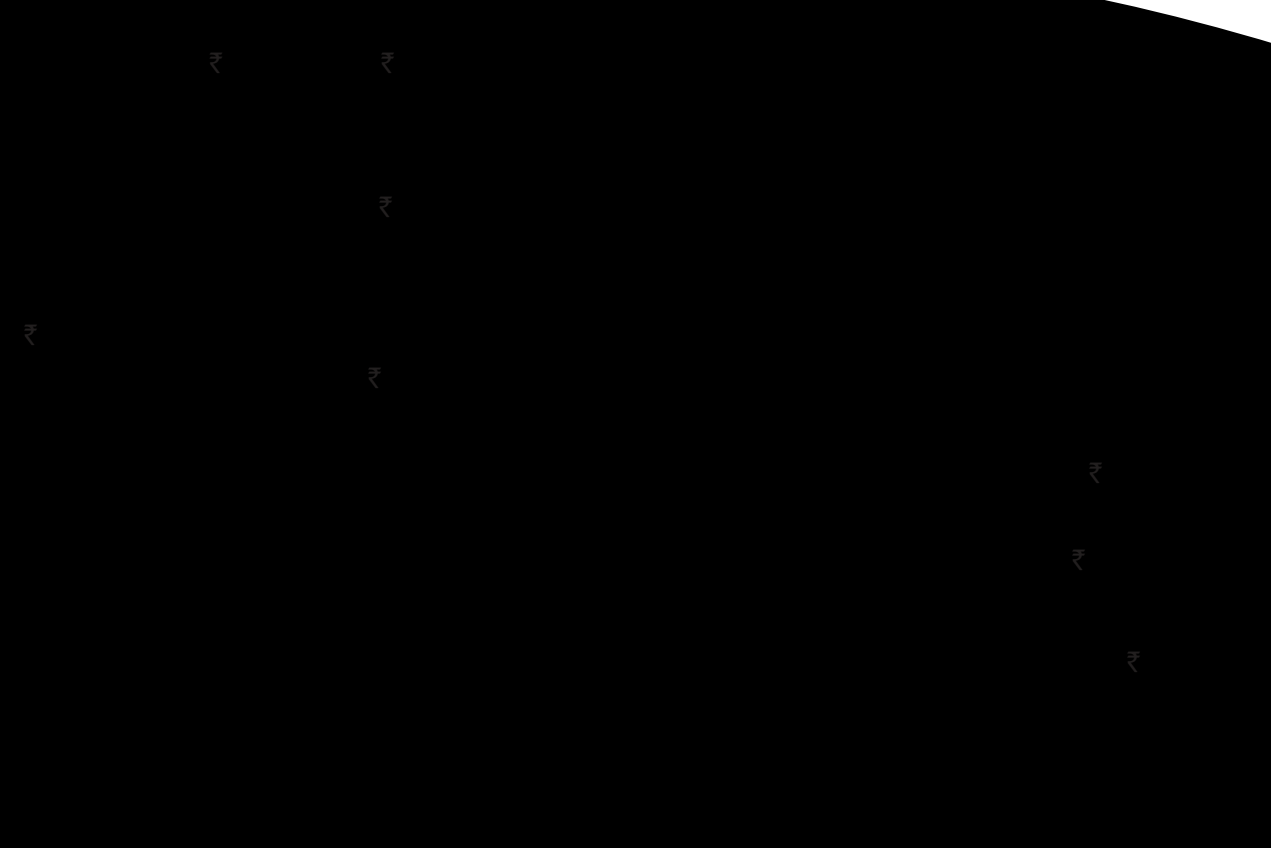
26,617 हेक्टेयर और अनुमानित 1.5 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में वर्ष 2024-25 के लिए कार्यक्रमों का क्रमबद्ध विवरण निम्नलिखित है।

क्षेत्रों में 3 मीटर से अधिक गहराई के खड्डों का निर्माण किया गया है।

पूराने और नए उपकरणों का उपयोग करके खेती के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया गया है।

कृषि क्षेत्रों में नौसेना के जहाजों के साथ-साथ बड़ी इलायची के उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

से आने वाले छोटे किसानों को अक्सर से मजबूत के लंबे शुष्क दौर जिसके कारण फसल का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ-साथ बड़ी इलायची के उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ताकी सर्दियों के मौसम में खेती की स्थिति से निपटने के लिए उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।





(ii) वर्षा जल संचयन संरचनाएं

बड़ी इलायची की खेती में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए गर्मी के महीनों में सिंचाई बहुत आवश्यक है। सिंचाई के उद्देश्य के लिए वर्षा जल का संचयन (प्रत्यक्ष वर्षा और सतही अपवाह दोनों) इलायची उत्पादकों के बीच इसकी कम लागत और सुविधा की वजह से लोकप्रिय हो रहा है। पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि है, वे इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। सहायता एचडीपीई शीट (120 जीएसएम) के साथ 200 घन मीटर क्षमता की संरचना के लिए होगी। कम क्षमता के लिए सहायता जल संचयन क्षमता के अनुपात में सीमित होगी। कोई भी किसान जिसने पहले यह लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता निर्माण की लागत का 33.33 प्रतिशत है ₹ 18,000 तक सीमित और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत ₹ 40,000 तक सीमित, जो भी कम हो, की दर से प्रदान की जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत 16 लाभार्थी किसानों (महिला 6, ट्रांसजेंडर 0, एससी: 0, एसटी: 12) को ₹ 5.52 लाख की वित्तीय सहायता के साथ 16 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया।

(iii) सिंचाई उपकरण (आईसीटी सक्षम सिंचाई उपकरण सहित)

सिंचाई उपकरणों के उपयोग से उत्पादकों को बिना अधिक बर्बादी के बेहतर तरीके से सिंचाई करने में मदद मिलती है और सिंचाई के लिए सिंचाई पंप सेट और होज़ पाइप लगाने में उत्पादकों की सहायता करने का प्रस्ताव है। पंजीकृत इलायची उत्पादक 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि वाले "सिंचाई उपकरण" कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक उत्पादकों को लाभ पहुँचाने के लिए, एक व्यक्ति को दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल एक इकाई तक ही सीमित है। कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत है, जो सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम

₹ 15,000 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत है, जो अधिकतम ₹ 22,500 तक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 36 सिंचाई पंप सेट स्थापित किए गए, जिससे 36 (महिला: 11, ट्रांसजेंडर: 0 अनुसूचित जाति: 0, अनुसूचित जनजाति: 28) किसानों को ₹ 6.70 लाख की वित्तीय सहायता मिली।

आ) मसालों की कटाई उपरांत गुणवत्ता उन्नयन

(क) चिन्हित क्लस्टरों में समूहों द्वारा कटाई के बाद सुधार के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित मसालों का मिशन

इस घटक के अंतर्गत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य निर्यात योग्य अधिशेष उत्पन्न करने हेतु केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से देश से मसालों के निर्यात को बढ़ाना है, जिससे आयातक देशों की गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी विशिष्टताओं को पूरा किया जा सके। मसालों में भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवी संदूषक भारतीय मसालों की गुणवत्ता अनुपालन को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका समाधान फसल-पश्चात गुणवत्ता उन्नयन हेतु बेहतर तकनीकों सहित उत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाकर किया जा सकता है। साथ ही, श्रमिकों की कमी की समस्या के समाधान हेतु कृषि गतिविधियों के मशीनीकरण का प्रस्ताव है। फसल-पश्चात प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से मसाला ईपीक्यूएस/किसान समूहों को उद्यमी बनने हेतु सुसज्जित और सतत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

(1) केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी कार्यक्रम

स्पाइसेस बोर्ड ने केसर के विकास, विपणन, गुणवत्ता, निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी (SPEDA) की स्थापना की। SPEDA की सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव और जम्मू और कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने SPEDA के पुनर्गठन के लिए कदम उठाए हैं। गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्रेता-विक्रेता बैठकें जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान जीआई केसर मेला सह जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया और जीआई केसर के प्रचार के लिए ₹ 1.64 लाख की राशि का उपयोग किया।

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

(2) गुणवत्ता अंतर ब्रिजिंग समूह (क्यूजीबीजी)

कटाई-पश्चात प्रबंधन मसालों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है और निर्यात योग्य अधिशेष प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेत स्तर पर बेहतर कटाई-पश्चात प्रबंधन प्रवृत्तियों को अपनाने से गुणवत्तापूर्ण मसाले उपलब्ध कराने में मदद मिलती है, जिससे भारत से मसालों के निर्यात में वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित समूहों को सहयोग प्रदान करके मसाला उत्पादकों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और पता लगाने योग्य मसालों का उत्पादन करने में सक्षम बनाना है।

(1) कटाई उपरांत की मशीन/उपकरण बैंक

प्रमुख मसाला उत्पादक समूहों में पंजीकृत मसाला उत्पादक समूह, जिनका निर्यातकों के साथ अग्रिम बाजार संपर्क है, फसलोत्तर सुधार कार्यक्रम के प्रत्येक उप-घटक के अंतर्गत मसाला उत्पादक समूहों के सदस्यों के बीच उपयोग हेतु दो मशीनें/उपकरण स्थापित करने हेतु सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यातकों के साथ समूहों का संपर्क विकसित करना है। समूहों को निर्यात के लिए मसालों की आपूर्ति हेतु निर्यातकों के साथ बाजार संपर्क व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मसाला उत्पादक समूह को कटाई उपरांत मशीन/उपकरण बैंक की स्थापना के लिए अधिकतम ₹ 23.5 लाख की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें बीजीय मसाला थ्रेशर के लिए ₹ 1,35,000 की दर से सहायता, काली मिर्च थ्रेशर के लिए ₹ 34,000 की दर से सहायता, हल्दी बाँयलर के लिए ₹ 3,38,000 की दर से सहायता, मसाला पॉलिशर के लिए ₹ 1,70,000 की दर से सहायता, पुदीना आसवन इकाइयों के लिए ₹ 3,38,000 की दर से सहायता, पत्ती/शाकीय मसाला आसवन इकाइयों के लिए ₹ 6,30,000 की दर से सहायता, ₹ 80,000/- की दर से मसाला क्लोनर/ग्रेडर/स्माइलर ग्रेविटी सेपरेटर, अधिकतम ₹ 95,000/- की दर से मसाला धुलाई उपकरण, ₹ 16,000/- की दर से मसाला स्लाइसिंग मशीनें, ₹ 1,50,000/- की दर से मसालों के लिए नवीनतम कटाई-पश्चात उपकरण (इमली डी-सीडर, लहसुन ग्रेडर, आदि), ₹ 90,000/- की दर से मसाला डिबुलर, ₹ 67,500/- मसाले सुखाने वाले स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर सतहों (सिलिपाॅलिन/तिरपाॅलिन) पर ₹ 4000/- की दर

से संचालित खेत उपकरणों हेतु मसालों को बुनियादी गुणवत्ता परीक्षण ₹ 18,000/- की दर से तथा ईपीओ के लिए सुखाने वाले प्लेटफॉर्म, तथा ₹ 1,00,000/- की दर से बाजार बाई शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, मसाला क्षेत्र के 42 किसान समूहों को विभिन्न कटाई-पश्चात मशीनें स्थापित करने के लिए ₹ 236.92 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 16,186 किसान लाभान्वित हुए।

(ii) इरराण के क्षेत्रों/पूर्वोत्तर क्षेत्र/दरकिनार किए समुदायों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, प्रमुख निर्यात/उत्पादन केंद्र के किसानों के लिए कटाई उपरांत मशीनें

(1) बीजीय मसाला थ्रेशर

कुछ बीज मसाला उत्पादकों द्वारा अपनाई जाने वाली कटाई और कटाई उपरांत की प्रथाएं अस्वास्थ्यकर हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद डटल, धूल, रेत, तने के टुकड़े आदि जैसे बाहरी पदार्थों से दूषित हो जाते हैं। काटे गए और सूखे पौधों को बांस की छड़ियों से पीटकर, पौधों को हाथ से गड़ कर बीज को अलग किया जाता है। सूखे पौधों से बीज अलग करने और साफ मसालों का उत्पादन करने के लिए, बोर्ड थ्रेशर के उपयोग को लोकप्रिय बनाना चाहता है जो मैन्युअल रूप से या बिजली का उपयोग करके संचालित होते हैं। 0.04 हेक्टर तक की भूमि वाले उत्पादक इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

बोर्ड थ्रेशर की लागत के लिए सामान्य को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान कर रहा है जिसकी अधिकतम सीमा क्रमशः ₹ 75,000 और ₹ 1,12,000 है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, किसानों के खेतों में 66 बिजली संचालित थ्रेशर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान किया गया और कुल ₹ 53.20 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 66 कृषक (महिला:18, ट्रांसजेंडर:0, एससी:4, एसटी:6) लाभान्वित हुए।

2) काली मिर्च थ्रेशर

कार्यक्रम का उद्देश्य काली मिर्च उत्पादकों को निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली काली मिर्च का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए काली मिर्च की फलियों को बाली से स्वच्छतापूर्वक अलग करने के लिए काली मिर्च थ्रेशर की



स्थापना को बढ़ावा दिया है। इस कार्यक्रम में वित्तीय सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को थ्रेशर की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 19,000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ₹ 28,000 है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 93.99 लाख की कुल वित्तीय सहायता के साथ 492 थ्रेशर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई, जिससे 492 उत्पादकों (महिला:172, ट्रांसजेंडर: 0, एससी:17, एसटी:107) को लाभ हुआ।

3) हल्दी बॉयलर

कार्यक्रम का उद्देश्य भाप से उबालने वाली इकाइयों का उपयोग करके हल्दी प्रसंस्करण के लिए बेहतर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में हल्दी उत्पादकों की सहायता करना है। यह अंतिम उत्पाद को बेहतर रंग और गुणवत्ता प्रदान करता है। स्पाइसेस बोर्ड निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाली हल्दी के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर हल्दी को उबालने वाली इकाई के उपयोग को उत्पादकों के बीच लोकप्रिय बनाता है। इस कार्यक्रम के तहत उबालने वाली इकाई की वास्तविक लागत के मद में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या सामान्य वर्ग और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए क्रमशः ₹ 1,88,000 और ₹ 2,82,000 जो भी कम हो, वह होती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 183.31 लाख की वित्तीय सहायता से हल्दी को भाप से उबालने वाली कुल 84 इकाइयों की स्थापना की गई, जिससे 84 उत्पादकों (महिला: 30, ट्रांसजेंडर: 0, एससी: 20, एसटी:14) को लाभ प्राप्त हुआ।

4) मसाला पॉलिशर

कार्यक्रम का उद्देश्य मसाला उत्पादकों, विशेष रूप से हल्दी और छोटी इलायची उत्पादकों, उत्पादकों के समूह, मसाला उत्पादक समितियों/मसाला किसान उत्पादक कंपनी इत्यादि को, मसालों की पॉलिशिंग को अपनाने के लिए प्रेरित करना और इसमें उनको सहायता देना है। इसके लिए उन्हें रियायती दरों पर बेहतर पॉलिशर्स की आपूर्ति करके निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाले मसालों का उत्पादन करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत बॉयलर इकाई की वास्तविक लागत के मद में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या सामान्य वर्ग और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति किसानों के लिए क्रमशः ₹ 94,000 और ₹ 140,000 जो भी कम हो, वह होती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 125.35 लाख की वित्तीय सहायता से 153 मसाला पॉलिशिंग इकाइयाँ (इलायची पॉलिशर व हल्दी पॉलिशर) इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई, जिससे 153 उत्पादकों (महिला:38, ट्रांसजेंडर:0, एससी:18, एसटी:24) को लाभ प्राप्त हुआ।

5) पुदीना आसवन इकाई

कार्यक्रम का उद्देश्य पुदीना उत्पादकों को अपने खेतों में स्टेनलेस स्टील से सुसज्जित आधुनिक आसवन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है ताकि आसवन इकाई की दक्षता में सुधार के साथ-साथ निर्यात के लिए तेल की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस कार्यक्रम में वित्तीय सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को आसवन इकाई की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 1,88,000/- और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ₹ 2,82,000/- है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल ₹ 16.91 लाख की वित्तीय सहायता से आठ आसवन इकाइयाँ स्थापित की गई, जिससे आठ उत्पादकों(महिला:2, ट्रांसजेंडर:0, एससी:2, एसटी:0) को लाभ हुआ।

6) मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मशीनीकरण के माध्यम से मसालों के उत्पादन में लाभप्रदता बढ़ाने और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर को लोकप्रिय बनाना है। इस कार्यक्रम में सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 44,000 प्रति इकाई और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को इकाई की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 66,000 प्रति इकाई सहायता प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 46.60 लाख की वित्तीय सहायता से कुल 153 मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर इकाइयों को स्थापित किया गया, जिससे 153 उत्पादकों (महिला: 33, ट्रांसजेंडर: 0, एससी: 6, एसटी: 35) को लाभ प्राप्त हुआ।

7) मसाला वाशिंग मशीन

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मशीनीकरण के माध्यम से मसालों के उत्पादन में लाभप्रदता बढ़ाने और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मसाला वाशिंग मशीन को



₹ 36,000 है और 400 किलोग्राम क्षमता वाली भट्टी या डबल डोर सॉ/समतुल्य ड्रायर के लिए सहायता ₹ 54,000 है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 12 लाख की वित्तीय सहायता से कुल 40 संशोधित भट्टी इकाइयों/सावो ड्रायर का निर्माण किया गया, जिससे 40 उत्पादकों (महिला 10, ट्रांसजेंडर:0 एससी:0 एसटी:27) को लाभ हुआ।

(5) मसाला संवर्धन के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए समावेशी विकास

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को मसाला खेती के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित करना तथा उन्हें प्राथमिक विक्रेता से उद्यमी बनाना है, जिससे समुदाय का उत्थान हो सके।

(i) आईसीएआर संस्थानों/एसएयूएस/केवीके एस/आईसीआरआई/समान के माध्यम से क्षमता निर्माण

कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषि/किसानों के इच्छुक युवाओं को सशक्त बनाना, खेती/उद्यमिता में उनके ज्ञान और कौशल को उन्नत करना और समुदाय के बीच मास्टर प्रशिक्षकों का एक समूह तैयार करना है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, पांच राज्यों में विभिन्न आईसीएआर संस्थानों/केवीके में छह प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिससे 183 उत्पादकों (महिला: 55, ट्रांसजेंडर: 0, एससी: 8, एसटी: 170) को लाभ हुआ। इस पर ₹ 10.19 लाख रुपये खर्च हुए।

(6) जिएल टैग वाले और अन्य मसालों के निर्यात योग्य अधिशेष को बढ़ावा देना

इस घटक का उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन को सुगम बनाने के उद्देश्य से, ऐसे मसालों की खेती के लिए उपयुक्त विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियों में, आंतरिक गुणों वाले विभिन्न मसालों और जीएल टैग वाले मसालों जैसे, लाकाडॉंग हल्दी, नागा मिर्च, हर्थई मिर्च, मिजो मिर्च, मिजो अदरक दल्ले खुरसानी आदि की खेती के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पादकों को प्रदर्शित करना और प्रेरित करना है। 0.10 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोतने वाला व्यक्तिगत पंजीकृत उत्पादक आवेदन करने के लिए पात्र है। सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के तहत न्यूनतम रोपण क्षेत्र एक सतत ब्लॉक में 0.10 हेक्टेयर है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर पात्र है, जो प्रति वर्ष 2 हेक्टेयर तक सीमित है। रोपण सामग्री की लागत के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय

सहायता प्रदान की जाती है, जो अधिकतम ₹ 25,000 प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों के 680 किसानों को 266.6 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए ₹ 60.73 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई (महिला: 204, ट्रांसजेंडर: 0, एससी :22, एसटी :484)

(ख) जैविक, इंडिगैप, प्राकृतिक खेती आदि जैसी टिकाऊ उत्पादन एवं प्रमाणन प्रणालियों को बढ़ावा देना।

1) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (समूह)

स्पाइसेस बोर्ड उत्पादक समूह प्रमाणन स्थापित करने के लिए किसान समूहों/एफपीओ को समर्थन देकर मसाला क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। जैविक खेती अपनाने के इच्छुक किसानों को जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) की स्थापना उत्पादक समूह प्रमाणन (अम्ब्रोला प्रमाणन) के लिए एक पूर्व-अपेक्षा है, ताकि इन किसानों को समूह गठन, जैविक विनियमन, प्रमाणन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, दस्तावेज़ीकरण, आंतरिक निरीक्षण आदि के बारे में तैयार किया जा सके। बोर्ड जैविक प्रमाणीकरण और उपज के एकत्रीकरण के लिए आईसीएस स्थापित करने के लिए उत्पादक समूहों/एफपीओ आदि को समर्थन देने का प्रस्ताव करता है। एक समूह/एफपीओ निधि की उपलब्धता के अनुसार लगातार तीन वर्षों तक या चरणों में वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। जैविक मसाले पैदा करने वाले समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के तहत जैविक प्रमाणीकरण की लागत का 50 प्रतिशत (जो एनईआर समूहों के अलावा अन्य के लिए अधिकतम ₹ 1,12,000 तक है) और एनईआर समूहों के लिए 75 प्रतिशत (जो अधिकतम ₹ 1,68,000 तक है) की सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान एक किसान समूह को ₹ 2.49 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(2) जैविक समूह प्रमाणीकरण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मसाला उत्पादक समूहों/एफपीओ को जैविक मसाला फार्मों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत सहायता (अधिकतम ₹ 1,50,000) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के समूहों के लिए 90 प्रतिशत सहायता (अधिकतम ₹ 2,70,000) प्रदान करता है।



(ख) स्वच्छ एवं सुरक्षित मसालों पर अभियान

‘स्वच्छ और सुरक्षित मसालों’ पर 25 फरवरी 2025 को एक अभियान चलाया गया, जो बोर्ड के 38वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह अभियान मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और निर्यात के विभिन्न चरणों में जोखिमों, सुधारात्मक कार्रवाइयों और अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में हितधारकों को जागरूक करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। सभी हितधारकों और जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए यह अभियान पूरे देश में चलाया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान 13 राज्यों में आयोजित 14 अभियानों के तहत कुल ₹ 1.68 लाख (महिला: 193, ट्रांसजेंडर :0, एससी :70, एसटी: 124) के व्यय से कुल 735 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) अध्ययन दौरे

उत्तराखंड के बड़ी इलायची किसानों के लिए बोर्ड द्वारा एक अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया। अध्ययन यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से कुल 153 किसानों को ₹ 2.65 लाख की वित्तीय सहायता से लाभान्वित किया गया।

(घ) हल्दी के लिए विशेष कार्यक्रम

वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने 12 राज्यों में 17 स्थानों पर किसानों और एफपीओ सदस्यों के लिए हल्दी के जीएपी और जीएचपी पर 17 विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम और तीन प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में हल्दी के लिए तीन खाद्य सुरक्षा और बाजार संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिन पर ₹ 57.25 लाख का व्यय हुआ है और 1,879 हितधारकों को लाभ हुआ है।

- हल्दी पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 1108 (महिला: 327, एससी :120, एसटी :471)
- मार्केट लिंकेज कार्यक्रम 771 (महिला :244, ट्रांसजेंडर :0 एससी :36 एसटी: 171)

उ) बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं

क) क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और बाजार पहुंच में सुधार करना मसालों में स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) समस्याओं का समाधान करने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड ने वर्ष 2014 में, मानकों और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत एक संगठन, जो विकासशील देशों

को उनके मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच हासिल करने या बनाए रखने की क्षमता में सुधार करने के साधन के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों को लागू करने की क्षमता बनाने में सहायता करता है) के लिए, “क्षमता निर्माण और नवीन हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और बाजार पहुंच में सुधार” शीर्षक से एक परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

इस परियोजना को अक्टूबर 2018 में एसटीडीएफ द्वारा अनुमोदित किया गया था। एफएओ इंडिया इस परियोजना के कार्यान्वयन में भागीदार और बजट धारक है और परियोजना के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। स्पाइसेस बोर्ड इस परियोजना का स्थानीय भागीदार है और सभी स्थानीय गतिविधियों का कार्यान्वयन और उनका समन्वय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठाता है।

परियोजना के समग्र उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले मसालों का भारत से विदेशी बाजार में निर्यात का विस्तार करने के लिए मसाला मूल्य श्रृंखला में शामिल हितधारकों की क्षमता निर्माण।
 - छोटे पैमाने के किसानों की आय बढ़ाना, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों को सशक्त बनाना
 - गरीबी कम करने के प्रयासों का समर्थन करना (एसडीजी 1/0 और भूख (एसडीजी 2))
- यह परियोजना चार राज्यों के 12 गांवों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें चार मसालों पर ध्यान केंद्रित किया गया है अर्थात;
- गुजरात और राजस्थान में (प्रत्येक राज्य के चार गांवों में लागू) में जीरा और सौंफ
 - मध्य प्रदेश में (दो गांवों में) धनिया
 - आंध्र प्रदेश में (दो गांवों में) काली मिर्च

यह परियोजना 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित एक आरंभिक कार्यशाला के साथ शुरू हुई थी। परियोजना के चार चरण में सितंबर 2024 तक पूरी हो गई। तीसरे चरण के दौरान आयोजित गतिविधियों में शामिल हैं:

- परियोजना कार्यान्वयन क्षेत्रों से चयनित किसानों/एफपीओ के लिए पास के जिलों और राज्यों में उद्योगों/प्रसंस्करण सुविधाओं/मसाला पार्कों के लिए चार क्षेत्रीय दौरे आयोजित किए गए, जिससे 61 उत्पादकों (महिला: 4.एससी:2. एसटी: 10) को लाभ हुआ।



निर्यात विकास और संवर्धन

स्पाइसेस बोर्ड को मसालों (53 अनुसूचित मसालों और उनके उत्पादों) के निर्यात संवर्धन, इलायची (छोटी एवं बड़ी) के उत्पादन, अनुसंधान, विकास एवं घरेलू विपणन तथा निर्यात हेतु मसालों के गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रमाणन का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र योजना - “निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता (SPICED)” के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रहा है।

भारत से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर गया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत ने ₹ 39,994.48 करोड़ (4,722.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 17,99,267 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया, जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 14,899.67 करोड़ (2432.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 8,93,920 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था, जो मात्रा में 101 प्रतिशत, रुपये के मूल्य के संदर्भ में 168 प्रतिशत और डॉलर के मूल्य के संदर्भ में 94 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2014-15 से मसालों के निर्यात में मात्रा में सात प्रतिशत, मूल्य (भारतीय रुपये) में दस प्रतिशत और मूल्य (अमेरिकी डॉलर) में सात प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है।

जम्मू और कश्मीर में केसर मूल्य श्रृंखला में शामिल एफपीओ/एफपीसी हितधारकों के साथ वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की गई। मंत्री ने केसर पार्क का दौरा किया जहाँ केसर की कटाई के बाद की प्रसंस्करण का प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने कोच्ची, केरल स्थित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के मुख्यालय में 21 फरवरी 2025 को आयोजित एक बैठक में मसाला क्षेत्र के हितधारकों के साथ बातचीत की। बैठक में मसाला क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा

की गई। बातचीत के प्रमुख क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित कालीमिर्च की निगरानी को मजबूत करना, मूल्यवर्धित प्रसंस्करण को आगे बढ़ाना और जैविक मसाला निर्यात का विस्तार करना शामिल रहा। बैठक के दौरान अन्य बागान फसलों के साथ संभावित मसालों की अंतर-फसल, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, आयातक देशों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित कड़े खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों और पूर्वोत्तर भारत में शाकीय मसालों की खेती पर भी चर्चा की गई।

‘बाज़ार विस्तार के लिए क्षमता बढ़ाना’, ‘व्यापार संवर्धन’ और ‘तकनीकी हस्तक्षेप’ घटकों के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा निर्यात संवर्धन हेतु बुनियादी ढाँचे के विकास में निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है, ताकि ऐसे प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित मसालों का निर्यात बढ़ाया जा सके जो आयातक देशों के उभरते खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों। वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने और प्रक्रिया उन्नयन को प्रोत्साहित करने के अलावा, बोर्ड मसालों की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। उपर्युक्त घटकों के अंतर्गत ज़ोर देने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, मिशन मूल्य संवर्धन, व्यापार संवर्धन, उत्पाद विकास और अनुसंधान, प्रमुख मसाला उत्पादक/विपणन केंद्रों में सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण (मसाला पार्क) के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थापना, जैविक मसालों/जीआई मसालों को बढ़ावा देना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना आदि।

क. बाजार विस्तार के लिए क्षमता बढ़ाना

अ) मिशन मूल्य संवर्धन:

1. मसालों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी और अवसंरचनात्मक हस्तक्षेप (टीआईआईपीएस)

कार्यक्रम का उद्देश्य मसालों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए सुविधाएं स्थापित करने, मसाला प्रसंस्करण

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

में उच्च तकनीक बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप करने आदि के लिए कार्यालय है। कार्यालय को मूल्य श्रृंखला को आसानी से सीजनल, अस्थ-साथ-साथ और बाजार के पैमाने पर अपने

सहायता करना है, जिससे भारत के किसानों को मसालों के उत्पादन के लिए आसानी मिलेगी और उत्पादन में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के तहत 1.50 करोड़ तक तकनीकी हस्तक्षेप की जायेगी और सहायक उपकरण की लागत अधिकतम ₹ 1.50 करोड़ तक तकनीकी हस्तक्षेप के दौरान इस कार्यक्रम के तहत तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान की गई।

केंद्रों



| क्रमांक | स्थान/राज्य | शामिल मसाले | भूमि क्षेत्र (एकड़) |
|---------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश | मिर्च और लहसुन | 10.00 |
| 2 | पुट्टुडी, केरल | काली मिर्च और इलायची | 12.50 |
| 3 | जोधपुर, राजस्थान | जीरा और धनिया | 60.00 |
| 4 | गुना, मध्य प्रदेश | धनिया | 100.00 |
| 5 | शिवगंगा, तमिलनाडु | मिर्च और हल्दी | 75.00 |
| 6 | गुंटूर, आंध्र प्रदेश | मिर्च | 125.00 |
| 7 | रामगंजमंडी (कोटा), राजस्थान | धनिया | 30.00 |
| 8 | रायबरेली, उत्तर प्रदेश | पुदीना | 11.79 |

(i) मसाला पार्कों में सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थिति

सभी पार्कों में मसालों और मसाला उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और भंडारण के लिए सुस्थापित सामान्य

प्रसंस्करण इकाइयों हैं, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित संचालकों के माध्यम से कार्यरत हैं। प्रत्येक पार्क में उपलब्ध प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ-साथ संचालकों के नाम नीचे दिए गए हैं:

| मसाला पार्क का स्थान | प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण | ऑपरेटर का नाम |
|----------------------|---|---|
| छिंदवाड़ा | लहसुन सुखाने / निर्जलीकरण और मिर्च निष्कर्षण | मेसर्स वी नेचुरल |
| गुना | बीजीय मसालों, विशेष रूप से धनिया के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग सुविधाएं | मेसर्स मयंक इंडस्ट्रीज |
| गुंटूर | मिर्च की सफाई, छंटाई, पीसने और पैकेजिंग की सुविधाएं | मेसर्स माने कांकोर स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड |
| जोधपुर | बीजीय मसालों, विशेष रूप से जीरे के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग सुविधाएं | मेसर्स श्री राधे कृष्णा स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड |
| रामगंज मंडी (कोटा) | बीजीय मसालों, विशेष रूप से धनिया के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग सुविधाएं | मेसर्स ओर्कला इंडिया लिमिटेड |
| पुट्टुडी | इलायची और काली मिर्च के लिए सफाई, ग्रेडिंग, पीसने, पैकेजिंग की सुविधाएं | मेसर्स फ्लेवरिट स्पाइसेज ट्रेडिंग लिमिटेड |
| रायबरेली | पार्क और प्रभावी क्षेत्र में पुदीना और अन्य पाक शाकों के तेल आसवन इकाई | आसवन इकाइयों सीधे किसान समूहों द्वारा संचालित की जाती हैं |
| शिवगंगा | मिर्च और हल्दी के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग की सुविधाएं | मेसर्स सीजन फ्रेश एग्रो फूड्स |



ख. भारतीय मसालों का उत्पाद एवं बाजार विकास और ब्रांडिंग

1. भारतीय मसालों के लोगो और ब्रांडों का प्रचार

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से पहचाने गए विदेशी बाजारों में भारतीय ब्रांडों के प्रवेश को बढ़ाना है, साथ ही पता लगाने और खाद्य सुरक्षा की एक स्पष्ट पहचान भी सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के तहत, जिन निर्यातकों ने बोर्ड के साथ अपने ब्रांड को पंजीकृत कराया है, वे प्रति ब्रांड ₹ 100 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के तहत सहायता में स्लॉटिंग/लिस्टिंग शुल्क और प्रचार व्यय का 100 प्रतिशत और उत्पाद विकास की लागत का 50 प्रतिशत शामिल है, ताकि निर्यातकों को विदेशों में चुनिंदा शहरों में पहचाने गए आउटलेट्स में निर्दिष्ट ब्रांडों को स्थापित करने में मदद मिल सके। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने इस कार्यक्रम के तहत एक निर्यातक को ₹ 15.70 लाख की राशि जारी की।

2. नमूने भेजने के लिए मसाला निर्यातकों को सहायता (एएसईएसएस)

मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात ठेका आम तौर पर खरीदारों को उपलब्ध कराए गए नमूनों के आधार पर संपन्न होते हैं। निर्यातकों को अनुमोदन के लिए और खरीदारों की आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए विदेशों में अपने ग्राहकों को नमूने भेजने की आवश्यकता होती है। नमूनों को कूरियर करने की उच्च लागत और ठेका हासिल करने के लिए कूरियर किए जाने वाले नमूनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड निर्यातकों को नमूने विदेश भेजने के लिए कूरियर शुल्क की लागत की भरपाई के लिए सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत नए पंजीकृत निर्यातकों (पिछले तीन वर्षों में स्पाइसेस बोर्ड के साथ पहला पंजीकरण) और सूक्ष्म और लघु श्रेणी के अंतर्गत आने वाले निर्यातकों और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य श्रेणी के लिए कूरियर शुल्क की लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम ₹ 1.50 लाख प्रति वर्ष है, और एससी/एसटी निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमालयी राज्यों, राज्य अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीप समूह (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों के लिए, कूरियर शुल्क का 75

प्रतिशत, जो अधिकतम ₹ 2.25 लाख प्रति वर्ष है, की सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान तक इस कार्यक्रम के तहत सात निर्यातकों को ₹ 1.30 लाख की सहायता प्रदान की गई।

3. निर्यात के लिए उत्पाद विकास का समर्थन करना

मसालों में औषधीय, सौंदर्यवर्धक, पोषण संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी गुण पाए जाते हैं। देश में ऐसे उपयोगों के बारे में पारंपरिक ज्ञान का एक विशाल भंडार उपलब्ध है। हालाँकि, मसालों/मसाला अर्क/मसाला मिश्रणों के प्रशंसित गुणों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रलेखित साक्ष्य/सत्यापन अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं। दस्तावेज़ीकरण/सत्यापन का अभाव ऐसे उत्पादों की बाजार उपलब्धता को बाधित करता है। यदि वैज्ञानिक रूप से किए गए परीक्षणों और नैदानिक मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक दस्तावेज़ीकरण/सत्यापन तैयार किया जाता है, तो उत्पादों को अत्यधिक मूल्यवर्धन के साथ तैयार किया जा सकता है और इन उत्पादों को वैकल्पिक दवाओं, कार्यात्मक खाद्य पदार्थों, न्यूट्रास्युटि कल्स, प्रतिरक्षा बूस्टर आदि के रूप में स्थापित बाजारों में विपणन और पेटेंट (यदि आवश्यक हो) कराया जा सकता है। साथ ही, देश में उत्पादित मसालों से नए अंतिम उपयोग और अनुप्रयोग प्राप्त करने की भी गुंजाइश है। मसालों से नए अंतिम उत्पादों के विकास में अपरंपरागत अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है, जिससे निर्यात की अधिक संभावना वाले पेटेंट योग्य उत्पादों का निर्माण हो सकता है। यह योजना उत्पाद अनुसंधान और विकास, नैदानिक परीक्षणों, गुणों के सत्यापन, और पेटेंटिंग एवं परीक्षण विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पंजीकृत निर्यातक और आवश्यक सुविधाओं वाले अनुसंधान एवं विकास संस्थान, उत्पाद विकास, अनुसंधान की लागत के 50 प्रतिशत तक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, जिसमें नए उपकरणों/ उपकरणों का विकास/प्रौद्योगिकी का सत्यापन शामिल है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये तक हो सकता है, यदि इसमें नैदानिक परीक्षण (अंतर्राष्ट्रीय), पेटेंटिंग और वाणिज्यिक/नियामक अनुमोदन (ईपीए, एफडीए आदि) शामिल हैं। यदि नैदानिक परीक्षण, पेटेंटिंग आदि शामिल नहीं हैं, तो सहायता ₹ 25 लाख तक सीमित होगी। उपकरण की लागत के लिए सहायता, यदि कोई हो, परियोजना लागत के अधिकतम 25 प्रतिशत तक मानी जाएगी। साथ ही, केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों/अनुसंधान एवं विकास और सरकार के अन्य संस्थानों के लिए सहायता का पैमाना बिना किसी बदलाव के परियोजना लागत के 100 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। वर्ष



परीक्षण किया और संबंधित परीक्षण रिपोर्ट जारी की।

(iv) मसालों के निजी नमूनों का परीक्षण

बोर्ड निर्यातकों/किसानों/हितधारकों से मसालों और मसाला उत्पादों के निजी नमूने प्राप्त करता है ताकि उनके द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार उनके मसालों/मसाला उत्पादों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सके।

वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने 346 निजी नमूनों का परीक्षण किया और परीक्षण रिपोर्ट जारी की।

6. पंजीकरण और लाइसेंसिंग

(i) मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस)

मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के अनुसार, मसालों का निर्यात करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) होना आवश्यक है। मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 के अनुसार, सीआरईएस जारी होने की तिथि से तीन वर्षों के लिए वैध है।

बोर्ड द्वारा सीआरईएस जारी करने की प्रक्रिया, वर्ष 2022-23 के दौरान डीजीएफटी द्वारा विकसित कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म (ईआरसीएमसी) में स्थानांतरित कर दी गई और मई 2022 से, सीआरईएस डीजीएफटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 4,106 सीआरईएस जारी किए गए, जिनमें से 3,713 व्यापारी निर्यातकों को और 393 निर्माता निर्यातकों को दिए गए।

(ii) इलायची डीलर और नीलामीकर्ता लाइसेंस

इलायची लाइसेंसिंग एवं विपणन नियम, 1987 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो नीलामीकर्ता या डीलर के रूप में इलायची का व्यवसाय करना चाहता है, उसके पास बोर्ड से वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। तदनुसार, बोर्ड द्वारा इलायची (छोटी एवं बड़ी) के लिए नीलामीकर्ता और डीलर लाइसेंस जारी किए जाते हैं। व्यापार को सुगम बनाने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (ऋक्ष्क्ष्) द्वारा विकसित राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (ऋच्छ्) को अपनाया है, जिसके तहत 01 अगस्त 2022 से इलायची डीलर और

नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नीलामीकर्ता और डीलर लाइसेंस तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और वर्तमान ब्लॉक अवधि (2023-26) 31 अगस्त 2026 तक है।

अब तक, बोर्ड ने 705 इलायची डीलर लाइसेंस जारी किए हैं, जिनमें 688 छोटी इलायची डीलर लाइसेंस और 17 बड़ी इलायची डीलर लाइसेंस शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने 130 इलायची डीलर लाइसेंस जारी किए, जिनमें से 116 छोटी इलायची डीलरों को और 14 बड़ी इलायची डीलरों को जारी किए गए।

वर्तमान में, इलायची के लिए 18 लाइसेंस प्राप्त ई-नीलामीकर्ता और चार लाइसेंस प्राप्त मैनुअल नीलामीकर्ता हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने छोटी इलायची के लिए दो इलायची ई-नीलामीकर्ता लाइसेंस और बड़ी इलायची के लिए एक मैनुअल नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी किया।

(iii) इलायची की नीलामी - क्लाउड-आधारित लाइव ई-नीलामी प्रणाली की स्थापना

बोर्ड ने 1 नवंबर 2021 से 'क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी' शुरू की, जिससे दोनों नीलामी केंद्रों को वर्चुअल लिंक करना और साथ-साथ ई-नीलामी का संचालन संभव हो गया। इस प्रणाली में, किसान और डीलर अपनी सुविधानुसार किसी भी नीलामी केंद्र से इलायची की नीलामी में भाग ले सकते हैं, जबकि पहले की प्रणाली में किसानों और डीलरों को नीलामी में भाग लेने के लिए संबंधित नीलामी केंद्र तक जाना पड़ता था। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भी क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी प्रणाली जारी रखी। क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी प्रणाली ने नीलामी में खरीदारों की भागीदारी बढ़ाने में मदद की, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति संभव हुई। वर्ष 2024-25 के दौरान, ई-नीलामी/मैनुअल नीलामी के माध्यम से कुल 23,335 मीट्रिक टन इलायची (छोटी) बेची गई, जिसका भारित औसत मूल्य ₹ 2575.98/किलोग्राम था।

ख. व्यापार संवर्धन

अ) व्यापार मेलों/बैठकों/सेमिनारों/प्रशिक्षणों में भागीदारी

स्पाइसेस बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मसालों को बढ़ावा देने और

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

निर्यातकों को अवसर प्रदान करने के लिए, बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों और म भाग लेता है। इन कार्यक्रमों के समर्थन में निर्यातकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, बोर्ड नियमित रूप से निर्यातकों के बीच सीधे बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

उत्तराखंड में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक के अंतर्गत, सामान्य तौर पर निर्यात के 50 प्रतिशत तक की लागत में सहायता प्रदान की जा सकती है।

क्रेता-विक्रेता बैठक के नियमित रूप से होने तथा मसालों के निर्यात स्रोतों के उद्देश्य से बोर्ड क्रेता-विक्रेता बैठकों को प्रोत्साहित कर रहा है, जो मसाला उत्पादकों, निर्यातकों और बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

बोर्ड निर्यातकों के लिए निर्यात स्रोतों के उद्देश्य से बोर्ड क्रेता-विक्रेता बैठकों को प्रोत्साहित कर रहा है, जो मसाला उत्पादकों, निर्यातकों और बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

| क्रमांक | कार्यक्रम का नाम | तारीख |
|---------|---|----------------|
| 1 | उत्तराखंड में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक | 22 अगस्त 2024 |
| 2 | केरल के इडुक्की में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक | 11 सितंबर 2024 |
| 3 | गंगटोक, सिक्किम में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक | 25 सितंबर 2024 |
| 4 | कर्नाटक के हुबली में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक | 25 नवंबर 2024 |
| 5 | ओडिशा में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक | 7 दिसंबर 2024 |
| 6 | जम्मू और कश्मीर में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक | 12 दिसंबर 2024 |
| 7 | अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक | 23 जनवरी 2025 |
| 8 | रांची, झारखंड में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक | 28 जनवरी 2025 |
| 9 | तेलंगाना के निज़ामाबाद में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक | 18 मार्च 2025 |
| 10 | खाद्य सुरक्षा और बाजार संपर्क कार्यक्रम, नागपुर, महाराष्ट्र | 23 मार्च 2025 |
| 11 | खाद्य सुरक्षा और बाजार संपर्क कार्यक्रम, चेन्नई, तमिलनाडु | 24 मार्च 2025 |
| 12 | खाद्य सुरक्षा और बाजार संपर्क कार्यक्रम, शिलांग, मेघालय | 26 मार्च 2025 |



में भी मदद करती हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कीं:

(ii) उद्यमिता विकास कार्यक्रम

मसाले और मूल्यवर्धित मसाला उत्पाद विश्व बाजार में लगातार वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, जिससे मसाला प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में उद्यमशील उपक्रमों की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। स्पाइसेस बोर्ड, प्रगतिशील हितधारकों को मसाला व्यवसाय में प्रवेश के लिए आकर्षित, प्रेरित और सुसज्जित करने हेतु, पूरे भारत से प्रतिभागियों को शामिल करते हुए

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को मसाला निर्यात क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर संवेदनशील और शिक्षित करना है, जिसमें निर्यात दस्तावेजीकरण और प्रक्रिया, गुणवत्ता और सुरक्षा मानक, निर्यात के लिए नियामक आवश्यकताएँ, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, निर्यात रसद, निर्यात डेटा और रुझानों का विश्लेषण आदि शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्रमांक | कार्यक्रम का नाम | तारीख |
|---------|--|-------------------|
| 1 | मसालों के निर्यात के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उंझा, गुजरात | 12-13 अगस्त 2024 |
| 2 | नमूनाकरण और प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ के विनियमन पर मसाला उद्योग के लिए क्षमता निर्माण, कोच्चि, केरल | 06-07 दिसंबर 2024 |
| 3 | नमूनाकरण और प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ के विनियमन पर मसाला उद्योग के लिए क्षमता निर्माण, उंझा, गुजरात | 09-10 दिसंबर 2024 |
| 4 | नमूनाकरण और प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ के विनियमन पर मसाला उद्योग के लिए क्षमता निर्माण, मुंबई, महाराष्ट्र | 12-13 दिसंबर 2024 |

भौगोलिक संकेत पंजीकरण

स्पाइसेस बोर्ड ने पाँच मसालों, अर्थात् मलबार कालीमिर्च, अलेप्पी ग्रीन कार्डमम, कूर्ग ग्रीन कार्डमम, गुंटूर सन्नम चिली और ब्यादगी मिर्च के लिए जीआई रजिस्ट्री से जीआई टैग प्राप्त किया है और वह इन पाँच जीआई टैग प्राप्त मसालों का पंजीकृत स्वामी है।

ग. तकनीकी हस्तक्षेप

1. उभरते उद्यमिताओं के लिए मसाला इनक्यूबेशन केंद्रों को सहायता (एस्पायर)

बोर्ड निर्यातकों, स्टार्ट-अप, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) और नवीन विचारों वाले उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए चिन्हित विशेषज्ञ संस्थानों में 'मसाला इनक्यूबेशन केंद्र' स्थापित करने हेतु एक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मसाला क्षेत्र में नवीन उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास में उनका मार्गदर्शन और सहायता करना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आवश्यक अवसरचना विकसित करने के

लिए विशेषज्ञ संस्थानों को ₹ 10 लाख तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, चिन्हित विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से बोर्ड द्वारा स्थापित मसाला इनक्यूबेशन केंद्रों में चयनित परियोजना पर इनक्यूबेशन के लिए प्रति इनक्यूबेटी ₹ 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इनक्यूबेटी और विशेषज्ञ संस्थानों का चयन प्राप्त आवेदनों के आधार पर एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

वर्तमान में, बोर्ड ने कृषि व्यवसाय विकास निदेशालय (डीएबीडी), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), कोयंबतूर में कृषि-व्यवसाय इनक्यूबेशन सोसाइटी द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई) और एस्पायर कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर के साथ सहयोग किया है।

मेसर्स श्री राजा राजेश्वरी ट्रेडर्स को एस्पायर कार्यक्रम के अंतर्गत सीएफटीआरआई मैसूर में इनक्यूबेटी के रूप में चुना गया है और



व्यापार सूचना सेवा

विपणन विभाग की व्यापार सूचना सेवा मसालों के निर्यात, आयात, क्षेत्र, उत्पादन, नीलामी और घरेलू कीमतों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।

भारत से मसालों के अनुमानित निर्यात/आयात को संकलित करने के लिए सूचना का प्रमुख स्रोत वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता/वाणिज्य मंत्रालय (एमओसी) की वेबसाइट/निर्यात की दैनिक सूची (डीएलई)/सीमा शुल्क द्वारा प्रकाशित आयात की दैनिक सूची (डीएलआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्यात/आयात आंकड़े हैं। बोर्ड मसालों के निर्यात विवरण को मासिक आधार पर और आयात विवरण को वार्षिक आधार पर संकलित कर रहा है और ये आंकड़े नियमित आधार पर अपनी वेबसाइट और मंत्रालय/विभागों के माध्यम से हितधारकों तक प्रसारित किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड नियमित रूप से कोचीन, जेएनपीटी, चेन्नई, तूतीकोरिन, मुंद्रा, कोलकाता, पेट्रॉपोल, मोहदीपुर, रक्सौल, अमृतसर/डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता जैसे सभी प्रमुख बंदरगाहों से डीएलई और डीएलआई दोनों एकत्र करता है

बोर्ड अपनी वेबसाइट और प्रकाशनों के माध्यम से नियमित रूप से भारत और विदेश के प्रमुख बाजारों से मसालों की कीमतों की जानकारी संकलित करता है और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाता है। मूल्य विवरण एकत्र करने के प्रमुख स्रोत भारतीय काली मिर्च और मसाला व्यापार संघ, कृषि उत्पाद विपणन समितियाँ, व्यापारी संघ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय, इंडोनेशिया जैसी एजेंसियाँ हैं। ये सभी जानकारी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सदस्यता के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से भी एकत्र की जाती है।

बोर्ड इलायची (छोटी एवं बड़ी) के उत्पादन विकास के लिए उत्तरदायी है, और इलायची के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता का अनुमान व्यापार सूचना सेवा द्वारा बोर्ड के क्षेत्रीय ढाँचे के

माध्यम से किए गए क्षेत्रीय नमूना अध्ययन के आधार पर लगाया जाता है। अन्य मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी/कृषि/बागवानी विभागों/डीएएसडी से संकलन हेतु एकत्र किया जाता है। सभी मसालों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की जानकारी बोर्ड के प्रकाशनों के साथ-साथ वेबसाइट के माध्यम से हितधारकों एवं नीति निर्माताओं तक पहुँचाई गई है।

निर्यातकों के पंजीकरण (विनियम) के अनुसार, सभी पंजीकृत मसाला निर्यातकों को बोर्ड को अपना तिमाही निर्यात रिटर्न प्रस्तुत करना होता है। व्यापार सूचना सेवा पंजीकृत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत तिमाही निर्यात रिटर्न का संकलन कर रही है और निर्यातक-वार मसालों के निर्यात का डेटाबेस बनाए रख रही है। इस डेटाबेस का उपयोग करके, प्रत्येक मसाले के प्रमुख निर्यातकों का विवरण संकलित किया जाता है और हितधारकों के अनुरोध पर आधिकारिक उद्देश्य/प्रसार के लिए उपयोग किया जाता है।

बोडिनायकनूर और पुडुडी में बोर्ड द्वारा विकसित ई-नीलामी केंद्रों के माध्यम से इलायची के व्यापार के लिए ई-नीलामी आयोजित कर रहा है। इलायची की दैनिक नीलामी मात्रा और औसत मूल्य का विवरण बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दैनिक आधार पर संकलित और प्रकाशित किया जाता है। नीलामी बिक्री और औसत मूल्य का समेकित विवरण बोर्ड के प्रकाशन के माध्यम से संकलित और प्रसारित किया जाता है।

उद्योग के हितधारकों के लाभ के लिए विभिन्न बाजार केंद्रों के लिए विभिन्न मसालों की साप्ताहिक घरेलू कीमत बोर्ड के प्रकाशन अर्थात् मसाला बाजार के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर (वेबसाइट पर) संकलित और प्रकाशित की जाती है।

क. मसालों का क्षेत्र और उत्पादन

वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए इलायची (छोटी) और इलायची (बड़ी) का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तालिका ६ और ६क्ष में दी गई है। अन्य मसालों का क्षेत्रफल और उत्पादन तालिका-६क्ष में दिया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

तालिका-I: इलायची (छोटी) का उत्पादन

| राज्य | 2023-24 | | | | 2024-25 | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
| | कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | उपज क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | उत्पादन (एमटी) | उत्पादकता (कि.ग्रा./हेक्टेयर) | कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | उपज क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | उत्पादन (एमटी) | उत्पादकता (कि.ग्रा./हेक्टेयर) |
| केरल | 40345 | 30949 | 22868 | 738.90 | 40345 | 30095 | 18310 | 608.41 |
| कर्नाटक | 25135 | 14666 | 867 | 59.17 | 25135 | 14694 | 902 | 61.40 |
| तमिलनाडु | 4930 | 2781 | 1495 | 537.73 | 4930 | 2727 | 1484 | 544.24 |
| कुल | 70410 | 48396 | 25230 | 521.33 | 70410 | 47516 | 20696 | 435.57 |

उत्पादन (बड़ी मात्रा में)

| राज्य | 2023-24 | | | | 2024-25 | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
| | कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | उपज क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | उत्पादन (एमटी) | उत्पादकता (कि.ग्रा./हेक्टेयर) | कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | उपज क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | उत्पादन (एमटी) | उत्पादकता (कि.ग्रा./हेक्टेयर) |
| सिक्किम | 23312 | 17453 | 5280 | 302.50 | 23312 | 17550 | 5429 | 309.33 |
| पश्चिम बंगाल | 3305 | 3165 | 1069 | 338.00 | 3305 | 3187 | 1089 | 341.79 |
| अरुणाचल प्रदेश | 12131 | 7078 | 1806 | 255.14 | 12438 | 7289 | 1864 | 255.65 |
| नागालैंड | 6631 | 4431 | 1128 | 254.64 | 6694 | 4473 | 1165 | 260.47 |
| मणिपुर | 217 | 64 | 5 | 76.50 | 267 | 64 | 5 | 79.89 |
| कुल | 45596 | 32191 | 9288 | 288.54 | 46017 | 32563 | 9552 | 293.33 |

| मसाले | 2023-24 | | 2024-25 * | |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | उत्पादन (एमटी) | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | उत्पादन(एमटी) |
| काली मिर्च | 312902 | 126038 | 254597 | 77533 |
| मिर्च | 965612 | 2909844 | 921540 | 2693265 |
| अदरक (ताजा) | 194243 | 2333000 | 193258 | 2246292 |
| हल्दी (सूखी) | 292830 | 1063224 | 290939 | 1116124 |
| धनिया | 604075 | 836524 | 627008 | 869443 |
| जीरा | 1302336 | 894565 | 1094382 | 723795 |
| अजमोदा | 4657 | 6882 | 4590 | 6636 |
| सौंफ | 216019 | 376049 | 129858 | 243666 |



| | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| मेथी | 158203 | 249523 | 147000 | 226853 |
| लहसुन | 388676 | 3315545 | 405115 | 3422491 |
| इमली | 35593 | 132429 | 39563 | 138113 |
| लौंग | 1847 | 1015 | 1887 | 1031 |
| जायफल | 25743 | 18940 | 26204 | 19012 |
| अन्य सहित कुल योग | 5056599 | 12483215 | 4686713 | 11995594 |

स्रोत: सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कोझिकोड; (*) : पहला अग्रिम अनुमान

ख. इलायची (छोटी) की नीलामी बिक्री और कीमतें

वर्ष 2024-25 (अगस्त 2024 - जुलाई 2025) और वर्ष 2023-24 (अगस्त 2023- जुलाई 2024) के लिए इलायची (छोटी) की राज्यवार नीलामी बिक्री और भारत औसत मूल्य तालिका-IV में दिए गए हैं।

तालिका IV: इलायची (छोटी) की नीलामी बिक्री और कीमतें

(मात्रा टन में, कीमत ₹/किया में)

| केंद्र | 2023-24 (अगस्त-जुलाई) | | 2024-25 (अगस्त-जुलाई) | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | बेची गई मात्रा | भारत औसत नीलामी मूल्य | बेची गई मात्रा | भारत औसत नीलामी मूल्य |
| केरल और तमिलनाडु (ई-नीलामी) | 29119 | 1763.89 | 23315 | 2575.94 |
| कर्नाटक | 11 | 1335.40 | 4 | 2229.23 |
| महाराष्ट्र | 106 | 1916.09 | 17 | 2728.54 |
| कुल | 29237 | 1764.43 | 23335 | 2575.98 |

स्रोत: लाइसेंस प्राप्त नीलामकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्टें

ग. इलायची (बड़ी) की कीमतें

वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के लिए गंगटोक और सिलीगुड़ी बाजारों में इलायची(बड़ी) के औसत थोक मूल्य तालिका V में दिए गए हैं।

(कीमत ₹/किया में)

| केंद्र | श्रेणी | 2023-24 | 2024-25 |
|-----------|----------|---------|---------|
| गंगटोक | बड़ादाना | 930.21 | 1481.25 |
| सिलीगुड़ी | बड़ादाना | 1177.90 | 1687.17 |

स्रोत: स्पाइसेस बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, गंगटोक।

घ. अन्य प्रमुख मसालों की कीमतें

प्रमुख मसालों के औसत घरेलू मूल्य नीचे दिए गए हैं। ये मूल्य चैंबर ऑफ कॉमर्स, भारतीय काली मिर्च एवं मसाला व्यापार

संघ, व्यापारी संघों द्वारा तैयार की गई बाज़ार समीक्षाओं आदि जैसे द्वितीयक स्रोतों से एकत्र किए गए हैं। महत्वपूर्ण बाज़ार केंद्रों में प्रमुख मसालों के मूल्य तालिका VI में दिए गए हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

तालिका VI: महत्वपूर्ण बाजारों की कीमतें (₹/मि. में)

| मसाला | बाज़ार | 2023-24 | 2024-25(*) |
|---------------------|-------------|-----------|------------|
| काली मिर्च (एमजी-1) | कोचीन | 572.83 | 656.78 |
| मिर्च | गुंटूर | 161.30 | 124.85 |
| हल्दी | चेन्नई | 109.43 | 152.08 |
| | निजामाबाद | 95.25 | 119.58 |
| धनिया | चेन्नई | 103.29 | 99.31 |
| | रामगंज मंडी | 75.23 | 72.60 |
| जीरा | चेन्नई | 554.08 | 374.33 |
| | उंझा | 425.70 | 235.64 |
| सौंफ | चेन्नई | 279.00 | 159.81 |
| मेथी | चेन्नई | 101.30 | 115.44 |
| लहसुन | चेन्नई | 105.55 | 174.71 |
| खसखस | चेन्नई | 1407.21 | 1407.96 |
| अजवाइन के बीज | चेन्नई | 188.40 | 175.89 |
| सरसों | चेन्नई | 85.26 | 84.84 |
| इमली | चेन्नई | 113.43 | 137.05 |
| केसर | दिल्ली | 166562.50 | 212145.83 |
| लौंग | कोचीन | 901.03 | 843.07 |
| जायफल(छिलका सहित) | कोचीन | 229.89 | 242.26 |
| जायफल (छिलका रहित) | कोचीन | 425.53 | 495.92 |
| जावित्री (मेस) | कोचीन | 779.04 | 917.80 |



अप्रैल 2024-मार्च 2025 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात अप्रैल 2023-मार्च 2024 की तुलना में नीचे तालिका VII में दिया गया है।

तालिका VII: अप्रैल-मार्च 2023-24 की तुलना में अप्रैल-मार्च 2024-25 के दौरान भारत से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात

| मसाले | अप्रैल-मार्च 2024-25 (एफ) | | | अप्रैल-मार्च 2023-24 (आर) | | | % परिवर्तन | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | मात्रा (टन में) | मूल्य (लाखों में) | मूल्य (मिलियन डॉलर) | मात्रा (टन में) | मूल्य (लाखों में) | मूल्य (मिलियन डॉलर) | मात्रा (टन में) | मूल्य (लाखों में) | मूल्य (मिलियन डॉलर) |
| काली मिर्च | 20830.15 | 105500 | 124.54 | 17890.17 | 73648.88 | 88.91 | 16% | 43% | 40% |
| इलायची छोटी | 6727.81 | 156682 | 184.65 | 6168.13 | 99959.85 | 120.52 | 9% | 57% | 53% |
| इलायची बड़ी | 1368.35 | 22944 | 27.02 | 1280.82 | 14815.41 | 17.86 | 7% | 55% | 51% |
| मिर्च | 715506.26 | 1140490 | 1342.52 | 601084.35 | 1249248.45 | 1509.00 | 19% | -9% | -11% |
| अदरक | 131359.75 | 106240 | 124.78 | 60833.26 | 64688.57 | 77.95 | 116% | 64% | 60% |
| हल्दी | 176325.34 | 288539 | 341.54 | 162018.46 | 187586.79 | 226.65 | 9% | 54% | 51% |
| धनिया | 60323.05 | 63320 | 74.84 | 108623.74 | 94820.97 | 114.74 | -44% | -33% | -35% |
| जीरा | 229881.07 | 617886 | 732.35 | 165269.45 | 579723.43 | 700.37 | 39% | 7% | 5% |
| अजमोदा | 8473.43 | 11879 | 14.05 | 6598.58 | 10074.31 | 12.17 | 28% | 18% | 15% |
| सौंफ | 76586.12 | 76544 | 90.93 | 39564.69 | 66960.91 | 80.97 | 94% | 14% | 12% |
| मेथी | 44515.97 | 36589 | 43.23 | 30854.92 | 26612.76 | 32.14 | 44% | 37% | 35% |
| अन्य बीज (1) | 35109.48 | 34959 | 41.37 | 39437.98 | 36177.50 | 43.74 | -11% | -3% | -5% |
| लहसुन | 43958.58 | 53838 | 63.34 | 73950.06 | 44118.84 | 53.33 | -41% | 22% | 19% |
| इमली | 43985.96 | 30328 | 35.78 | 27128.02 | 18475.00 | 22.30 | 62% | 64% | 60% |
| जायफल और जावित्री | 4756.16 | 25192 | 29.85 | 5142.74 | 28687.69 | 34.63 | -8% | -12% | -14% |
| करी पाउडर/पेस्ट | 77151.45 | 209499 | 247.59 | 72420.92 | 175727.66 | 212.18 | 7% | 19% | 17% |
| मसाला तेल/ तैलीराल | 20940.26 | 453324 | 535.92 | 18762.47 | 412300.59 | 497.98 | 12% | 10% | 8% |
| पुदीना उत्पाद (2) | 27282.92 | 353576 | 417.8 | 27658.60 | 343919.81 | 415.40 | -1% | 3% | 0.6% |
| अन्य मसाले (3) | 74185.37 | 212119 | 250.55 | 75004.69 | 168333.08 | 203.33 | -1% | 26% | 23% |
| कुल | 1799267 | 3999448 | 4722.65 | 1539692 | 3695880.50 | 4464.17 | 17% | 8% | 6% |

स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय / डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता; एफ: अंतिम और आर: संशोधित अंतिम

(1) मसाले का पौधा (अजोवन बीज), सोआ बीज, खसखस बीज, सौंफ, सरसों आदि शामिल हैं।

(2) मेन्थॉल, मेन्थॉल क्रिस्टल और अन्य पुदीना तेल शामिल हैं।

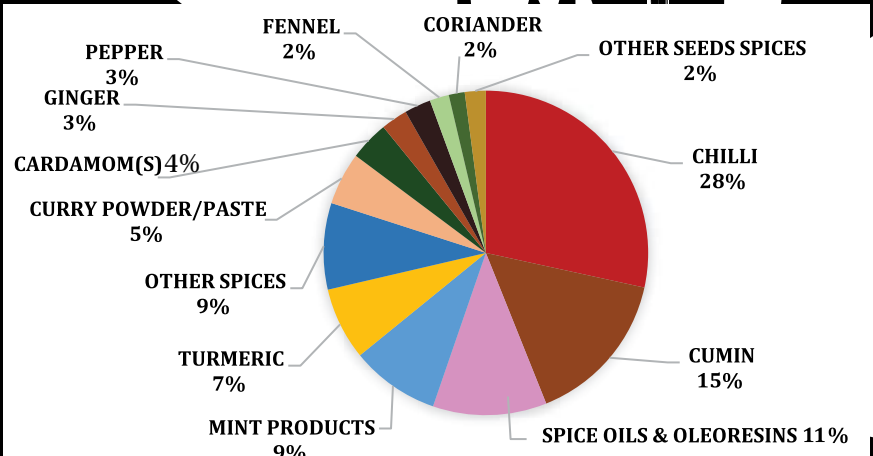
(3) हींग, दालचीनी, कैसिया, कम्बोजिया, केसर, मसाले (एन इ एस), आदि शामिल हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

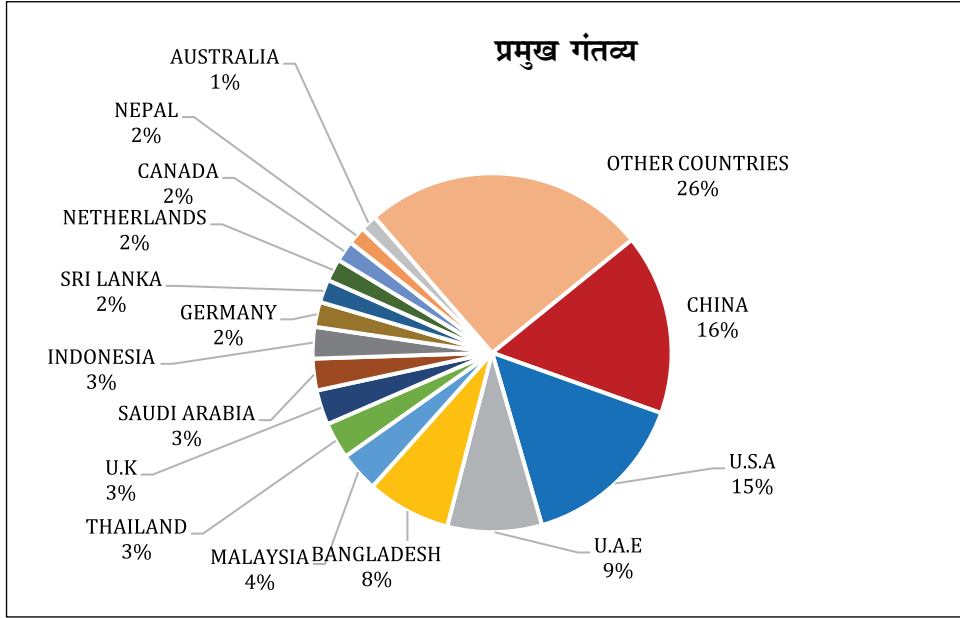
च. वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख मसाला निर्यात बाजारों में भारत की निर्यात गतिविधि का विश्लेषण किया गया है। निर्यात गतव्य चीन (15%), यूएसए (15%), इंडोनेशिया (9%), बांग्लादेश (8%), मलेशिया (7%), थाईलैंड (7%), वियतनाम (7%), श्रीलंका (6%), अरब एमिरेट्स (5%), मसाला तेल और तैलीराल (5%), इटली (4%), स्पेन (3%), कोरिया (3%), जर्मनी (3%), फ्रांस (3%), ऑस्ट्रेलिया (3%), जपान (3%), अन्य (3%)।

मसाला तेल और तैलीराल (5%), हल्दी (7%), कुरी पाउडर/पेस्ट (5%), इलायची (छोटी) (4%), अदरक (3%), कालीमिर्च (3%), सौंफ (2%), धनिया (2%), अन्य बीज मसाले (2%)।

भारत मसाला निर्यात बास्केट में प्रमुख निर्यात बाजारों में निर्यात गतिविधि का विश्लेषण किया गया है। निर्यात गतव्य चीन (15%), यूएसए (15%), इंडोनेशिया (9%), बांग्लादेश (8%), मलेशिया (7%), थाईलैंड (7%), वियतनाम (7%), श्रीलंका (6%), अरब एमिरेट्स (5%), मसाला तेल और तैलीराल (5%), इटली (4%), स्पेन (3%), कोरिया (3%), जर्मनी (3%), ऑस्ट्रेलिया (3%), जपान (3%), अन्य (3%)।



| वस्तु | मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर) | % योगदान |
|----------------------|-----------------------------|----------|
| मिर्च | 1342.52 | 28 |
| जीरा | 732.35 | 16 |
| मसाला तेल और तैलीराल | 535.92 | 11 |
| पुदीना उत्पाद | 417.8 | 9 |
| हल्दी | 341.54 | 7 |
| अन्य मसाले | 406.54 | 9 |
| करी पाउडर/ पेस्ट | 247.59 | 5 |
| इलायची (छोटी) | 184.65 | 4 |
| अदरक | 124.78 | 3 |
| कालीमिर्च | 124.54 | 3 |
| सौंफ | 90.93 | 2 |
| धनिया | 74.84 | 2 |
| अन्य बीज मसाले | 98.65 | 2 |
| कुल | 4722.65 | |



| देश | मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर) | % योगदान |
|-------------|-----------------------------|------------|
| चीन | 769.58 | 16 |
| यु.एस.ए. | 711.16 | 15 |
| यु.ए.ई. | 401.73 | 9 |
| बांग्लादेश | 357.96 | 8 |
| मलेशिया | 169.73 | 4 |
| थाईलैंड | 154.98 | 3 |
| यू.के. | 148.24 | 3 |
| साऊदी अरब | 134.6 | 3 |
| इंडोनेशिया | 134.41 | 3 |
| जर्मनी | 106.37 | 2 |
| श्रीलंका | 97.55 | 2 |
| नीदरलैंड | 94.81 | 2 |
| कनाडा | 88.88 | 2 |
| नेपाल | 77.24 | 2 |
| ऑस्ट्रेलिया | 69.5 | 1 |
| अन्य देश | 1205.91 | 26 |
| कुल | 4722.65 | 100 |



| | | | |
|----|--|----------------------------|---------------------------|
| 10 | भारत सरकार के वाणिज्य सचिव के साथ उद्योग संपर्क बैठक(स्पाइसेस बोर्ड और 'हाउस ऑफ हिमालय लिमिटेड' और 'राज्य बागवानी मिशन(उत्तराखंड)' के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह) | देहरादून | 09 अक्तूबर 2024 |
| 11 | सारास मेला | लेजर वैली पार्क, गुरुग्राम | 13-29 अक्तूबर 2024 |
| 12 | भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला | प्रगति मैदान, नई दिल्ली | 14-27 नवंबर 2024 |
| 13 | 21 केलकाता फूडटेक - 2024 | कोलकाता | 29 नवंबर - 01 दिसंबर 2024 |
| 14 | एसआईएएल इंडिया 2024 | नई दिल्ली | 5-7 दिसंबर 2024 |
| 15 | कर्नाटक उत्पादक संघ द्वारा कॉफी सम्मेलन 2024 | सकलेशपुर | 23 दिसंबर 2024 |
| 16 | इंडस फुड 2025 | ग्रेटर नोएडा, एनसीआर | 8-10 जनवरी 2025 |
| 17 | आईसीएआर-एनआरसीएसएस का रजत जयंती स्थापना दिवस समारोह | अजमेर | 19 जनवरी 2025 |
| 18 | जिला प्रशासन, अल्लूरी सीताराम राजु जिले में गणतंत्र दिवस समारोह | पडेरू | 26 जनवरी 2025 |

अंतर्राष्ट्रीय मेलों की सूची जिनमें स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रतिभागिता की गई हैं।

| क्रमांक | मेले का नाम | स्थान | मेले की तारीख |
|---------|--|----------------------|--------------------|
| 1. | शंघाई अंतर्राष्ट्रीय मसाला और खाद्य सामग्री प्रदर्शनी 2024 | शंघाई, चीन | 28-30 अगस्त 2024 |
| 2. | फाइन फूड ऑस्ट्रेलिया 2024 | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया | 2-5 सितंबर 2024 |
| 3. | वर्ल्ड फूड मॉस्को 2024 | मॉस्को, रूस | 17-20 सितंबर 2024 |
| 4. | एसआईएएल (सियाल) पेरिस 2024 | पेरिस, फ्रांस | 19-23 अक्तूबर 2024 |
| 5. | फुड इंजीनियर्स नोर्थ अमेरिका 2024 | लास वेगास, यूएसए | 30-31 अक्तूबर 2024 |
| 6. | गल्फूड मैनुफैक्चरिंग 2024 | दुबई, युएई | 5-7 नवंबर 2024 |
| 7. | फुड इंजीनियर्स यूरोप 2024 | फ्रैंकफर्ट, जर्मनी | 19-21 नवंबर 2024 |
| 8. | फूडेक्स जापान 2025 | टोक्यो, जापान | 11-14 मार्च 2025 |
| 9. | आईएफई मैनुफैक्चरिंग 2025 | लंदन, यूके | 17-19 मार्च 2025 |

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

ग) ऑनलाइन प्रचार अभियान

प्रदेशीय भारतीय मसालों और स्पॉन्सर्स बोर्ड की गतिविधियों के माध्यम से 2024-25 के दौरान, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया है। अभियान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन प्रचार और व्यापारिक विकास के लिए प्रयत्न किए गए हैं।

स्पॉन्सर्स बोर्ड का बाजबा

2022 को लॉन्च किया गया स्पॉन्सर्स बोर्ड का उद्देश्य है, व्यापारिक विकास को बढ़ावा देना और बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।

प्रदेशीय भारतीय मसालों के स्वयंसेवक प्रकाशित किए गए हैं।

2024-25 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ होईंगीं।

- चिदेस
- डुप
- पाइसेस
- जिस

अन्य प्रचार अभियान

पूजादि के अवसरों पर किया जा रहा है। स्वयंसेवक व्यापारिक विकास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सबस्क्राइबर्स का उपयोग के लिए ईमेल के माध्यम से किया जाता है।

2024-25 के दौरान मसालों, मसालों के उपयोग, मसालों के उत्पादन आदि से संबंधित ब्रोशर, लिफाफे तैयार किए गए।

स्थापना के लिए

2024-25 में निविदाओं आदि के लिए बोर्ड



गुणवत्ता सुधार

कोच्ची में स्पाइसेज बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (QEL) की स्थापना वर्ष 1989 में बोर्ड की अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची को ब्रिटिश मानक संस्थान (BSI), यू.के. द्वारा 1997 से ISO 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत, 1999 से ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रमाणित किया गया है और इसे राष्ट्रीय परीक्षण और अंशान्कन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL), भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI), भारत सरकार द्वारा सितंबर 2004 से ISO/IEC:17025 प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत भी मान्यता प्राप्त है। चूंकि गुणवत्ता को प्रमुख प्रतिबद्धता माना जाता है, इसलिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने गुणवत्ता प्रणालियों को निरंतर उन्नत करके अपनी विश्वसनीयता हमेशा बनाए रखा है और बनाए रखना जारी रखा है। प्रयोगशाला को BSI द्वारा नवीनतम उन्नत प्रणालियों, ISO 9001:2015 और ISO 14001:2015 के तहत प्रमाणित किया गया है, और NABL द्वारा ISO/IEC 17025:2017 (NABL-FSSAI एकीकृत) के तहत मान्यता भी प्राप्त है।

भारत से निर्यात किए जाने वाले मसाले उपयुक्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हों तथा ग्राहकों को समय पर, विश्वसनीय और सटीक परीक्षण परिणाम उपलब्ध हों, इस उद्देश्य से स्पाइसेज बोर्ड ने क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं स्थापित करके पूरे भारत में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। प्रमुख निर्यात केन्द्रों अर्थात् चेन्नई, गुंटूर, मुंबई, नई दिल्ली, तूतीकोरिन, कांडला और कोलकाता में वर्तमान में सात क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला संचालित हो रहे हैं, तथा स्पाइसेज पार्क, जोधपुर में जीरा और अन्य बीज मसालों के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधा और माइलाडुम्परा, इडुक्की में छोटी इलायची में कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित है। कोच्ची, मुंबई, गुंटूर, चेन्नई, नई दिल्ली, तूतीकोरिन और कांडला स्थित प्रयोगशालाओं को NABL द्वारा ISO/IEC 17025:2017 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, तथा गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोलकाता मान्यता प्राप्त करने

की प्रक्रिया में है।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला बोर्ड के निर्यात खेपों के अनिवार्य नमूनाकरण और परीक्षण के तहत नमूनों का विश्लेषण करते हैं, भारतीय मसाला उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करते हैं और देश में उत्पादित और संसाधित मसालों की गुणवत्ता की निगरानी में मदद करते हैं। प्रयोगशालाएं आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषण करने के लिए परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित हैं। प्रयोगशाला की विश्लेषणात्मक सेवाओं से संबंधित दस्तावेज, जिसमें कार्यपत्रक तैयार करना और विश्लेषणात्मक परिणाम प्रस्तुत करना शामिल है, 'QUADMAS' नामक सॉफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन बनाए जाते हैं और इन्हें लगातार अपडेट किया जाता है।

क. विश्लेषणात्मक सेवाएँ

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के परीक्षण का दायरा स्पाइसेज बोर्ड की वेबसाइट पर मुख्य शीर्षक - गुणवत्ता और उप-शीर्षक - विश्लेषणात्मक सेवाएं और शुल्क के अंतर्गत उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने मसालों और मसाला उत्पादों की निर्यात खेपों के अनिवार्य परीक्षण के तहत निम्नलिखित विश्लेषण के लिए सेवाएं प्रदान करना जारी रखा:

1. मिर्च (कुटी हुई, पाउडर और पिसी हुई), मिर्च के बीज, करी पाउडर, करी मसाला, करी पेस्ट, और हल्दी पाउडर और इसके उत्पादों (कटे हुए को छोड़कर) में एफ्लोटॉक्सिन और सूडान डाई (I से IV) के लिए परीक्षण।
2. साबुत मिर्च, हल्दी (साबुत और कटी हुई), अदरक और उसके उत्पाद, जायफल और उसके उत्पाद, जावित्री और उसके उत्पाद, तथा खाने के लिए तैयार वस्तुओं में एफ्लोटॉक्सिन की जांच।
3. करी पत्ते में कीटनाशकों (114 कीटनाशकों) की जांच।
4. जीरे में बाहरी पदार्थ और अन्य बीजों की जांच।

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

5. मिर्च, अदरक, काली मिर्च, ... निलो, ... और ... में कीटनाशक अवशेषों ... फोस, ... फूल, लौंग ... फस, क ... मि ... मि ... बादि ... पर दे ... केसर, ह ... निय ... आर ... सरसों के ... और ... प ... और प्र ... अज ... न, ... और प्र ... 0 की ... आओलियोरेसिन ... कोच्ची ने 01 जून 2024 से ... विश्लेषणात्मक सेवा में क्य ... शामिल किया है। प्रयोगशाला ने ... एप्लटाटॉक्सिन, अवैध रंग, कीट ... अन्य बीज, क्य ... साल्मोनेला ... का विश्लेषण किया था। ... और परीक्षण के दायरे के

| गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला | प्राप्त नमूनों की संख्या | परीक्षण किये गये मापदंडों की संख्या | परीक्षण किये गये अनिवार्य नमूनों की संख्या |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| कोच्ची | 18983 | 37675 | 34537 |
| कांडला | 18147 | 37527 | 37342 |
| चेन्नई | 20526 | 26950 | 20417 |
| मुंबई | 19292 | 36865 | 32780 |
| नरेला | 2839 | 6232 | 5964 |
| तूतीकोरिन | 4815 | 10196 | 10190 |
| गुंटूर | 11200 | 19319 | 18455 |
| कोलकाता | 3913 | 4684 | 4665 |
| जोधपुर | 103 | 206 | 206 |
| कुल योग | 99818 | 179654 | 164556 |



को पूरा करने के लिए, वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों ने निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में भाग लिया:

1. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची के वैज्ञानिक-सी, वरिष्ठ रसायन विज्ञानी और कनिष्ठ रसायन विज्ञानी ने केरल राज्य उत्पादकता परिषद, कलमशशेरी, केरल द्वारा 25 जून 2024 से 26 जून 2024 तक आयोजित 'ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पर आंतरिक लेखा परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम' में भाग लिया।
2. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची के कनिष्ठ रसायन विज्ञानी ने 22 जुलाई 2024 से 23 जुलाई 2024 तक कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CUSAT), कोच्ची के परिष्कृत परीक्षण और इंस्ट्रुमेंटेशन केंद्र (STIC) द्वारा आयोजित "ISO/IEC 17025:2017 के अनुसार विधि सत्यापन, वैधीकरण और माप अनिश्चितता" पर प्रशिक्षण में भाग लिया।
3. वैज्ञानिक-सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 26 जुलाई 2024 को हैविटेट सेंटर, नई दिल्ली में भारत में 'डेटा उत्पादन और अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) निर्धारण के फसल समूहीकरण सिद्धांत' पर एक कार्यशाला में भाग लिया।
4. वैज्ञानिक-सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 20 अगस्त 2024 को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), नई दिल्ली में FAD 9 (मसाले की तकनीकी समिति), "तकनीकी समिति के सदस्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला-सह-मंथन सत्र" में भाग लिया।
5. वैज्ञानिक-सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 30 अगस्त 2024 को हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशंस, बेंगलुरु द्वारा आयोजित "खाद्य पदार्थों में खनिज तेल घटकों के विश्लेषण पर कार्यशाला" में भाग लिया।
6. वैज्ञानिक-सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, गुंटूर ने होटल द चांसरी पैवेलियन, बेंगलुरु, कर्नाटक में 18 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 तक "ISO/IEC 17025:2017 पर आधारित NABL मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" में भाग लिया।
7. वैज्ञानिक-ए, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 20 नवंबर 2024 को ITC ग्रैंड चोला, चेन्नई में स्पिनको चेन्नई और शिमादजु जापान द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय मास स्पेक्ट्रोमीटर सम्मेलन" में भाग लिया।
8. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची के वरिष्ठ रसायनविज्ञानी और कनिष्ठ रसायनविज्ञानी ने 06 जून

2024 से 07 जून 2024 तक मानसून एम्प्रेस, कोच्ची में "मसालों के नमूने और प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ के विनियमों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम" में भाग लिया।

9. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कांडला ने 09 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक गुजरात के ऊंझा में "मसाला उद्योग के लिए नमूनाकरण और प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ के नियमों पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम" में भाग लिया।
10. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई, और वैज्ञानिक-ए, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 12 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक नवी मुंबई में "मसालों के नमूने और प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ के नियमों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम" में भाग लिया।
11. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 18 दिसंबर 2024 को BIS-राष्ट्रीय प्रशिक्षण मानकीकरण संस्थान (NITS), नोएडा द्वारा आयोजित "ISO ऑनलाइन मानक विकास" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
12. कनिष्ठ सूक्ष्मजीवविज्ञानी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 28 दिसंबर 2024 को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (TCB) प्रभाग, QCI द्वारा आयोजित 'सूक्ष्मजीववैज्ञानिक परीक्षण के लिए विधि सत्यापन और वैधीकरण' पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण में भाग लिया।
13. कनिष्ठ रसायनविज्ञानी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोलकाता ने 20 जनवरी 2025 से 21 जनवरी 2025 तक "रासायनिक विश्लेषण की विधि सत्यापन और वैधीकरण (कीटनाशक अवशेष, संदूषक और पोषण विश्लेषण को कवर करते हुए)" पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण में भाग लिया।
14. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 10 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक "प्रवीणता परीक्षण में उपयोग के लिए ISO 13528 2022 सांख्यिकीय विधियां" विषय पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण में भाग लिया।
15. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची ने 10 फरवरी 2025 से 21 फरवरी 2025 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, रोम, इटली में 'खाद्य पदार्थों में माइकोटॉक्सिन के नमूने लेने और विश्लेषण पर सुरक्षित भोजन के लिए बेहतर प्रशिक्षण (BTSF)' प्रशिक्षण में भाग लिया।
16. कनिष्ठ सूक्ष्मजीवविज्ञानी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 28 फरवरी 2025 को प्रशिक्षण और क्षमता



में भाग लिया।

10. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, गुंटूर ने 07 अक्टूबर 2024 से 08 अक्टूबर 2024 तक मलेशिया में “अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय (IPC) की गुणवत्ता पर 30वीं बैठक” में भाग लिया।
11. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 15 जनवरी 2025 को कीटनाशकों पर FAD 27 की एक्च 11वीं बैठक में भाग लिया।
12. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 20 मार्च 2025 को ISO FAD 09 मसाला अनुभागीय समिति की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।
13. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई ने 20 मार्च 2025 को कोडेक्स समिति (CCCF) के अध्यक्ष के साथ नमूना योजना के लिए एक मानक का मसौदा तैयार करने के संबंध में खाद्य पदार्थों में संदूषण पर एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।

ड. आई एस ओ प्रणाली से संबंधित गतिविधियाँ

1. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला चेन्नई और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला गुंटूर ने ISO 17025-2017 के निरंतर अनुपालन के लिए NABL डेस्कटॉप ऑडिट पूरा किया था।
2. क्यूईएल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कांडला ने ISO/IEC 17025:2017 नवीनीकरण ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था।
3. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची ने निरंतर अनुपालन के लिए NABL FSSAI एकीकृत निगरानी ऑडिट 08 मार्च 2025 से 09 मार्च 2025 तक और ISO 9001:2015 और ISO 14001:2015 ऑडिट 17 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।

च. स्पाइसेज बोर्ड का चेक नमूना कार्यक्रम/प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम

अ) अंतर-प्रयोगशाला जांच नमूना (ILC) कार्यक्रम का विवरण

1. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, तूतीकोरिन ने जीरा में बाहरी पदार्थ और अन्य बीजों तथा हल्दी पाउडर में करक्यूमिन सामग्री के मापदंडों के लिए ILC कार्यक्रम का आयोजन किया।
2. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने एंटरोबैक्टी

रियासी पैरामीटर के लिए ILC कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

3. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने पैरामीटर कीटनाशक अवशेषों के लिए ILC कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

आ) PT कार्यक्रम विवरण

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा संचालित दक्षता परीक्षण कार्यक्रमों, जैसे खाद्य विश्लेषण प्रदर्शन मूल्यांकन योजना (FAPAS), अंतर्राष्ट्रीय पेपर समुदाय, फेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, और आश्वी दक्षता परीक्षण एवं विश्लेषणात्मक सेवाओं के अंतर्गत, विभिन्न गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (कोच्ची, तूतीकोरिन, चेन्नई, नरेला, गुंटूर, मुंबई, कांडला और कोलकाता) ने विभिन्न भौतिक, रासायनिक और अवशिष्ट मापदंडों, जैसे एफ्लाटॉक्सिन, ऑक्रैटॉक्सिन A, सिंथेटिक डाई (सूडान I से IV, पैरारेड), कीटनाशक अवशेष (क्लोरपाइरीफॉस, डायज़िनॉन), अम्ल अघुलनशील राख, कुल राख, वाष्पशील तेल, नमी, करक्यूमिन, पिपेरिन, बाहरी/विदेशी पदार्थ, अन्य बीज, कैप्साइसिन, कुल कैप्साइसिनोइड्स (SHU), ASTA कलर और सूक्ष्मजीवविज्ञानी पैरामीटर जैसे *साल्मोनेला*, *स्टैफिलोकोकस ऑरियस*, कुल एरोबिक माइक्रोबियल गणना, यीस्ट और मोल्ड गणना, *ई.कोलाइ*, कोलीफॉर्म, एंटरोबैक्टीरियासी, *बैसिलस सेरेस* में भाग लिया।

छ. शुरू की गई परियोजनाएं/मानकीकरण कार्य

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोलकाता ने मसालों में गुणवत्ता मापदंडों के मानकीकरण का कार्य शुरू किया है।

ज. प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उपकरणों की खरीद

1. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने एक नया ICP MS (इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमैट्री) प्रणाली खरीदा और इसके दायरे में ट्रेस-लेवल हेवी मेटल विश्लेषण को शामिल करके अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाया। यह उन्नत प्रणाली गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला को मसालों में अति-निम्न-स्तरीय ट्रेस धातु विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। प्रयोगशाला ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए मसालों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, मसालों में लोड जैसी खतरनाक धातुओं सहित, 11 भारी धातुओं के लिए विश्लेषणात्मक सेवाएं शुरू कीं। इस अपग्रेड से गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची को मसालों में भारी धातुओं के लिए कड़े विनियामक और संवेदनशीलता आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची ने माइक्रोबायोलॉजी अनुभाग में उप-नमूनाकरण के

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

लिए एक वर्टिकल लोमिनर... xi. वेनिका... गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची,

मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई नए नई LC... गुणवत्ता

नए नए... गुणवत्ता

जोड़... गुणवत्ता

नए LC... गुणवत्ता

कीटनाशक... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता

गुणवत्ता... गुणवत्ता



पैनलबद्धता योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रयोगशाला की पहुंच प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों और प्रमुख निर्यात केन्द्रों के निकट सुनिश्चित करके जांच में लगने वाला समय (TAT) कम करना है। इसके अलावा, यह पहल बोर्ड को आयातक देशों द्वारा उठाई गई परीक्षण आवश्यकताओं को तुरंत पूरा करने और भारत के मसाला निर्यात उद्योग के समग्र विकास के लिए निजी क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता और उन्नत बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।

वर्तमान में, बोर्ड के आठ गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, पैनलबद्ध प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर मसालों के लिए विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला नेटवर्क नामक एक समेकित परीक्षण ढांचा बनाते हैं। इस संरचना के अंतर्गत, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला जांच करने वाली मुख्य संस्थाओं के रूप में कार्य

करती हैं, जबकि पैनलबद्ध प्रयोगशालाएं क्षमता और भौगोलिक पहुंच बढ़ाने के लिए द्वितीयक सहायता इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं। पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए, बोर्ड ने 2022 में प्रयोगशाला पैनलीकरण योजना पर एक व्यापक मैनुअल प्रकाशित किया था, जिसमें पात्रता मानदंड, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का विवरण दिया गया है। इस मैनुअल को 2024 में उभरते उद्योग की जरूरतों और नियामक चुनौतियों के अनुरूप संशोधित किया गया। वर्ष 2023 में, बोर्ड ने NABL को QCI के तहत उनकी एकीकृत मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पैनल आवश्यकताओं के अनुपालन को सत्यापित करने का काम सौंपा। वर्तमान में, अनिवार्य परीक्षण गतिविधियों के लिए 11 प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध किया गया है, तथा नेटवर्क का आगे विस्तार सक्रिय रूप से चल रहा है।





आठवां सत्र 13-17 अक्टूबर 2025 के दौरान आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में, मसालों पर पांच नए कोडेक्स मानकों, अर्थात् वेनिला, स्वीट मार्जोरम, धनिया, बड़ी इलायची और दालचीनी का विकास कार्य प्रगति पर है, जिन पर आगामी सत्र में विचार किया जाएगा। भारत की ओर से स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिक धनिया के मानक के विकास पर इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूह (EWG) की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा, स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिक भी वर्तमान में विकसित किए जा रहे अन्य मसाला मानकों के लिए EWG में सदस्य के रूप में भाग ले रहे हैं। दिसंबर 2024 के दौरान मसालों और पाक शाकों पर कोडेक्स समिति के आठवें सत्र के आयोजन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय (MoC) के साथ पत्राचार शुरू कर दिया गया है।

IV. खाद्य पदार्थों में संदूषकों पर कोडेक्स समिति -17वां सत्र

खाद्य पदार्थों में संदूषकों पर कोडेक्स समिति (CCCF17) का 17वां सत्र अप्रैल 2024 में पनामा सिटी में आयोजित हुआ जिसमें स्पाइसेस बोर्ड के एक अधिकारी ने, मसालों में माइक्रोटॉक्सिन की अधिकतम सीमा के विकास पर इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूह के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया था। बैठक के दौरान, समिति ने मसालों में माइक्रोटॉक्सिन के परीक्षण के लिए नमूनाकरण योजना को कोडेक्स प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ाने की सिफारिश की, तथा निर्णय नियम और कुल नमूना भार पर भारत के प्रस्तावों पर सहमति भी व्यक्त की।

इस समिति सत्र में मसालों में लेड संदूषक का अधिकतम स्तर (MLs) का विकास भी प्रगति पर रहा। नवंबर 2024 के दौरान जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (CAC47) के 47वें सत्र में सूखे एरिल, सूखे पुष्प भाग, सूखे फल और बेरीज, सूखे पेपरिका और सुमाक, सूखी सिचुआन काली मिर्च और स्टार ऐनीज़, सूखे प्रकंद और जड़, और सूखे बीजों में लेड का अधिकतम स्तर को स्वीकृति दी गई। सूखी छाल और सूखी पाक शाकों में भी लेड का अधिकतम स्तर को स्वीकृति दी गई। CAC47 ने मसालों के लिए समूह में लेड का अधिकतम स्तर निर्धारित करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के बारे में भारत की चिंता को नोट किया, जिससे नमूनों का असमान वितरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लेड का अधिकतम स्तर संभावित रूप से गैर-प्रतिनिधिक हो सकते हैं। CAC47 ने सदस्य देशों को CCCF18 (2025) में चर्चा और

निर्णय लेने में सुविधा के लिए डेटा की मांग पर प्रतिक्रिया देने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

वर्तमान में, भारत की ओर से स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिक 'कुछ मसालों (सूखी मिर्च, जायफल और लाल शिमला मिर्च) में कुल एफ्लाटॉक्सिन और ओक्रैटॉक्सिन ए के लिए नमूनाकरण योजना' विषय पर इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं।

V. निर्यात अस्वीकृतियों की निगरानी के लिए तकनीकी-वैज्ञानिक समिति

भारतीय मसालों के निर्यात अस्वीकृतियों तथा भारतीय मसालों की गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित अन्य तकनीकी मामलों की निगरानी के लिए स्पाइसेस बोर्ड में एक तकनीकी-वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया। मार्च 2025 तक, कुल 15 सत्र आयोजित किए गए हैं, जिनमें इस अवधि के दौरान हुए निर्यात अस्वीकृतियों के मूल कारणों का विश्लेषण किया गया तथा बोर्ड को सिफारिशें प्रस्तुत की गईं।

VI. राष्ट्रीय मसाला गुणवत्ता एवं सुरक्षा समिति (NCSQS)

स्पाइसेस बोर्ड ने, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक सलाहकार समिति अर्थात्, 'राष्ट्रीय मसाला गुणवत्ता एवं सुरक्षा समिति' (NCSQS) का गठन किया है जिसमें गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं सहित भारतीय मसालों और उनके निर्यात को प्रभावित करने वाली चुनौतियों और तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मसाला क्षेत्र के विभिन्न विभागों, संस्थानों और हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

राष्ट्रीय मसाला गुणवत्ता एवं सुरक्षा समिति (NCSQS3) का तीसरा सत्र 24 अक्टूबर 2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। सत्र की अध्यक्षता स्पाइसेस बोर्ड के निदेशक (अनुसंधान) ने किया था। इस सत्र में नियामक क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञों जैसे कि सचिव CIB एवं RC, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सलाहकार तथा भारतीय मसाला क्षेत्र की समिति के सदस्यों ने भाग लिया। समिति ने मसाला क्षेत्र के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों, जैसे मसालों में उपयोग के लिए कीटनाशकों के लेबल दावों का विस्तार और FSSAI के तहत भारत में एथिलीन ऑक्साइड की नियामक स्थिति पर चर्चा की, तथा विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गईं, तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर हैं।

कोडेक्स सेल बैठक के आयोजन, एजेंडा, बैठक के विवरण आदि तैयार करने में सहायता करता है।



निर्यातोन्मुख अनुसंधान

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (ICRI) अपने अनुसंधान प्रयासों को फसल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी, फसल उत्पादन, फसल संरक्षण और फसल कटाई के बाद के अध्ययनों पर केंद्रित करता है। अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र छोटी और बड़ी इलायची दोनों के लिए पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा विश्लेषण, एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करने वाली फसल संरक्षण रणनीतियां थे। इसके अलावा, ICRI अपने अनुसंधान के परिणामों को प्रौद्योगिकियों के रूप में परामर्श सेवाओं, जैव-एजेंट उत्पादन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक-किसान संवाद सत्र, मोबाइल मसाला क्लिनिक, वेबिनार, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और ऑडियो-विजुअल मीडिया और प्रकाशनों के माध्यम से प्रसार जैसी विस्तार गतिविधियों के माध्यम से किसानों और लक्षित समूहों तक पहुंचाता है। स्थायित्व पर जोर देते हुए, ICRI इलायची की खेती में कीटनाशक के उपयोग को न्यूनतम करने के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। इसमें एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM), और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) प्रणालियों के साथ-साथ जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहन दिया गया। अपनी क्षमताओं को और बढ़ाते हुए, ICRI ने मायलाडुमपारा में अत्याधुनिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना की। मसाला किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, राज्य बागवानी मिशन, केरल की सहायता से, ICRI ने काली मिर्च के गुणन के लिए बारह उच्च तकनीक वाले पॉलीहाउस स्थापित किए, जिनमें सिंचाई के लिए स्वचालन के साथ-साथ सापेक्ष आर्द्रता नियंत्रण और खेत में इलायची चूषक नर्सरी भी शामिल है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), रबर बोर्ड, केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) और कीटनाशक निर्माताओं के साथ अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में कई सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए गए।

क) फसल सुधार

अ) छोटी इलायची

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, स्पाइसेस बोर्ड, मैलाडुम्पारा द्वारा विकसित छोटी इलायची की अधिक उपज देने वाली, उत्कृष्ट, जलवायु अनुकूल किस्म, ICRI 10

(ICRI सुगंधा भारती) को कृषि और बागान फसलों पर केरल राज्य किस्म विमोचन समिति द्वारा 12 नवंबर 2024 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित अपनी 29वीं बैठक के दौरान जारी किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉ. बी. अशोक IAS, कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव (कृषि), केरल सरकार ने की। इस किस्म में प्रोस्ट्रैट पैनिकल्स होते हैं जिनकी उपज क्षमता मध्यम प्रबंधन के तहत 3,500-4,000 किलोग्राम/हेक्टेयर तक है। कैप्सूल की शुष्क रिकवरी 23.5 प्रतिशत है। लगभग 80 प्रतिशत सूखे कैप्सूल सात (7) मिमी से बड़े आकार के होते हैं और उनका रंग हल्का हरा होता है। ये पौधे सूखे की स्थिति, बीमारियों, थ्रिप्स और बोरर संक्रमण के प्रति सहनशील हैं। नई किस्म के लगभग साठ प्रदर्शन भूखंड केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के इलायची क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं।

प्रायोगिक उद्देश्य के लिए तथा किसानों को आपूर्ति करने के लिए उत्कृष्ट क्लोनों का ICRI क्षेत्रीय स्टेशन, सकलेशपुर में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। कर्नाटक में जरूरतमंद किसानों को MCC 260- (1000 नग), SHC 1- (500 नग) और SHC 2 - (500 नग) और ICRI 5 - (500 नग) की आपूर्ति की गई।

आ) बड़ी इलायची

बड़ी इलायची के तीन जर्मप्लाज्म, रंभांगे, दारुपट्टी और गोल्सी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों तथा सिक्किम के मंगन जिले से एकत्र किए गए तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBPGR), नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार पासपोर्ट डेटा भी दर्ज किया गया। जर्मप्लाज्म में श्रेष्ठ लक्षणों के मूल्यांकन में, SCC 212 को ब्लाइट रोग के प्रति सहनशील पाया गया। संकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, आठ संकर वंशक्रम विकसित किए गए तथा वर्तमान में वे विकास प्रदर्शन और रोग प्रतिरोधकता के मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, एक स्क्रीनिंग अध्ययन में, जिसमें दस जीनोटाइप को शामिल किया गया था, PEG 6000 (पॉलीइथिलीन

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

ग्लाइकॉल 6000) का उपयोग किया गया। प्रारंभिक अवस्था में, ग्लाइकॉल 6000 में सूखा

ख) जैव

विभिन्न आणविक भारों के पदार्थों का उपयोग किया गया। प्रारंभिक अवस्था में, ग्लाइकॉल 6000 में सूखा

विभिन्न आणविक भारों के पदार्थों का उपयोग किया गया। प्रारंभिक अवस्था में, ग्लाइकॉल 6000 में सूखा

के साथ मौसम चर के संबंध में, तामिलनाडु और केरल के

के साथ मौसम चर के संबंध में, तामिलनाडु और केरल के

के साथ मौसम चर के संबंध में, तामिलनाडु और केरल के

के साथ मौसम चर के संबंध में, तामिलनाडु और केरल के

के साथ मौसम चर के संबंध में, तामिलनाडु और केरल के

के साथ मौसम चर के संबंध में, तामिलनाडु और केरल के

के साथ मौसम चर के संबंध में, तामिलनाडु और केरल के

के साथ मौसम चर के संबंध में, तामिलनाडु और केरल के

के साथ मौसम चर के संबंध में, तामिलनाडु और केरल के

के साथ मौसम चर के संबंध में, तामिलनाडु और केरल के

के साथ मौसम चर के संबंध में, तामिलनाडु और केरल के

के साथ मौसम चर के संबंध में, तामिलनाडु और केरल के



खाद और वर्मीकम्पोस्ट के 1:1:1 मिश्रण के साथ 10 ग्राम वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा के साथ लगाया गया था मूल्यांकन किए गए नौ उपचारों में सर्वश्रेष्ठ पाया गया।

घ) पादप रोगविज्ञान

अ) छोटी इलायची

कवकनाशियों के व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नए अणुओं जैसे; एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 11% + टेबुकोनाज़ोल 18.3%, प्रोपिकोनाज़ोल 13.9% + डाइफेनोकोनाज़ोल 13.9%, पाइडिफ्लुमेटोफेन 6.89% + डाइफेनोकोनाज़ोल 11.49%, कासुगामाइसिन 6% + थिफ्लुज़ामाइड 26%, और हेक्साकोनाज़ोल 4% + ज़िनेब WP 68% का छोटी इलायची के प्रमुख कवक रोगजनकों जैसे फ्यूज़ेरियम ऑक्सीस्पोरम, फाइटोफथोरा मीडी, कोलेटोट्राइकम ग्लोओस्पोरियोइड्स और राइज़ोक्टोनिया सोलानीपर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। परिणामों से पता चला कि एज़ोक्सीस्ट्रोबिन + टेबुकोनाज़ोल, और प्रोपिकोनाज़ोल + डाइफेनोकोनाज़ोल द्वारा सभी परीक्षण सांद्रताओं (0.1, 0.2, 0.3%) में, और हेक्साकोनाज़ोल + ज़िनेब (0.3%) द्वारा भी पी. मीडी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। एज़ोक्सीस्ट्रोबिन + टेबुकोनाज़ोल (0.2% और 0.3%) ने भी एफ. ऑक्सीस्पोरम की वृद्धि को पूरी तरह से रोक दिया था। परिणामों से यह भी साबित हुआ कि एज़ोक्सीस्ट्रोबिन + टेबुकोनाज़ोल (0.3%) और प्रोपिकोनाज़ोल + डाइफेनोकोनाज़ोल (0.2% और 0.3%) ने सी. ग्लोओस्पोरियोइड्स के माइसेलियल विकास को 100 प्रतिशत रोक दिया। आर. सोलानी के मामले में, एज़ोक्सीस्ट्रोबिन + टेबुकोनाज़ोल की सभी सांद्रताओं (0.1, 0.2, 0.3%) से, और प्रोपिकोनाज़ोल + डाइफेनोकोनाज़ोल (0.3%) से पूरा अवरोध प्राप्त हुआ।

नर्सरी की स्थिति में इलायची पर किए गए एक प्रारंभिक अध्ययन से पता चला है कि VAM और ट्राइकोडर्मा युक्त एक जैव-समूह इलायची के फ्यूज़ेरियम विल्ट को नियंत्रित करने में प्रभावी है। जीवाणु जैव-एजेंटों के माध्यम से कीटनाशकों के अपघटन पर अध्ययन के दौरान, इडुक्की जिले के विभिन्न इलाकों से एकत्रित 12 मिट्टी के नमूनों से कुल 34 जीवाणु अलग किए गए, जिनमें कीटनाशक क्लोरपाइरीफोस को अपघटित करने की क्षमता थी। शीर्ष 10 आइसोलेट्स को आगे के अध्ययन के लिए चुना गया।

फ्यूज़ेरियम ऑक्सीस्पोरम, राइज़ोक्टोनिया सोलानी और कोलेटोट्राइकम ग्लोओस्पोरियोइड्स जैसे प्रमुख रोगजनकों

में रोधक गतिविधि का अध्ययन करने के लिए छोटी इलायची के फिलोस्फीयर और राइजोस्फीयर से दस जीवाणु आइसोलेट्स प्राप्त किए गए थे।

टी. हरजियानम का हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फार्मूलेशन विकसित किया गया, जो बीजाणुओं को छह महीने तक रोके रख सकता है। इससे अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए मात्रा में कमी होने से परिवहन लागत में कमी आएगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएस एचएयू), हिसार में आयोजित अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीएस) की 35वीं वार्षिक समूह बैठक (एजीएम) के दौरान दो प्रौद्योगिकियां जारी की गईं, जिनमें इलायची के प्रकंद में सड़न और पत्ती झुलसा के नियंत्रण के लिए कवकनाशी का उपयोग होता है।

आ) बड़ी इलायची

बड़ी इलायची में रोग की घटना का आकलन व्यवस्थित निगरानी के माध्यम से किया गया। काबी और पंगथांग में ICRI के फार्मों में निश्चित भूखंड सर्वेक्षण किया गया। कोलेटोट्राइकम ब्लाइट (Colletotrichum blight), रस्ट और फ्यूज़ेरियम ड्राई रॉट जैसी प्रमुख बीमारियों का प्रकोप दर्ज किया गया। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में किसानों के खेतों पर भी सर्वेक्षण किए गए। रोगग्रस्त और लक्षणयुक्त नमूने एकत्र किए गए, तथा संबंधित रोगजनक सूक्ष्मजीवों को पहचान के लिए अलग किया गया। फफूंदजनित रोगजनकों पर उनकी प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए स्वदेशी लाभकारी सूक्ष्मजीवों (आईबीएम) का पृथक्करण, रखरखाव, तथा इन विट्रो और इन विवो दोनों प्रकार की जांच की गई। भारत के प्रमुख बड़ी इलायची उत्पादक क्षेत्रों में विषाणुजनित रोगों, विल्ट और फ्यूज़ेरियम शुष्क सड़न पर व्यापक सर्वेक्षण किए गए। पंगथांग फार्म में ट्राइकोडर्मा एसपीपी., स्यूडोमोनास एसपीपी., मेटारिज़ियम एसपीपी., और बेउवेरिया एसपीपी. जैसे जैव एजेंटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया।

ड) कीटविज्ञान

अ) छोटी इलायची

एन्टोमो पैथोजेनिक नेमाटोड (ICRI EPN -18) (गैलेरिया कैडेवर्स) का बड़े पैमाने पर उत्पादन जारी रखा गया। इलायची की जड़ की इल्लियों के जैविक प्रबंधन के लिए, ICRI फार्म, मायलाडुम्परा और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (RRS), गंगटोक, सिक्किम के अलावा, केरल और

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

तमिलनाडु के किसानों का...
...की आपूर्ति की गई।

...की...
...अणु...

तमिलनाडु...
SG का म...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...

...में...
...में...



किसान सेवा केंद्र का उद्देश्य मसाला किसानों को सहायता और कृषि क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों का समाधान प्रदान करना है।

मसाला उत्पादकों के लाभ के लिए ICAR- IISR, कोझिकोड से विभिन्न जैव नियंत्रण एजेंटों और रोपण सामग्री की ICRI-किसान सेवा केंद्र के माध्यम से आपूर्ति की सुविधा के लिए स्पाइसेस बोर्ड और ICAR- IISR के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ICRI क्षेत्रीय स्टेशन, सकलेशपुर ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान छोटी इलायची (2964 नग) और काली मिर्च (366 नग) की रोपण सामग्री की आपूर्ति की। किसानों को जैव एजेंट अर्थात ट्राइकोडर्मा तरल (577 लीटर), ट्राइकोडर्मा ठोस (416 किलोग्राम) और स्फ्यूडोमोनास तरल (981 लीटर) भी उपलब्ध कराए गए।

आ) बड़ी इलायची

वर्ष 2024-25 के दौरान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में बड़ी इलायची के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए नौ मसाला क्लीनिक आयोजित किए गए। कृषि परामर्श सेवा के एक भाग के रूप में, 162 बड़ी इलायची के खेतों का दौरा किया गया, तथा बागान सुधार के लिए आवश्यक कृषि परामर्श प्रदान किए गए। ICRI-क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, गंगटोक ने कृषि अभियांत्रिकी एवं फसल कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय) में एक प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां बड़ी इलायची में अनुसंधान गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

च) फसल कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकी

अ) छोटी इलायची

फसल कटाई के बाद के अध्ययनों से पता चला है कि एआई-सहायता प्राप्त रंग छंटाई अधिक वजन और अधिक संख्या में बीजों वाले कैप्सूलों को प्रभावी ढंग से अलग करती है, जिससे बहुत कम समय में प्रीमियम गुणवत्ता की निगरानी और ग्रेडिंग समाधान सुनिश्चित होता है।

शोध अध्ययनों ने फसल कटाई के बाद की प्रक्रियाओं जैसे कि पूर्व-उपचार प्रक्रिया के दौरान धुलाई और पॉलिशिंग के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे इलायची के कैप्सूल के भौतिक (थोक घनत्व ग्राम/लीटर) और रासायनिक गुणवत्ता (सुगन्धित तेल (%), ओलियोरेंजिन (%)) मापदंडों में वृद्धि हुई और एसिड अघुलनशील राख सामग्री

में महत्वपूर्ण कमी आई। अध्ययनों से साबित हुआ है कि NPK के साथ-साथ द्वितीयक पोषक तत्वों का संतुलित अनुप्रयोग बेहतर भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता पहलुओं के साथ इलायची कैप्सूल के उत्पादन के लिए आवश्यक है।

आ) बड़ी इलायची

बड़ी इलायची कैप्सूल के बेहतर शेल्फ जीवन के लिए उपचार के रूप में बोरियों, पॉलिथीन-लाइन वाले बैग और वायुरोधी भंडारण बैग का उपयोग करके बेहतर भंडारण और विभिन्न पैकिंग सामग्रियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि और प्रत्येक पैकेजिंग सामग्री की सापेक्ष संरक्षण क्षमता का आकलन करने के लिए तीन महीने के अंतराल पर कवक और जीवाणु आबादी की आवधिक गणना की गई। अध्ययन जारी है, तथा गुणवत्ता बनाए रखने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त पैकिंग विधि निर्धारित करने हेतु डेटा विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है।

छ) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कीटनाशक अवशेष सामग्री की पहचान और मात्रा निर्धारण के लिए 5092 मापदंडों के आधार पर छोटी इलायची के कुल 106 नमूनों का विश्लेषण किया गया। नमूनों में फार्म गेट स्तर पर सलाहकार सेवा (52 नग) और फार्म गेट स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी के लिए अनुसंधान नमूने (54 नग) शामिल थे। किसी भी नमूने में कीटनाशक की मात्रा सऊदी अरब और जापान के लिए निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) से अधिक नहीं पाई गई। विश्लेषण करने पर पाया गया कि ICRI द्वारा जारी छोटी इलायची की किस्मों में जैव रासायनिक गुणों के तुलनात्मक अध्ययन में फ्लेवोनोइड्स, फिनोल और टेपीन जैसे फाइटोकेमिकल घटकों में स्पष्ट भिन्नता पाई गई।

ज) बाहर से वित्तपोषित परियोजनाएँ

अ) छोटी इलायची

‘छोटी इलायची के प्रमुख कीटों पर नए अणु आईएसओसाइक्लोसीरम 10% w/v DC (100 DC) की जैव-प्रभावशीलता का मूल्यांकन’ नामक एक बाहर से वित्त पोषित परियोजना को मेसर्स सिंजेन्टा इंडिया लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के सहयोग से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए ₹ 18.00 लाख की मंजूरी दी गई थी।



सूचना प्रौद्योगिकी और इलक्टॉनिक डाटा प्रक्रमण

सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ के साथ स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों में काफी बदलाव आया है। कई मैनुअल संचालन को ऑनलाइन सिस्टम से बदल दिया गया जो बोर्ड के विभिन्न विभागों के कार्यभार को प्रभावी ढंग से कम किया और संचालन के समय को भी कम किया। ईडीपी विभाग उनके साथ काम करके बोर्ड के विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। वास्तव में, यह पूरी प्रणाली को तेज और अधिक उत्पादी बनाता है और बोर्ड को अधिक कुशलता से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है।

क. ईडीपी विभाग की मुख्य गतिविधियाँ

1. सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए बोर्ड के विभिन्न विभागों और कार्यालयों को सलाह देना, उनका माग्रदर्शन और सहायता करना।
2. मौजूदा एप्लिकेशन, मैसेजिंग समाधान, इंटरनेट और वेबसाइट रखरखाव के लिए हेल्प डेस्क प्रबंधन।
3. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और परिधीय उपकरण जैसे संगठन के व्यापक आईटी संसाधनों का प्रशासन।
4. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, एकीकरण और कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार करना।
5. आईटी अवसंरचना का उन्नयन।
6. आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर के सुचारु कामकाज के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को परिभाषित और कार्यान्वित करना।

7. डेटा प्रोससिंग

8. नए सिस्टम (या मौजूदा सिस्टम में संशोधन) की आवश्यकता की पहचान करना और उपयोगकर्ताओं के अनुरोधों का जवाब देना।
9. सूचना प्रणाली और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की डिजाइन, विकास, प्रलेखन, परीक्षण, कार्यान्वयन और रखरखाव।
10. बोर्ड की वेबसाइट indianspices.com, spicesboard.in, indianspices.org.in, worldspicecongress.com एवं ccsch.in का रखरखाव और अद्यतनीकरण।
11. कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार और संचालित करना।

ख. वर्ष 2024-25 की प्रमुख उपलब्धियाँ

- ❖ निर्यात सहायता प्रणाली (ईएसएस) में ऑनलाइन बैच भुगतान सुविधा।
- ❖ निर्यात सहायता प्रणाली (ईएसएस) से गुणवत्ता दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (क्वाडमास) तक एपीआई के माध्यम से सूचना विवरणों का एकीकरण।
- ❖ एपीआई के माध्यम से एकल साइन-ऑन की सुविधा के लिए आईसीईगेट के साथ निर्यात सहायता प्रणाली (ईएसएस) का एकीकरण।





भविष्य की ओर

मसालों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध भारत, मसालों और मसाला उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में 75 से अधिक विशिष्ट मसालों की खेती के साथ, भारतीय मसालों का निर्यात 180 से अधिक देशों में किया जाता है, जिसमें 225 से अधिक अनूठे उत्पाद शामिल हैं। सदियों से, भारत ने खुद को विविध प्रकार के मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया है। यह क्षेत्र भारत के कुल कृषि निर्यात में लगभग नौ प्रतिशत और बागवानी निर्यात में 41 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।

देश की कृषि -जलवायु विविधता लगभग हर राज्य में मसाला उत्पादन को संभव बनाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत ने लगभग 12 मिलियन मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन किया और 1.80 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक का निर्यात किया, जो कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत है। मसाला बोर्ड के हस्तक्षेप से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 1987 के 229.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 4.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में, मसाला निर्यात में मात्रा के हिसाब से 17 प्रतिशत, रुपये के हिसाब से मूल्य में आठ प्रतिशत और डॉलर के हिसाब से छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2024-25 के बीच, भारत के मसाला निर्यात में मात्रा में 101 प्रतिशत, रुपये के मूल्य में 168 प्रतिशत और डॉलर के मूल्य में 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें मात्रा में 7 प्रतिशत, रुपये के मूल्य में 10 प्रतिशत और डॉलर के मूल्य में 7 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई।

वैश्विक मसाला और मसाला उद्योग परंपरा और नवाचार के संगम पर स्थित है। सदियों पुरानी पाक-कला पद्धतियों में दृढ़ता से निहित होने के बावजूद, यह क्षेत्र आधुनिक स्वास्थ्य रुझानों, बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता और वैश्वीकरण के अनुरूप तेजी से विकसित हो रहा है। यह परिवर्तन बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं, लगातार बदलते अंतर्राष्ट्रीय नियमों, जलवायु संबंधी चुनौतियों और तेजी से बढ़ती तकनीकी प्रगति द्वारा आकार ले रहा है। ये रुझान भारतीय मसाला उद्योग के लिए

गुणवत्ता, प्रामाणिकता, स्थिरता और पारदर्शिता पर अपना ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं ताकि उभरते अवसरों का सफलतापूर्वक दोहन किया जा सके और संबंधित चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

जैसे-जैसे पारंपरिक स्वादों, कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और स्वच्छ-लेबल उत्पादों की वैश्विक उपभोक्ता मांग बढ़ रही है, प्राकृतिक, स्वास्थ्यवर्धक सामग्रियों का बाजार भी लगातार विस्तार कर रहा है। हालाँकि, इस क्षेत्र को मिलावट, लेबलिंग में विसंगतियाँ, बदलते नियामक ढाँचे, नैतिक स्रोत, खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ आदि जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत के वैश्विक नेतृत्व को बनाए रखने और मज़बूत करने के लिए, मसाला उद्योग को एक दूरदर्शी रणनीति अपनानी होगी जो निर्यात संवर्धन, तकनीकी उन्नति और समावेशी, सतत विकास पर केंद्रित हो। गुणवत्ता, पता लगाने की क्षमता और स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले निर्यातकों को इस उभरते बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की संभावना है।

भारत ने वैश्विक स्थिरता मानदंडों के साथ तालमेल बिठाने की अनिवार्यता को समझते हुए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सक्रिय कदम उठाए हैं। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के आठवें संस्करण का शुभारंभ, सतत कृषि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एनपीओपी के अंतर्गत अद्यतन दिशानिर्देश जैविक उत्पादन और प्रसंस्करण में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारतीय जैविक मसाले गुणवत्ता, सुरक्षा और उपभोक्ता विश्वास के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते रहें।

हालाँकि, लगातार चुनौतियाँ बनी हुई हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला में सामाजिक स्थिरता हासिल करने में। भारत के मसालों का एक बड़ा हिस्सा छोटे किसानों द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिनमें से कई वित्तीय तंगी का सामना करते हैं और बुनियादी ढाँचे और कटाई के बाद की सुविधाओं तक उनकी पहुँच नहीं है। पर्याप्त संस्थागत समर्थन के बिना, ये किसान रासायनिक पदार्थों का सहारा ले सकते हैं या अधिक लाभदायक फसलों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे स्थायी रूप से उगाए गए, उच्च

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

गुणवत्ता वाले मसालों की उपलब्धता के लिए, पारंपरिक कृषि पद्धतियों में सुधार और आधुनिक तकनीक तैयार करने के लिए प्रदान करने के लिए प्रयासों पर ध्यान देना और प्राथमिकता देना आवश्यक है।

स्वरोदार फयरट्रड, रनफरिस्ट अपने देशों के नियामकों के साथ काम करते हैं। भारतीय मसालों के बने रहने के लिए पद्धतियों

के लिए अत्यंत आवश्यक है। विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मसालों के उत्पादन में सुधार और आधुनिक तकनीक तैयार करने के लिए प्रदान करने के लिए प्रयासों पर ध्यान देना और प्राथमिकता देना आवश्यक है।

योंकि उपभोक्ताओं को पसंद आता है। मसालों के स्वाद और सुगंध निभाते हैं, अल्क अपने प्राकृतिक गुणों के कारण उत्पाद के शैली जीवन देते हैं।

हुए, स्पाइसेस बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र के लिए प्रगतिशील, नवीन और (NED) के माध्यम से मसाला क्षेत्र को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत, विश्वव्यापी तंत्र विकसित



1. उच्च-स्तरीय मूल्य संवर्धन को सुगम बनाने और प्रसंस्कृत मसाला निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत के मसाला विनिर्माण बुनियादी ढांचे को उन्नत और मजबूत करके मूल्य संवर्धन क्षमता को बढ़ाना।
 2. निर्यातकों, उद्यमियों, स्टार्ट-अप और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को समर्थन देने के लिए अग्रणी संस्थानों के साथ साझेदारी करके मसाला इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना, निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नवीन विचारों को बाजार के लिए तैयार मसाला उत्पादों और प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने में सहायता करना।
 3. इनक्यूबेशन सहायता, डिजिटलीकरण और आधुनिक प्रसंस्करण उपकरणों को अपनाकर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाना। निर्यात के लिए ट्रेसेबिलिटी और प्रत्यक्ष सोर्सिंग को सुगम बनाने हेतु प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से मसाला उत्पादकों और निर्यातकों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।
 4. बदलती वैश्विक उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुरूप नए मसाला-आधारित उत्पादों और अनुप्रयोगों के विकास का समर्थन करना
 5. संभावित निर्यात बाजारों पर विस्तृत अध्ययन करना तथा नए और मौजूदा दोनों क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार करना।
 6. लक्षित निर्यात गंतव्यों में भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय करके प्रचार अभियान शुरू करना।
 7. वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों और मसाला उत्पादों को अलग पहचान दिलाने के लिए जीआई-टैग वाले मसालों और अद्वितीय भारतीय किस्मों को बढ़ावा देना।
 8. अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम लागू करना तथा वैश्विक नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं को उन्नत करना।
 9. निर्यात-गुणवत्ता वाले मसालों और मूल्य-वर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कटाई के बाद की प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
 10. पूर्वोत्तर क्षेत्र के मसालों, जीआई किस्मों और उच्च आंतरिक मूल्य वाले मसालों के लिए लक्षित कार्यक्रमों को लागू करना, जिसमें आयात प्रतिस्थापन का समर्थन करने की पहल भी शामिल है।
 11. अंतर्राष्ट्रीय बाजार संपर्कों के निर्माण और भारतीय मसालों की लक्षित ब्रांडिंग सहित व्यापार संवर्धन प्रयासों को मजबूत करना।
 12. निर्यात तत्परता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जैव-पूर्वक्षण, जलवायु-लचीले व्यवहार, पेटेंटिंग और नवीन उत्पादों के व्यावसायीकरण जैसे क्षेत्रों में मसाला क्षेत्र को समर्थन देने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान करना।
 13. उभरती वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने, ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ाने और सतत क्षेत्रीय विकास का समर्थन करने के लिए मसाला मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
- खाद्य प्रसंस्करण के वैश्विक रुझान विकसित हो रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिशीलता की सूक्ष्म समझ अत्यंत आवश्यक है। बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और नियामक अपेक्षाओं के साथ उत्पादन को संरेखित करने के लिए किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों और नीति निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। मसाला मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और बढ़ाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय मसाले वैश्विक बाजारों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करें। इन मानकों को बनाए रखने से भारतीय मसालों के लिए एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने में मदद मिलेगी, जो गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास से जुड़ी होगी और इस प्रकार वैश्विक मसाला व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत होगी।



वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समिति के लेखापरीक्षा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

| | |
|-----|----------------------------------|
| अ | |
| अ.1 | उ |
| | 39.1 |
| | ची 3) |
| | चौंके धर्म |
| | प |
| | के वि |
| | भी अ |
| | आय और व्यय खाते में |
| | जाना है धर्म |
| | ही। स |
| | आय और धर्मस्व |
| | था। इस प्रकार, |
| | निधि से प्राप्त |
| | की अ |
| | पहचान नहीं की |
| | के लिए घटा और |
| | धर्मस्व |
| | से प्राप्त परिसंपत्तियों |
| | से नहीं बताया |
| | मुश्किल लगता है। |
| | संपत्तियों |
| | लोक, वर्ष 20 |
| | वधि के दौरान TIES, NHM, |
| | प्राप्त परिसंपत्तियों को धर्मस्व |
| | निधि से प्राप्त |
| | रहा है। |
| | वै |
| | त्मक कार्रवाई नहीं कर सका कि |
| | मुदान और धर्मस्व निधि से प्राप्त |
| | किया जा सका। |
| | अवसंरचना एवं संबद्ध |
| | एवं |



| | <p>अन्य उदाहरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 12 करोड़ के विश्लेषणात्मक शुल्क को आय और व्यय विवरण में आय के रूप में लेखा किए बिना सीधे ही उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों अर्थात पेंशन निधि (10 करोड़ रुपये) और 'मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानक' (2 करोड़ रुपये) (अनुसूची 57 के नोट 1-लेखा पर नोट्स) में अंतरित कर दिया गया।</p> <p>पिछले वर्षों 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में इस विषय में लगातार की गई टिप्पणियों के बावजूद स्पाइसेस बोर्ड ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया है।</p> | <p>गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएल) के अनुरक्षण और रखरखाव के संबंध में, बोर्ड को प्रयोगशालाओं में उपकरणों के नवीनीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय की उम्मीद है, क्योंकि महंगे उपकरणों के अप्रत्याशित रूप से खराब होने से निर्यात खेपों के लिए गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार करने में देरी हो सकती है।</p> <p>निर्यात में गुणवत्ता मानक बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया अपरिहार्य है। बोर्ड को इसके लिए पर्याप्त पूंजीगत व्यय की उम्मीद है, इसलिए प्रयोगशालाओं के नियमित व्यय के लिए नहीं, बल्कि इन खर्चों को पूरा करने के लिए धनराशि निर्धारित की जा रही है।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|--------|----------------|-----|---|--------|-------|-------|--------|-----------------------------------|--------|-------|-------|--------|---|-------|---------|---------|-------|--|
| <p>अ.1.2</p> | <p>चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान - प्रावधान: ₹ 325.37 करोड़ (अनुसूची 7ख)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>i) स्पाइसेस बोर्ड ने कर्मचारी संबंधी देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन किया और 31-03-2021 तक 348.72 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंचा, जिसके लिए उसने 31-03-2025 तक 325.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जैसा कि नीचे निर्धारित है:</p> <table border="1" data-bbox="279 1066 815 1470"> <thead> <tr> <th></th> <th>पेंशन</th> <th>उपदान</th> <th>छुट्टी नकदीकरण</th> <th>कुल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जैसा कि 31-03-2021 को है बीमांकिक मूल्य</td> <td>319.07</td> <td>18.54</td> <td>11.10</td> <td>348.72</td> </tr> <tr> <td>जैसा कि 31-03-2025 को है प्रावधान</td> <td>272.21</td> <td>29.70</td> <td>23.40</td> <td>325.31</td> </tr> <tr> <td>31-03-2021 के मूल्यांकन के संबंध में कमी (अधिकता)</td> <td>46.86</td> <td>(11.16)</td> <td>(12.30)</td> <td>23.41</td> </tr> </tbody> </table> | | पेंशन | उपदान | छुट्टी नकदीकरण | कुल | जैसा कि 31-03-2021 को है बीमांकिक मूल्य | 319.07 | 18.54 | 11.10 | 348.72 | जैसा कि 31-03-2025 को है प्रावधान | 272.21 | 29.70 | 23.40 | 325.31 | 31-03-2021 के मूल्यांकन के संबंध में कमी (अधिकता) | 46.86 | (11.16) | (12.30) | 23.41 | <p>लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट कर ली गई है।</p> |
| | पेंशन | उपदान | छुट्टी नकदीकरण | कुल | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जैसा कि 31-03-2021 को है बीमांकिक मूल्य | 319.07 | 18.54 | 11.10 | 348.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जैसा कि 31-03-2025 को है प्रावधान | 272.21 | 29.70 | 23.40 | 325.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31-03-2021 के मूल्यांकन के संबंध में कमी (अधिकता) | 46.86 | (11.16) | (12.30) | 23.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>बीमांकिक देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ और घाटे के लिए प्रावधान वर्ष के लिए ₹ 23.41 करोड़ (निवल) कम दर्शाए गए हैं।</p> <p>ii) लेखा मानक 15 (पैरा 58) के अनुसार, परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का विस्तृत बीमांकिक मूल्यांकन तीन वर्ष से अधिक के अंतराल पर नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, अंतिम बीमांकिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 में किया गया था, अर्थात् 31-03-2025 तक अवधि तीन वर्ष से अधिक हो गई है।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| <p>अ.2.1</p> | <p>चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, और अन्य वित्तीय धारणाएँ। चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, और अन्य वित्तीय धारणाएँ। चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, और अन्य वित्तीय धारणाएँ।</p> | <p>अनुसूची - 1</p> |
| | <p>से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अग्रिमों का ब्यौरा पता देना शुरू किया है। अग्रिमों का ब्यौरा पता देना शुरू किया है। अग्रिमों का ब्यौरा पता देना शुरू किया है।</p> | <p>की 1</p> |



| | | |
|----|--|--------------------------------------|
| इ. | प्राप्ति और अदायगी लेखा - शून्य | |
| ई. | लेखांकन नीतियाँ - शून्य | |
| उ. | सामान्य - शून्य | |
| ऊ | <p>प्रबंधन पत्र जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।</p> | लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट की गई है। |
| ऋ | <p>(i) आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता बैंकों के चालू खातों के अधीन वर्गीकृत 85 खातों में से, शेष पुष्टीकरण के 41 मामले (10,56,60,233.60 रुपए) ऐसे थे जिनमें यह नहीं बताया गया था कि यह चालू खाता है या बचत बैंक खाता। शेष पुष्टीकरण के 11 मामले (95,55,445 रुपए की राशि) बचत खाते के रूप में दिखाए गए हैं। जैसे कि 31 मार्च, 2025, को है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हैदराबाद शाखा की बही शेष 53,083 रुपए रहा जबकि बैंक पुष्टीकरण के अनुसार शेष 8,377 रुपए था। शेष राशि का समाधान नहीं किया गया था।</p> | लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट की गई है। |
| | <p>(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान स्पाइसेस बोर्ड के 82 शाखा कार्यालयों तथा मुख्यालय में से किसी में भी आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं चलाई गई है। इस मुद्दे को भी वर्ष 2023-24 की पृथक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में सूचित किया गया था।</p> | लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट की गई है। |
| | <p>(iii) स्थिर परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी सभी 83 इकाइयों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है।</p> | |
| | <p>(iv) मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन और मूल्यांकन किया है।</p> | केवल टिप्पणी |
| | <p>(v) सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता: बोर्ड ने जी एस टी, टीडीएस, सी पी एफ आदि जैसे सभी सांविधिक देयों को नियमित रूप से जमा किया है।</p> | केवल टिप्पणी |

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

| | | |
|---|--|--|
| | (vi) इकाई के कामकाज से संबंधित मामले | |
| ए | संश्लेषण के तहत भारत सरकार के विभागों के कार्यों का निष्कर्षण कि | संश्लेषण के तहत भारत सरकार के विभागों के कार्यों का निष्कर्षण कि |

IN PICTURES SPICES BOARD 2024-25



Visit of the Hon'ble Minister for Commerce and Industry



Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India welcomed by Smt. P. Hemalatha IAS, Secretary Spices Board for the stakeholder interaction on 21st February 2025.



Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India interacting with the spice industry stakeholders



A view of the stakeholders attending the interactive session with Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India

Interactive Session with Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry



Shri Jitin Prasada, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry addressing the FPO/FPC stakeholders involved in the Saffron Value Chain in Jammu and Kashmir on 11th July 2024



A view of the saffron stakeholders attending interactive session with Shri Jitin Prasada, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry



A glimpse of the stakeholder interaction held on 11th July 2024 in Jammu and Kashmir

Chintan Shivir



Inauguration of the 'Chintan Shivir' on spices organised during 09-10 May 2024 at Munnar, Kerala by lighting the lamp



Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Chairman, Spices Board addressing the stakeholders of the 'Chintan Shivir' on spices



Interactive session during the 'Chintan Shivir'



A view of the participants attending the 'Chintan Shivir' on spices at Munnar, Kerala



Participants of the common 'Chintan Shivir' organised by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and the Plantation Boards at Coorg in Karnataka during 22 -23 May 2024



A glimpse of the brainstorming session at the common 'Chintan Shivir' organised during 22 -23 May 2024

Inauguration of National Turmeric Board



Shri Arvind Dharmapuri, MP, Nizamabad garlanding Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India during the inauguration of the National Turmeric Board on 14th January 2025



Shri Palle Ganga Reddy, Chairperson, National Turmeric Board lighting the lamp during the inauguration of the National Turmeric Board at Nizamabad, Telangana



Ms Kesang Yangzom Sherpa IRS, Joint Secretary, Department of Commerce addressing the gathering during the inauguration of the National Turmeric Board



Smt. P. Hemalatha IAS, Secretary Spices Board addresses the audience during the inauguration of the National Turmeric Board



View of the turmeric farmers and other stakeholders assembled to witness the inauguration of the National Turmeric Board

Partnerships for Synergy



India taking over the Chairmanship of the International Pepper Community during its 52nd Annual Session and Meetings



Smt. P. Hemalatha IAS, Secretary Spices Board addressing the participants of the 52nd Annual Session and Meetings of the International Pepper Community



A view of the participants attending the 52nd Annual Session and Meetings of the International Pepper Community



Shri B.N. Jha, Director, Spices Board attending the 10th meeting of the IPC Committee on Marketing



Dr. A.B. Rema Shree, Director, Spices Board chairs the 32nd Meeting of ISO/TC34/SC7 at AFNOR, Paris during 18-20 June 2024

Partnerships for Synergy



Signing and exchange of MoU between ICRI, Spices Board and ICAR-IISR, Kozhikode in connection with the establishment of ICRI- Kisan Seva Kendra



Shri Takayuki Hagiwara, FAO representative in India along with the FAO India team interacting with Spices Board officials on 25th June 2024, at Spices Board Head Office in Kochi



Memorandum of understanding signed between Indian Cardamom Research Institute, Spices Board and NIC, Kolkata on 3rd July 2024 for developing AI based detection of large cardamom diseases



The third session of the National Committee on Spices Quality and Safety (NCSQS3) was held on 24th October 2024



Signing of MoU between Spices Board and Directorate of Horticulture and Food Processing, Govt. of Uttarakhand for promotion of spices

Export Development & Promotion



Inauguration of the Buyer Seller Meet for Byadagi Chilli and Turmeric organised at Hubballi, Karnataka on 25th November 2024



Inauguration of the outreach programme on opportunities for growth in spices, tea and coffee for farmers of Uttarakhand on 21st December 2024



Shri Nyato Dukam, Hon'ble Minister for Commerce & Industry, Labour & Employment, Information & Public Relations, & Printing, Govt of Arunachal Pradesh attending the Buyer Seller Meet for Spices at Itanagar on 23rd January 2025



Participants attending the Buyer Seller Meet for Spices at Itanagar on 23rd January 2025



Dr A. B. Rema Shree, Director, Spices Board addressing the participants of the International Conclave cum Buyer Seller Meet on Spices at Aizawl, Mizoram



Shri B.N. Jha, Director, Marketing interacting with officials of Singapore Food Agency (SFA) on strengthening direct connections and updating on the EtO issue

Export Development & Promotion



Inauguration of the Buyer Seller Meet for Spices in Uttarakhand at Haldwani on 22nd August 2024



Shri B.N. Jha, Director, Spices Board addressing the participants of the Buyer Seller Meet for Spices in Odisha held on 7th December 2024 at Bhubaneswar, Odisha



Glimpse of the Buyer Seller Meet for Saffron and Temperate Spices held on 12th December 2024 at Srinagar, Jammu and Kashmir



Inauguration of the Buyer Seller Meet for Spices held at Ranchi, Jharkhand on 28th January 2025



Shri Palle Ganga Reddy, Chairperson, National Turmeric Board inaugurating the Buyer Seller Meet for Turmeric with Focus on Telangana on 18th March 2025 at Nizamabad



Ms P. Hemalatha IAS, Secretary, Spices Board visited Spices Park, Guna and interacted with stakeholders

Export Development & Promotion



Spices Board's pavilion at Biofach India 2025 held during 3-5 August 2024 at India Exposition Mart Ltd (IEML), Greater Noida, Delhi – NCR



Smt. Kesang Yangzom Sherpa IRS, Joint Secretary, Ministry of Commerce and Shri Neeraj Gaba, Director (Plantations), Ministry of Commerce at Spices Board's pavilion in India International Trade Fair held during 14-27 November 2024 at New Delhi



Spices Board's pavilion at Food Ingredients Europe held during 19-21 November 2024 at Frankfurt, Germany



Spices Board's pavilion at Fine Food Australia held during 2-5 September 2024 at Melbourne, Australia



Inauguration of Spices Board's pavilion in International Food and Drink Event, London during 17-19 March 2025



Shri B. N. Jha, Director, Spices Board interacting with Shri Siby George, Ambassador of India to Japan during Foodex Japan 2025 held during 11-14 March 2025



Shri T. Nandakumar, Consul General, Consulate General of India, Shanghai at Spices Board's pavilion at Shanghai International Condiment and Food Ingredients Exhibition 2024



Glimpse of the Reverse Buyer Seller Meet organised as part of the Board's participation in Shanghai International Condiment and Food Ingredients Exhibition 2024 at Shanghai, China



Glimpse of the reverse buyer seller meet organised as part of Spices Board's participation in World Food Moscow 2024



Inauguration of Spices Board's pavilion at World Food Moscow held during 17-20 September 2024 in Moscow, Russia



Visit of Shri Chirag Kumar Paswan, Honorable Minister of Food Processing Industries to Spices Board pavilion at World Food India 2024.



Spices Board's stall in Indus Food during 8-10 January 2025 at India Expo Mart, Greater Noida.

Export Development & Promotion



A glimpse of 'Spice Up Your Business: Stakeholders' Conclave and Buyer Seller Meet on Spices' held at ICRI, Myladumpara on 11th September 2024



Participants attending the 'Stakeholders' Conclave and Buyer Seller Meet on Spices' held at ICRI, Myladumpara on 11th September 2024



Inauguration of the SCSP Farmers Training on Good Agricultural Practices in Black Pepper and Small Cardamom held at ICRI, Myladumpara on 11th March 2025



Glimpse of the workshop on Marketing of Branded Spices for FPOs organised in collaboration with Indian Institute of Plantation Management, Bengaluru



Inauguration of the Food Safety Training and Market Linkage Programme on Turmeric held at Chennai, Tamil Nadu on 24th March 2025



Inauguration of the Food Safety Training and Market Linkage Programme on Turmeric held at Shillong, Meghalaya on 26th March 2025

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement



Assistance for installation of primary processing unit for garlic by M/s Lahsun Farmer Fed Krishi Producer Company at Baran, Rajasthan



Assistance for installation of spice cleaner/grader by M/s Farmer Leaf Krishi Producer Company at Amapura, Rajasthan



Participants of the Regional Workshop on Seed Spices for establishing arrangement between spice exporters and FPO under STDF project at Jodhpur



Honouring of Ms Kesang Yangzom Sherpa IRS, Joint Secretary, Department of Commerce during the Meeting with Spices Stakeholders in Raebareli, Uttar Pradesh



Clean & Safe Spices Campaign organised on 26th February 2025

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement



A view of the Regional Level Workshop on Seed Spices under the STDF Project at Mehsana, Gujarat on 25th July 2024



Glimpse of the stakeholders meet held on 2nd September 2024 at ICRI Myladumpara to explore the modalities of weather based crop insurance scheme for small cardamom under PMFBY



Orientation session conducted for the 65th batch of trainees from the Diploma in Agriculture Marketing under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare



Field visit of pepper farmers from Andhra Pradesh to University of Agricultural Sciences, Bangalore



Project results dissemination workshop organised on 27th September 2025 at New Delhi on the project Strengthening Spice Value Chain in India and Improving Market Access through Capacity Building and Innovative Interventions

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement



Extension advisory service extended to small cardamom farmers at Lower Palani Hills in Tamil Nadu



Extension advisory service for large cardamom farmers in Sikkim



Capacity Building Programme on turmeric at Nizamabad, Telangana



Quality Improvement Training Programme for saffron in Jammu and Kashmir



Quality Improvement Training Programme for chilli in Guntur, Andhra Pradesh



Quality Improvement Training Programme on seed spices in Gujarat



Outreach Programmes for Production & Quality Improvement



Planting material production through Certified Nurseries for large cardamom in West Bengal



Planting material production of black pepper through Departmental Nursery at Yeslur, Karnataka



Replanting of large cardamom in Sikkim



Replanting of small cardamom in Idukki, Kerala



Exposure visit of farmers and FPO members from Guna, Madhya Pradesh to spices processing units in Rajasthan



Assistance extended for procurement of turmeric boiler at Satara, Maharashtra

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement



GI Saffron Mela cum Awareness Programme organised for the promotion of GI Saffron at Jammu and Kashmir



Financial assistance given for installing gravity separator for pepper in Uttara Kannada district of Karnataka



Financial assistance for installing improved cardamom curing device



Assistance for installation of pepper thresher in Karnataka



Assistance for installation of turmeric polisher in Telangana

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement



Assistance for on farm production of compost for large cardamom in Sikkim



Assistance for installation of pepper thresher at Paderu, Andhra Pradesh



Assistance for installation of polisher in Kerala



Assistance for installation of turmeric polisher at Hingoli, Maharashtra



Assistance for installation of seed spice thresher at Guna, Madhya Pradesh



Assistance for installation of seed spice thresher at Barmer, Rajasthan

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement



Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, former Chairman of the Spices Board and Additional Secretary (Plantations), Government of India visiting ICRI Sugandha Bharathi demonstration plot at Chinnakanal



Assistance for installation of turmeric boiler at Nizamabad, Telangana



On farm advisory services through Spice Clinic programme of Spices Board



Assistance for installation of spice cleaner/grader given to M/s Risch Return Krishi producer company at Anta, Rajasthan



Input distribution to large cardamom farmers under AICRPS project

General Administration



76th Republic Day Celebration at Spices Board
on 26th January 2025



International Yoga Day celebration at Spices Board
on 21st June 2024



Observation of Rashtriya Ekta Diwas on 31st October 2024



Observation of Swachhta Hi Sewa Campaign at ICRI
Myladumpara



Observance of World Blood Donor Day on 14th June 2024

General Administration



Release of handbooks on Good Agricultural Practices and Good Hygienic Practices for black pepper, cumin, fennel and coriander during the 38th Anniversary Celebration of Spices Board



Glimpse of Spices Board's 38th Anniversary Celebration on 26th February 2025



Special sales counter opened for organic spices at the Spices India outlet of Flavourit Spices Trading Limited at Cochin



International Women's Day celebration at Spices Board



Observance of Fit India Mission at Spices Board as part of International Women's Day celebration



Observance of Fit India Mission at Spices Board as part of International Women's Day celebration

BOARD MEMBERS



Shri Amardeep Singh Bhatia IAS
Chairman
(12-07-2023 to 10-10-2024)



Shri L. Satya Srinivas IRS
Chairman
(11-10-2024 to 31-03-2025)



Dr KG Jagadeesha IAS
Secretary
18-03-2024 to 23-10-2024



Ms. P. Hemalatha IAS
Secretary
24-10-2024 to 31-03-2025



Ms S. Jothimani MP
Member of Parliament



Shri Ramesh Chandappa Jigajinagi MP
Member of Parliament



Shri S. Thirumurugan
Member



Shri Chandrasekhar Singh Raghuvanshi
Member



Shri S.K. Sathyanarayana
Member



Shri Gautam Ghosh
Member



Shri Akkiseti Baburao
Member



Shri Rajesh Kumar Mishra IRS
Member
Indian Institute of Packaging
Mumbai



Dr R. Dinesh
Member
ICAR-Indian Institute of
Spices Research, Kozhikode



Dr Neelam Patel
Senior Advisor (Agriculture),
NITI Aayog



Dr Atya Nand
Member
Director, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi

Member
CSIR - Central Food Technological
Research Institute (CFTRI)

Number of vacant positions - 15

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring transparency and accountability in financial matters.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to ensure the validity of the results.

3. The third part of the document describes the different types of data that are collected and analyzed. It includes information on both quantitative and qualitative data, as well as the various sources from which the data is gathered.

4. The fourth part of the document discusses the various statistical methods and techniques used to analyze the data. It covers topics such as descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis.

5. The fifth part of the document describes the different types of reports and documents that are generated from the data analysis. It includes information on how to present the results in a clear and concise manner, as well as the various formats and styles that are commonly used.

6. The sixth part of the document discusses the various challenges and limitations associated with data collection and analysis. It highlights the need for careful planning and execution to ensure that the data is accurate and reliable.

7. The seventh part of the document describes the different types of software and tools that are used to collect and analyze data. It includes information on the various options available, as well as the pros and cons of each.

8. The eighth part of the document discusses the various ethical considerations and standards that must be followed when collecting and analyzing data. It emphasizes the need for transparency and accountability in all aspects of the data collection and analysis process.

9. The ninth part of the document describes the different types of data visualization techniques that are used to present the results. It includes information on the various options available, as well as the pros and cons of each.

10. The tenth part of the document discusses the various applications and uses of the data analysis results. It highlights the need for careful interpretation and communication of the results to ensure that they are understood and used effectively.



Promoting Heritage, Hygiene & Health



Spices  India
FLAVOURFULLY YOURS

Now open at:

Spices India
Lulu Mall, Edapally,
Kochi-682 024, Kerala
Tel: 0484-4073489

Compiled and Edited by:

Shri Nithin Joe

Deputy Director

Shri Kanagadhileepan K.

Assistant Director

Shri Biju D. Shenoy

Assistant Director

Ms Reshmi E.G.

Farm Manager

Ms Aneenamol P.S.

Editor

Technical Support:

Shri R. Jayachandran

EDP Assistant

CONTENTS

EXECUTIVE SUMMARY

1. Constitution and Functions
2. Administration
3. Finance and Accounts
4. Export Oriented Production and Post-harvest Improvement of Spices
5. Export Development and Promotion
6. Trade Information Service
7. Publicity and Promotion
8. Codex Cell and Interventions
9. Quality Improvement
10. Export Oriented Research
11. Information Technology and Electronic Data Processing
12. Implementation of Right to Information Act, 2005

Way Forward

Appendix

Paras in Separate Audit Report 2024-25



ANNUAL REPORT 2024-25





EXECUTIVE SUMMARY

Spices Board is the flagship organisation under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India for the development and world-wide promotion of Indian spices. The Board has been spearheading activities for excellence of Indian spices to help the Indian spice industry to attain the vision of becoming the international processing hub and premier supplier of clean and value-added spices and herbs to the industrial, retail and food service segments of the global spices market. The Board has made quality and hygiene as the cornerstones for its development and promotional strategies.

The export of spices and spice products from India crossed an all-time high in FY 2024-25. During FY 2024-25, India exported 17,99,267 MT of spices and spice products valued at ₹39,994.48 crore (4,722.65 million US\$) as compared to 8,93,920 MT valued at ₹14,899.67 crore (2432.84 million US\$) during 2014-15, registering an increase of 101 per cent in volume, 168 per cent in rupee terms of value, and 94 per cent in dollar terms of value. The export of spices registered a CAGR of seven per cent in volume, ten per cent in rupee terms of value, and seven per cent in dollar terms of value since 2014-15.

Indian spice export basket contains 225 spices and spice products which were exported to more than 180 destinations globally during the period under report. During 2024-25, the major contributors in spice export basket in terms of value were chilli (28%), cumin (16%), spice oil & oleoresins (11%), mint products (9%), turmeric (7%), curry powder/paste (5%), small cardamom (4%), ginger and pepper (3%), fennel and coriander (2%), which together contributed to more than 90 per cent to the total export earnings from spices.

The major export destinations for Indian spices during 2024-25 were China (16%), USA (15%), UAE

(9%), Bangladesh (8%), Malaysia (4%), Thailand (3%), UK (3%), Saudi Arabia (3%), Indonesia (3%), Sri Lanka (2%), Germany (2%), Netherlands (2%), Canada (2%), Nepal (2%), Australia (1%), Japan (1%), Russia (1%), Singapore (1%), France (1%), Mexico (1%), Vietnam (1%), Morocco (1%), South Africa (1%), and Korea (1%) which together account for more than 85 per cent of the total export earnings of spices from the country.

In 2024-25, the export of pepper, cardamom (small & large), ginger, turmeric, cumin, celery, fennel, fenugreek, tamarind, spice oils & oleoresins, and curry powder & paste increased both in quantity and value. Though the export of chilli increased 19 per cent in volume in 2024-25, its value declined by nine per cent in rupee terms and 11 per cent in dollar terms. In the case of mint products, despite the decline of one per cent in volume of export, the export value has increased by three per cent in rupee terms and one per cent in dollar terms of value as compared to last year. Export of coriander, declined 44 per cent in volume, 33 per cent in rupee terms and 35 per cent in dollar terms of value while export of nutmeg & mace decreased by eight per cent in volume, 12 per cent in rupee terms, and 14 per cent in dollar terms of value.

During 2024-25, a total of 4,106 Certificates of Registration as Exporter of Spices (CRES) were issued by the Board. Of these, 3,713 certificates were issued to merchant exporters and 393 to manufacturer exporters. The Board has issued 705 Cardamom Dealer Licences, comprising 688 Small Cardamom Dealer Licences and 17 Large Cardamom Dealer Licences. Of these, 130 were issued during 2024-25 which includes 116 Small Cardamom Dealer Licence and 14 Large Cardamom Dealer Licence. Also, at present there are 18 licensed e-auctioneers and four licensed



ANNUAL REPORT 2024-25



manual auctioneers for cardamom. During the FY 2024-25, the Board issued two cardamom e-auctioneer licence for small cardamom and one manual auctioneer licence for large cardamom.

During 2024-25, a total quantity of 23,335 MT of cardamom (small) was sold through e-auction/manual auction with weighted average price of ₹2,575.98/kg. Production of small and large cardamom during 2024-25 was 20,696 MT and 9,552 MT respectively with a productivity of 435.57 kg/ha in small cardamom and 293.33 kg/ha in large cardamom.

The budget approved for the Board during 2024-25 was ₹13,000.00 lakh. An amount of ₹7,153.00 lakh against Grant-in-aid General, Capital Expenditure, Salaries, Other Expenditure and Swachha Bharath; ₹4,200.00 lakh against Grant-in-aid for Subsidies/financial assistance; ₹849.00 lakh against Grant-in-aid for North East Region; ₹249.00 lakh against Grant-in-aid for Scheduled Caste Sub Plan; and ₹549.00 lakh against Grant-in-aid for Tribal Sub Plan were received by the Board from the Government of India during 2024-25. The Board generated a revenue (IEBR) of ₹3,751.59 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the Quality Evaluation Laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of research farms, subscription and advertisement charges, exporters' subscriptions fee, interest on advance, interest on short term deposits, etc., in 2024-25. The total expenditure of the Board during 2024-25 was ₹13,343.85 lakh.

To identify opportunities in key value addition segments in spices, challenges in supply chain, sharing best practices, development of Vision Document 2047 for spices sector and evolving strategies and action plan for increasing the export of spices, Spices Board organised a 'Chintan Shivir' during 09-10 May 2024 at Munnar, Kerala. The programme was inaugurated by Shri Amardeep Singh Bhatia, IAS, Additional Secretary, Department of Commerce, Government of India and Chairman, Spices Board. Senior officers from the Ministry of Commerce and Industry, industry

representatives, and officials from the Spices Board participated in the 'Chintan Shivir' and contributed their insights on ways to address the challenges in the spices sector and devise a roadmap to achieve the goals and vision set for the spices sector by 2047.

Spices Board participated in the Common 'Chintan Shivir', a two-day, closed door, brainstorming session, organised by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and the Plantation Boards at Coorg in Karnataka during 22-23 May 2024. The 'Chintan Shivir' was attended by around 75 senior officers of the Ministry, officers of the four Plantation Boards, exporters, experts, and industry leaders.

An interactive meeting was held by Shri Jitin Prasada, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry with the FPO/FPC stakeholders involved in the Saffron Value Chain in Jammu and Kashmir on 11th July 2024. The Minister visited the Saffron Park wherein the post-harvest processing of saffron was demonstrated.

Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India interacted with the stakeholders of spices sector on 21st February 2025 in a meeting organised at Marine Products Exports Development Authority (MPEDA), Headquarters in Kochi, Kerala. The meeting discussed the challenges and opportunities in the spices sector. Key areas of interaction included strengthening the monitoring of rerouted pepper, advancing value added processing, and expanding organic spice exports. Intercropping of potential spices with other plantation crops, modernising the Quality Evaluation Laboratories, stringent food safety and quality standards fixed by importing countries, especially the European Union, and cultivation of herbal spices in the North East India were also discussed during the meeting.

During 2024-25, Spices Board participated in 18 domestic trade fairs and nine international trade fairs with an aim to promote Indian spices globally. With a view to promote the export of spices and to strengthen linkages for export sourcing of spices,



the Board has been conducting buyer seller meets. Also, to attract, motivate and equip, the progressive stakeholders to enter the spices business, Spices Board has been organising Entrepreneurship Development Training Programmes (EDP) involving participants from across India. During 2024-25, the Board conducted 12 buyer seller meets and four entrepreneurship development training programmes.

Spices Board being responsible for the overall development of cardamom (small and large) in terms of improving production, productivity and quality, implemented various programmes for betterment of the cardamom sector under the SPICED scheme. During 2024-25, through implementing the replanting/new planting programme, financial assistance of ₹366.68 lakh was provided for replanting 746.67 ha of small cardamom benefitting 2670 growers in the states of Tamil Nadu and Kerala and financial assistance of ₹61.99 lakh was provided for replanting 153.7 ha of small cardamom in Karnataka benefitting 364 growers. Financial assistance of ₹265.36 lakh was provided for replanting/new planting 771.18 ha of large cardamom in NE region benefitting 3,472 growers.

During 2024-25, a total of 74,304 cardamom planting materials, 3,84,507 rooted pepper cuttings, and 13,377 pepper nucleus planting materials, and 34,132 cardamom suckers were produced by the five departmental nurseries of the Board in Karnataka region. These planting materials were distributed to 659 growers. Under certified nursery scheme, 216.03 small cardamom units (10,80,500 planting materials) and 342.4 large cardamom units (17,12,050 planting materials) were established with financial assistance of ₹141.77 lakh.

Under the programme 'Development of water sources and focus on micro-irrigation in small cardamom' 78 water storage structures, 53 rainwater storage structures, 67 irrigation pump sets and 22 sprinkler systems were installed benefitting 220 farmers with financial assistance of ₹61.56 lakh. In large cardamom, eight water storage

structures, 16 rainwater harvesting structures and 36 irrigation pump sets were installed benefitting 60 farmers with financial assistance of ₹15.37 lakh.

To protect small cardamom growers against the adverse weather incidences such as deficit or excess rainfall, heat (temperature), relative humidity, etc., which are deemed to adversely affect the production, Spices Board has been implementing a programme of weather based insurance for cardamom (small). The programme provides assistance of 75 per cent of the premium by Spices Board and 25 per cent by the beneficiary. During 2024-25, 670 farmers were enrolled under the programme covering an area of 370 ha with financial assistance of ₹62.22 lakh as the Board's share.

Under the programme for Post-harvest Quality Upgradation of Spices, Spices Board organised GI Saffron Mela cum Awareness Programme during 2024-25 and utilised an amount of ₹1.64 lakh for the promotion of GI Saffron; 42 farmer groups in spices sector were assisted for installing various post-harvest machines with financial assistance of ₹236.32 lakh benefitting 16,186 farmers under the Quality Gap Bridging Group (QGBG) component. Under the component for post-harvest machineries for farmers from remote areas/ NE region/ marginalised communities, SC/ST, major export/ production hub, assistance was provided for installing 66 power operated seed spice threshers, 492 pepper threshers, 84 turmeric boiling units, 153 spices polishing units (cardamom polisher and turmeric polisher), eight mint distillation units, 153 spice cleaners/graders/spiral gravity separators, 39 spices washing machines, ten spice slicing machines, and 320 spice dryers benefitting 1,325 farmers with financial assistance of ₹617.07 lakh.

To promote primary processing and value addition by groups or FPOs in identified clusters to generate an exportable surplus, Spices Board has been extending assistance to FPOs to set up units for primary processing and value addition. During 2024-25, assistance was given to two FPOs in setting up of processing units with financial assistance of ₹15.73 lakh, benefitting 405 growers.



ANNUAL REPORT 2024-25



During 2024-25, 29 improved small cardamom curing devices were set up at financial assistance of ₹34.48 lakh, benefitting 29 growers. In addition, a total of 40 modified bhatti units/sawo dryer were constructed for curing of large cardamom at financial assistance of ₹12 lakh, benefitting 40 growers.

Under the Board's programme for inclusive development for SC/ST communities through spice promotion, the Board has been implementing capacity building through ICAR institutes, SAUs, KVKs, ICRI, and similar institutes. During 2024-25, six such trainings were conducted in various ICAR institutes/KVKs in five states benefitting 183 growers. The programme helps empower the aspiring youth in agriculture/farmers belonging to the SC/ST category, upgrade their knowledge and skill in farming/entrepreneurship, and to create a pool of master trainers among the community.

With the objective of demonstrating and motivating the growers of North Eastern states for cultivation of various spices with intrinsic qualities and GI tag viz., Lakadong turmeric, Naga chilli, Hathei chilli, Mizo chilli, Mizo ginger, Dalley khursani, etc., Spices Board has been implementing a programme under the SPICED scheme. During 2024-25, assistance was provided to 680 farmers of NE states covering 266.6 ha with financial assistance of ₹60.73 lakh.

Under the programme for promotion of sustainable production and certification systems like organic, IndGAP, natural farming, etc., financial assistance of ₹2.49 lakh was provided to three farmer groups during 2024-25 for internal control system; ₹2.03 lakh was provided to three farmer groups for Organic Group Certification; ₹8.05 lakh towards certification assistance for five farmer groups for INDGAP and other sustainable certifications in production; ₹33.68 lakh towards on farm production of composts benefitting 247 farmers; and ₹8 lakh towards the cost of setting up of Care and Cure Centre and inputs procured from authorised sources to five FPOs.

During 2024-25, a total of 14,945 extension visits were made and 2,788 group meetings/campaigns

were organised for cardamom (small and large) in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Kalimpong, and Darjeeling districts of West Bengal, and other spices growing areas. The total expenditure under extension advisory service was ₹114.53 lakh.

Spices Board is regularly conducting Quality Improvement Training Programmes (QITP) for farmers, officials of state agriculture / horticulture departments, traders, members of NGOs, etc., for educating them on scientific methods of pre- and post-harvest and storage technologies and updated quality requirements for major spices. A total of 12,771 personnel were trained under 215 training programmes during 2024-25 at a total expenditure of ₹22.32 lakh.

A campaign on 'Clean and Safe Spices' was conducted on 25 February 2025, commemorating the 38th foundation day of the Board. The campaign was designed to sensitise the stakeholders on the risk, corrective actions, and good practises to be followed at various stages of production, processing, value addition, and export of spices. A total of 735 personnel were trained under the 14 campaigns conducted during 2024-25 across 13 states at a total expenditure of ₹1.68 lakh. An outreach programme was organised by the Board for the large cardamom farmers of Uttarakhand. A total of 153 farmers from various parts of Uttarakhand were benefitted through the outreach programme with the financial assistance of ₹2.65 lakh.

During the year 2024-25, the Board has conducted 17 special capacity building programmes on GAP and GHP of turmeric for farmers and FPO members in 17 locations across 12 states and three food safety and market linkage programmes for turmeric in three major turmeric growing states with expenditure of ₹57.25 lakh benefitting 1,879 stakeholders.

In order to address the Sanitary and Phytosanitary (SPS) issues in spices, Spices Board submitted a project proposal titled "Strengthening of spice value chain in India and improving market



access through capacity building and innovative interventions”, to the Standards and Trade Development Facility (STDF), an organisation under World Trade Organisation (WTO) that supports developing countries in building capacity to implement international standards, guidelines, and recommendations as a means to improve their human, animal and plant health status and ability to gain or maintain access to international markets. The project was approved by the STDF in 2018. The FAO India was the implementation partner of the project and the budget holder and was responsible for the overall supervision of the project. Spices Board was the local partner of the project and had to ensure the implementation of all local activities and their coordination under the project. The project commenced with an inception workshop conducted on 22nd October 2020. The project was completed by September 2024.

Human resource development programmes were conducted for pepper farmers during 2024-25 under the Integrated Project on Production and Post-harvest Management of Black Pepper for Tripura. The programmes were organised by Spices Board with financial assistance from Government of Tripura. A total of 492 farmers were trained under four training programmes during 2024-25 at a total expenditure of ₹4.00 lakh.

Various programmes implemented under the components ‘Enhancing Capacities for Market Expansion’, ‘Trade Promotion’ and ‘Technological Interventions’ aim to support exporters in developing infrastructure and promoting Indian spices and spice products, with a view to enhance export of processed and value-added spices, which comply with the evolving food safety standards of the importing countries. Besides encouraging adoption of scientific practices and process upgradation, the Board focused on enhancing compliance with quality and food safety norms across the supply chain of spices. The major thrust areas under above mentioned components are trade promotion, product development and research, infrastructure development, promotion of Indian spice brands

abroad, setting up of infrastructure for common cleaning, grading, processing, packing and storing (Spices Park) in major spice growing/marketing centres, promotion of organic spices/GI spices, organising Buyer Seller Meets, etc.

Under the programme ‘Technological & Infrastructural Interventions for Processing of Spices (TIIPS)’ which aims at supporting the exporters for setting up facilities for processing and value addition of spices, adoption of hi-tech infrastructure in spice processing, undertake technology interventions for process upgradation, etc., assistance amounting to ₹100.00 lakh was provided during 2024-25.

Under the programme for ‘Setting up/ Upgradation of In-house Labs for Exports’, assistance of ₹1.60 lakh was provided during 2024-25. Spices Board, with a view to empower the farmers to get better price realisation and wider market access for their produce, has established eight crop specific Spices Parks in major production/market centres. All the Parks have well established common processing units for processing, value addition and storage of spices and spice products and the units in all the Parks are functioning presently through the operators identified by the Board. As on 31st March 2025, 25 plots have been allotted to 21 exporters at Spices Park, Jodhpur, of which 13 units are functioning; 37 plots have been allotted to 21 exporters at Spices Park, Guna, of which three units are functioning; 16 plots have been allotted to 15 exporters at Spices Park, Ramganjmandi (Kota), of which one unit is functioning; 51 plots have been allotted to 26 exporters at Spices Park, Guntur, of which seven units are functioning; 17 plots have been allotted to 12 exporters at Spices Park, Sivaganga and seven plots have been allotted to three exporters at Spices Park, Raebareli. During the financial year 2024-25, one unit in Spices Park, Jodhpur started functioning.

During 2024-2025, 68774.08 MT spices worth ₹89,951.70 lakh have been processed in the common processing units and units established by the exporters in the Spices Parks of which



ANNUAL REPORT 2024-25



19,789.17 MT spices / spices products valued at ₹35,326 lakh were exported / supplied to exporters. In addition, a total of 18,197.04 MT of spices worth ₹26,261.76 lakh have been stored in the warehouses at Spices Parks. Also, a total of 1,717 workers / labourers were engaged in the Spices Parks.

Under the programme for primary processing equipment for spices, assistance of ₹14.80 lakh was provided to two exporters during 2024-25. To assist penetration of Indian brands in the identified overseas markets, with a clear mark of traceability and food safety through a series of promotional programmes. The Board has been implementing a programme for promotion of Indian spices logo and brands and assistance of ₹15.70 lakh was released to one exporter during 2024-25.

Under the programme for Assistance to Spice Exporters for Sending Samples (ASESS), assistance of ₹1.30 lakh was provided under this programme to seven exporters. Under the component for supporting product development for export, the Board provided assistance of ₹37.40 lakh to four firms during the period under report. Spices Board provided assistance of ₹8.57 lakh as certification cost to five exporters under the programme "Assistance for implementation of food safety and quality assurance mechanisms/certifications" during 2024-25.

Under the Board's programme for participation in trade fairs/ meetings/ seminars/ trainings, assistance to the tune of ₹62.61 lakh as reimbursement of air fare as well as stall charges was given to 22 exporters in FY 2024-25. The Board is also implementing programme for setting up of "Spice incubation Centres" in identified expert Institutions to support exporters, start-ups, SMEs, and entrepreneurs with innovative ideas. Objective of this programme is to guide and assist them in developing innovative products and processes in the spices sector. During 2024-25, the Board provided assistance of ₹20 lakh to two expert institutions and ₹2 lakh to an incubatee under the programme.

The Quality Evaluation Laboratories (QEL) of Spices Board at Kochi, Chennai, Guntur, Mumbai, New Delhi, Tuticorin, Kandla, and Kolkata continued to provide analytical services and mandatory testing and certification of export consignments of select spices. During the FY 2024-25, the laboratory analysed a total of 1,64,556 parameters such as Aflatoxin, Illegal dyes, Extraneous matters, Pesticide residues, Salmonella, and EtO, in 71,241 samples of spices and spice products meant for export to various countries. Also, the Board issued 14,162 Official Certificates for export consignments of spices and spice products to the EU and UK. During 2024-2025, the Board tested 606 samples in import consignments of spices and spice products received from the Customs Department under Advance Authorisation Scheme (AAS) and test reports were issued. Spices Board being referral lab to FSSAI, the Board undertook testing of samples drawn by the FSSAI for reconfirmation the ML of specified parameters. During 2024-2025, the Board tested 18 such samples received from the FSSAI Department and issued corresponding test reports.

The 47th Session of the Codex Alimentarius Commission (CAC47) held at Geneva, Switzerland during November 2024 adopted three more spice standards developed by the CCSCH committee viz., turmeric, small cardamom and the group standard for dried or dehydrated fruits and berries – allspice, juniper berry, and star anise. Presently, a total of 14 full-fledged spice standards comprising of 16 spices are published and available under Codex.

Indian Cardamom Research Institute (ICRI) focused its research efforts on crop improvement, biotechnology, crop production, crop protection, and post-harvest studies. The focal areas of research were nutrient management and soil analysis, crop protection strategies employing Integrated Pest and Disease Management techniques for both small and large cardamom. A high yielding, superior, climate resilient small cardamom variety, ICRI 10 (ICRI Sugandha Bharathi) developed by ICRI, Spices



Board, Myladumpara was released by the Kerala State Variety Release Committee on Agricultural and Plantation Crops during its 29th meeting held on 12 November 2024 at Thiruvananthapuram.

Spices Board launched the 'CardsApp,' an application with online fertiliser recommendation system during "Spice Up Your Business: Stakeholders Conclave and Buyer Seller Meet" held at ICRI, Myladumpara on 11th September 2024. This app with online fertiliser recommendation system provides vital soil test results, including a Soil Fertility Map, from samples collected across 19 villages in Udumbanchola and Idukki taluks— the regions known for cardamom cultivation potential. The project was undertaken in collaboration with Rubber Board and Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology. ICRI- Kisan Seva Kendra, a dedicated farmer facilitation centre, was also inaugurated during "Spice Up Your Business: Stakeholders Conclave and Buyer Seller Meet" held at ICRI, Myladumpara on 11th September 2024. The ICRI- Kisan Seva Kendra aims to support the spice farmers and provide solutions to various challenges in the agricultural sector. An MoU has been signed between Spices Board and ICAR- IISR for facilitating the supply of various bio control agents and planting materials from ICAR- IISR, Kozhikode through ICRI- Kisan Seva Kendra for the benefit of spice growers.

About 7,332 soil fertility parameters were tested from 935 soil samples of Cardamom Hill Reserve of Idukki district in Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka and recommendations were given for judicious application of fertilisers. Additionally, 528 soil fertility parameters from 44 soil samples in Sikkim were tested and reports provided for soil nutrient management. A total 377 soil samples from 226 farmers were analysed for available nitrogen.

In order to cater to the needs of spice farmers, with the assistance of State Horticulture Mission, Kerala, ICRI established twelve numbers of hi-tech polyhouses with automation for irrigation as well as

relative humidity control for multiplication of black pepper and a cardamom sucker nursery.

During 2024–25, the 95th Board Meeting of Spices Board was held on 29th June 2024 at Vanijya Bhawan, New Delhi, in hybrid mode. A total of 16 members were appointed to the Board out of a sanctioned strength of 31. Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India, held charge as Chairman of the Board from 12th July 2023 to 10th October 2024. Shri L. Satya Srinivas IRS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India was appointed as the Chairman of the Board on 11th October 2024.

Dr K. G. Jagadeesha IAS assumed the charge of Secretary, Spices Board with effect from 18th March 2024 and continued upto 23rd October 2024. Ms P. Hemalatha IAS took the charge of Secretary, Spices Board on 24th October 2024 and continued during the period under report.

In line with the Annual Programme as well as the orders issued by the Dept. of Official Language, M/o Home Affairs in regard to use of Hindi as Official Language, the OL section continued its efforts to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2024-25.

The Board effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the government in this regard. The Board designated the Library & Information Officer as the Coordinating Central Public Information Officer for coordinating the dissemination of information by CPIOs. The Board disclosed every information required to be disclosed suo moto in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act 2005] through the Board's official website. During 2024-25, a total of 104 RTI applications (through physical and through the online portal) and 13 appeals were received under the RTI Act and information disseminated to all the cases within the stipulated time. Three Central Information Commission (CIC) hearings were held during this period.





CONSTITUTION AND FUNCTIONS

A. Constitution of Spices Board

The Spices Board Act 1986, (No.10 of 1986) enacted by the Parliament provides for the constitution of a Board for the development of export of spices and for the control of cardamom industry including control of cultivation of cardamom and matters connected therewith. The Central Government by notification in the official gazette constituted the Spices Board, which came into being on 26 February, 1987.

B. The Spices Board consists of:

- a) A Chairman to be appointed by the Central Government
- b) Three members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States;
- c) Three members to represent the Ministries of the Central Government dealing with:
 - (i) Commerce;
 - (ii) Agriculture; and
 - (iii) Finance;
- d) Six members to represent the growers of spices*;
- e) Ten members to represent the exporters of spices;
- f) Three members to represent major spice producing states;
- g) Four members one each to represent:
 - (i) The Planning Commission (now NITI Aayog);
 - (ii) The Indian Institute of Packaging, Mumbai;
 - (iii) The Central Food Technological Research Institute, Mysuru;
 - (iv) Indian Institute of Spices Research, Kozhikode;
- h) One member to represent spices labour interests

- ❖ Amended as per Ministry of Commerce & Industry, Government of India, Gazette Notification (Extraordinary) No.G.S.R.157 (E) dated 2nd February, 2018.

C. Functions of the Board

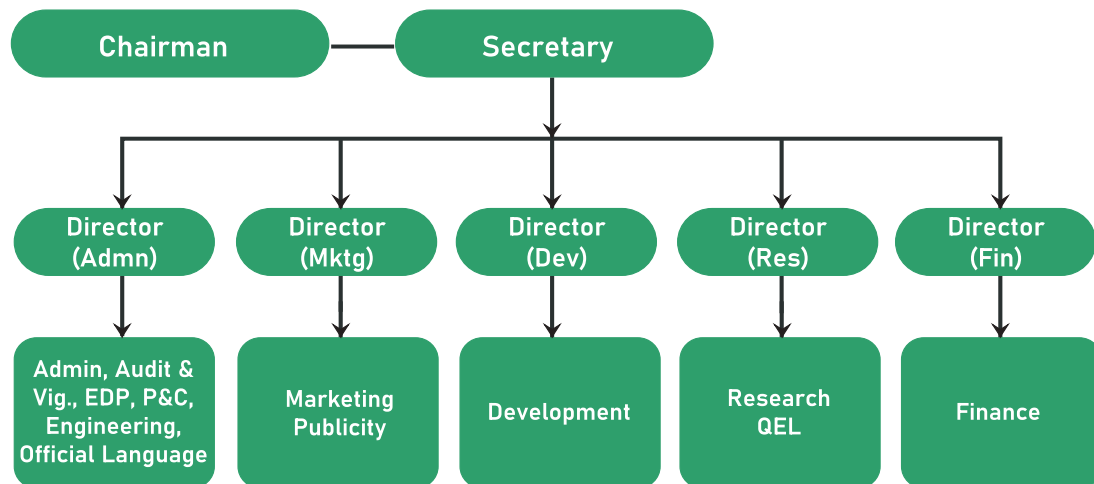
The Spices Board Act, 1986 has assigned the following functions to the Board:

a) The Board may:

- (i) Develop, promote and regulate export of spices;
- (ii) Grant certificate for export of spices;
- (iii) Undertake programmes and projects for promotion of export of spices;
- (iv) Assist and encourage studies and research, for improvement of processing, quality techniques of grading and packaging of spices;
- (v) Strive towards stabilization of prices of spices for export;
- (vi) Evolve suitable quality standards and introduce certification of quality through 'quality marking' of spices for export;
- (vii) Control quality of spices for export;
- (viii) Give licences, subject to such terms and conditions as may be prescribed, to the manufacturers of spices for export;
- (ix) Market any spice, if it considers necessary in the interest of promotion of export;
- (x) Provide warehousing facilities abroad for spices;
- (xi) Collect statistics with regard to spices for compilation and publication;
- (xii) Import with prior approval of the Central Government any spice for sale; and
- (xiii) Advise the Central Government on matters relating to import and export of spices.



Organogram of Spices Board



Sanctioned strength-379
In position - 211 (as on 31.03.2025)



ADMINISTRATION

A. Administration

Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India held charge as the Chairman, Spices Board from 12th July 2023 to 10th October 2024. Shri L. Satya Srinivas IRS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India was appointed as the Chairman of the Board on 11th October 2024 for a period of six months or until further orders. Dr K. G. Jagadeesha IAS assumed the charge of Secretary, Spices Board with effect from 18th March 2024 and continued upto 23rd October 2024. Ms P. Hemalatha IAS took the charge of Secretary, Spices Board from 24th October 2024 and continued during the period under report. Dr Rema Shree A. B. continued as Director (Research) and held additional charge of Director (Finance) during the period under report. Shri Jijesh T. Das, Deputy Director (EDP), Shri B. N. Jha, Deputy Director (Marketing), and Shri Dharmendra Das, Deputy Director (Development) continued to hold the charge of Director (Administration), Director (Marketing), and Director (Development) respectively during the period under report.

Spices Board has already achieved the targeted staff strength approved in the restructuring proposal. Against the sanctioned strength of 379, as on 31st March 2025, the existing staff strength of Spices Board is 211 consisting of 64 Group A, 72 Group B, and 75 Group C employees.

The Board granted promotion to two employees and granted financial upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) to 14 eligible employees during the period under report. The Board engaged three Marketing

Executives and eight Development Executives to support export promotion and development activities.

The Board engaged 57 unemployed youth from the SC/ST category in the graduate/postgraduate level as trainees for imparting training in analytical services in the Quality Evaluation Laboratories, agricultural extension service in the Field Offices and Research Stations and for attending official works in the Accounts and Library section.

a) Reservation for SC/ST/OBC in appointments and promotions

The Board is properly implementing the post-based reservation roster for SC/ST/OBC. The instructions issued by the Government from time to time in this regard were strictly adhered to. As on 31st March 2025 there were 128 (OBC-76, SC- 31 and ST-21) employees belonging to SC/ST and OBC categories.

No appointment was made during the period under report as per the direction from the Department of Commerce due to pending approval of the Recruitment Regulation (R.R.) of Spices Board.

b) Welfare of women

As on 31st March 2025, the total strength of women employees in the Board in Group A, B, and C categories was 59. The grievances of women employees were timely and properly attended to. A Group-A level woman officer of the Board was appointed as 'Women Welfare Officer' to sort out the difficulties/ problems, if any, or to bring them to the notice of the higher



authorities along with suggestions for possible solutions. Internal Complaints Committee was re-constituted under the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013.

c) SC/ST/OBC welfare

The Board constituted SC/ST and OBC Committees for looking after the welfare of the employees and to sort out their problems. The Board nominated a Liaison Officer for reservation matters relating to SC/ST/OBC. Apart from this, an "Internal Grievance Committee" for Scheduled Tribes employees was also constituted as recommended by the National Commission for Scheduled Tribes (NCST).

d) Welfare of persons with disabilities

Spices Board constituted PWD Cell for looking after the welfare of the employees belonging to PWD category and to sort out their problems. The Board nominated a Liaison Officer for reservation matters related to persons with disabilities. The Board also implemented reservation in promotion to the persons with disabilities as per the instructions from the Government. An expert committee was re-constituted for the purpose of identification of posts suitable for Persons with Disabilities as per the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. As on 31st March, 2025 there were 9 (OH-5, VH-3, HH-1) employees belonging to Persons with Disabilities (Divyangjan) category.

e) Functional network of Spices Board

The Head Office of Spices Board is located at Kochi in Kerala. Further, the Board has offices across the country which include Export Promotion Offices, Development Offices for small and large cardamom, Quality Evaluation Laboratories (QEL), Research Stations, and Spices Parks.

The following offices of the Board functioned during 2024-25:

(i) Export Promotion Offices

| Sl. No. | Location | State/UT |
|---------|-----------|------------------|
| 1 | Paderu | Andhra Pradesh |
| 2 | Warangal | Andhra Pradesh |
| 3 | Guntur | Andhra Pradesh |
| 4 | Guwahati | Assam |
| 5 | Patna | Bihar |
| 6 | Jagdalpur | Chhattisgarh |
| 7 | New Delhi | Delhi |
| 8 | Ponda | Goa |
| 9 | Ahmedabad | Gujarat |
| 10 | Unjha | Gujarat |
| 11 | Una | Himachal Pradesh |
| 12 | Srinagar | Jammu & Kashmir |
| 13 | Bangalore | Karnataka |
| 14 | Mumbai | Maharashtra |
| 15 | Shillong | Meghalaya |
| 16 | Aizawl | Mizoram |
| 17 | Koraput | Odisha |
| 18 | Jodhpur | Rajasthan |
| 19 | Chennai | Tamil Nadu |
| 20 | Nagercoil | Tamil Nadu |
| 21 | Nizamabad | Telangana |
| 22 | Hyderabad | Telangana |
| 23 | Agartala | Tripura |
| 24 | Barabanki | Uttar Pradesh |
| 25 | Kolkata | West Bengal |

(ii) Development Offices/Farms

| Research and Development of Small Cardamom | | |
|--|----------|--------|
| Sl. No. | Location | State |
| 1 | Adimali | Kerala |
| 2 | Elappara | Kerala |
| 3 | Kalpetta | Kerala |



| | | |
|----|-------------------|------------|
| 4 | Kattappana | Kerala |
| 5 | Kumily | Kerala |
| 6 | Nedumkandam | Kerala |
| 7 | Pampadumpara | Kerala |
| 8 | Peermade | Kerala |
| 9 | Puttady | Kerala |
| 10 | Rajakkad | Kerala |
| 11 | Rajakumari | Kerala |
| 12 | Santhanpara | Kerala |
| 13 | Udumbanchola | Kerala |
| 14 | Bodinayakanur | Tamil Nadu |
| 15 | Erode | Tamil Nadu |
| 16 | Bathlagundu | Tamil Nadu |
| 17 | Aigoor (farm) | Karnataka |
| 18 | Belagola (farm) | Karnataka |
| 19 | Beligeri (farm) | Karnataka |
| 20 | Bettadamane(farm) | Karnataka |
| 21 | Sakleshpur | Karnataka |
| 22 | Haveri | Karnataka |
| 23 | Koppa | Karnataka |
| 24 | Madikeri | Karnataka |
| 25 | Mudigere | Karnataka |
| 26 | Shivamogga | Karnataka |
| 27 | Sirsi | Karnataka |
| 28 | Somwarpet | Karnataka |
| 29 | Vanagur | Karnataka |
| 30 | Yeslur (farm) | Karnataka |

| Research and Development of Large Cardamom | | |
|--|----------|-------------------|
| Sl. No | Location | State |
| 1 | Itanagar | Arunachal Pradesh |
| 2 | Namsai | Arunachal Pradesh |
| 3 | Pasighat | Arunachal Pradesh |
| 4 | Roing | Arunachal Pradesh |
| 5 | Ziro | Arunachal Pradesh |

| | | |
|----|---------------|-------------|
| 6 | Dimapur | Nagaland |
| 7 | Kohima | Nagaland |
| 8 | Gangtok | Sikkim |
| 9 | Geyzing | Sikkim |
| 10 | Jorethang | Sikkim |
| 11 | Mangan | Sikkim |
| 12 | Kalimpong | West Bengal |
| 13 | Sukhiapokhri | West Bengal |
| 14 | Churachandpur | Manipur |

(iii) Research Stations

| Sl. No. | Location | State |
|---------|--------------------|------------|
| 1 | Myladumpara | Kerala |
| 2 | Donigal-Sakleshpur | Karnataka |
| 3 | Thadiyankudissai | Tamil Nadu |
| 4 | Tadong | Sikkim |

(iv) Quality Evaluation Laboratories (QEL)

| Sl. No. | Location | State |
|---------|-----------|----------------|
| 1 | Guntur | Andhra Pradesh |
| 2 | Kandla | Gujarat |
| 3 | Kochi | Kerala |
| 4 | Mumbai | Maharashtra |
| 5 | Narela | New Delhi |
| 6 | Chennai | Tamil Nadu |
| 7 | Tuticorin | Tamil Nadu |
| 8 | Kolkata | West Bengal |

(v) Spices Parks

| Sl. No. | Location | State |
|---------|----------------------|----------------|
| 1 | Guntur | Andhra Pradesh |
| 2 | Puttady | Kerala |
| 3 | Chhindwara | Madhya Pradesh |
| 4 | Guna | Madhya Pradesh |
| 5 | Jodhpur | Rajasthan |
| 6 | Ramganj Mandi (Kota) | Rajasthan |
| 7 | Sivaganga | Tamil Nadu |
| 8 | Raebareli | Uttar Pradesh |



f. Activities during 2024-25

i. Procurement of goods and services

All the outsourced services like security, house keeping, electricians, drivers, etc., were procured through Central/State Government owned Service Providers. Purchase of products like computers, printers, stationery, etc., were also made through GeM (More than 80 per cent of the total purchase was done through GeM).

ii. Implementation of Swachh Bharat Mission

All the activities notified by the Ministry as part of implementation of Swachh Bharat Mission were successfully implemented in Spices Board and reports including photos were forwarded to the Ministry.

As a part of the Swachhata Hi Seva (Special Campaign 4.0), the dormant and scrap items of different locations of Spices Board were identified and disposed by following the procedure as laid down in the Manual for Procurement of Goods & Services and credited the proceedings to the Spices Board.

iii. Board meetings during 2024-25

During the period 2024–25, only one Board meeting was held i.e., the 95th Board Meeting on 29th June 2024 at Vanijya Bhawan, New Delhi, in hybrid mode. A total of 16 members were appointed to the Board out of a sanctioned strength of 31. Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India, held charge as Chairman of the Board from 12th July 2023 to 10th October 2024. Shri L. Satya Srinivas IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India, was appointed as Chairman of the Board on 11th October 2024 for a period of six months or until further orders.

Dr K.G. Jagadeesha, IAS, Secretary, Coffee Board, was given additional charge of Secretary, Spices Board, with effect from

18th March 2024 to 17th September 2024, or until further orders. Ms P. Hemalatha, IAS, Development Commissioner, Cochin SEZ, was given additional charge of Secretary, Spices Board with effect from 22nd October 2024, and assumed charge on 24th October 2024. She continues to hold the position as of date.

iv. Maintenance of Outstation Offices

Maintenance of the Head Office of the Board located at Kochi and 82 offices across the country which include Export Promotion Offices, Development Offices, eight Quality Evaluation Laboratories (QELs), four Research Stations and eight Spices Parks was attended to.

v. Observance of Days of National Importance

Days of National Importance notified by the Government of India were observed in Spices Board. Following such Days were observed during the year 2024-25:-

- 10th International Day of Yoga (IDY)
- World Blood Donation Day
- Communal Harmony Week
- Campaign on “Har Ghar Tiranga”
- Country-wise Mass Pledge against Drugs
- Rashtriya Ekta Diwas
- Janjatiya Gaurav Divas
- National Commerce Day
- Armed Forces Day
- Vigilance Awareness Week
- All other days of national importance like Independence Day, Republic Day, Constitution day, etc.

B. Implementation of Official Language Policy

The Official Language section in Spices Board HO is the nodal point responsible to assist the Board to formulate and carry out programmes to promote use of Hindi as official language and also to monitor and guideline implementation of OL policy in the offices of the Board. In line with the Annual Programme



as well as the orders issued by the Department of Official Language, M/o Home Affairs in regard to use of Hindi as Official Language, the OL section, with concurrence and approval of the Secretary and the Official Language Implementation Committee of the Board, kept its efforts continued to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2024-25.

Major activities and achievements:

(i) Translation

Major translation work [English to Hindi and Vice versa] undertaken were of the;

- ❖ Documents coming under section 3(3) of OL Act, like General Orders [Circulars], Tender Documents, Advertisements, Press Release, Notifications, VIP references, etc.
- ❖ Annual Report & Audit Report 2023-24 and other administrative reports of the Board placed before the Parliament.
- ❖ Letters received in Hindi and replies thereof.
- ❖ Material for visiting cards, rubber stamps for the officials in service and mementos for the officials retiring from the service of the Board.
- ❖ Materials [banner, backdrop, invitation card, programme sheets, etc.) for various official functions arranged by the Board.

(ii) Implementation of OL policy

a) OLIC meetings

Four OLIC meetings, in the tune of one in each quarter, were convened on 27th June 2024 (April-June 2024), 30th September 2024 (July-September 2024), 31st December 2024 (October-December 2024), and 26th March 2025 (January-March 2025) respectively.

b) Hindi workshop

Four Hindi workshops were organised regularly in each quarter for the staff members of the Board and information was provided to the participants about the latest techniques to increase the use of Hindi in the office. They were made aware of the OL policy as well

as the Boards' activities to implement the OL policy with a thrust on ensuring compliance of check-points effectively.

c) Subscription to Hindi newspaper/ magazines

Continued subscription to Hindi newspaper 'Daily Hindi Milap' and Hindi magazines namely *Sarita* and *Vanita*.

d) Official Language inspection

Shri Paramanad, Deputy Director (OL), Department of Commerce and his team visited and conducted Official Language inspection of the Regional Office, Spices Board, Mumbai on 14th November 2024. The progress made by the Board in the field of implementation of the Official Language Policy of the Government was appreciated by the inspection team. During the inspection/meeting, the officials gave valuable suggestions for better implementation of the Official Language policy. Actions are being taken on the suggestions given by the officials.

e) Hindi Day/Fortnight celebrations 2024

14th September 2024 was celebrated as Hindi Day in the Board. On behalf of the Board, the Assistant Director (Official Language), Head Office, Kochi participated in the All India Hindi Conference held at Bharat Mandapam, New Delhi during 14-15 September 2024. The same day was celebrated as Hindi Day across the Board. Officials from across India participated in the Hindi Fortnight Celebrations held during 14-29 September 2024. Various competitions were organised through online medium for the staff members in connection with Hindi Fortnight Celebrations 2024.

f) Participation in the programmes arranged by TOLIC

During the period under report, Spices Board was awarded the Rolling Trophy (3rd position) instituted by Kochi TOLIC for the



best implementation of Official Language Policy in the office. The award was received by the Director i/c (Administration) during the periodical meeting of the Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Kochi on 23rd October 2024.

During the period, the Director (Research and Finance i/c) and Assistant Director (OL) of the Board attended the first half-yearly meeting of TOLIC, Kochi organised on 28th May 2024 .

g) In-service training

Spices Board nominated two officials for the Pragma Hindi training course through correspondence organised by the Central Hindi Training Institute, New Delhi.

h) Internship for the University Students

Five students doing Post Graduate Diploma in Translation, Journalism and Hindi Computing (PGDTJC) in Department of Hindi, Cochin University of Science and Technology (CUSAT) successfully completed their internship in Hindi Language from the Board as part of their curriculum.

iii) Spice India (Hindi)

Attended the work related with the release of the Board's monthly magazine 'Spice India' in Hindi.

C. Library and Documentation Service

The Board's library has a good collection of books and periodicals with computerised bibliographic data base. The process of strengthening the library and documentation unit was continued by addition of new books and periodicals. During 2024-25, 139 new books were added and continued the subscription of about 80 periodicals. Library continued the regular services like issue and return of books and periodicals, current awareness services, daily information services, e- paper reading and accessing open access journals and commenced the 'spice news service'. Reference facilities including guidelines were provided to about 17 students and research scholars from various institutions. Besides the regular activities, information was compiled on organic farming, climatic change, Indian agriculture, black pepper, cardamom, ginger, turmeric, chilli, garlic, mint, seed spices, tree spices, and oils and oleoresins.





FINANCE AND ACCOUNTS

The schemes, projects, and programmes of Spices Board are financed through grants from the Government of India. The expenditure on Administration is partly met through Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) generated from various activities of the Board.

The budget approved for the Board during 2024-25 was ₹13,000.00 lakh. The detailed allocation of the Grant-in-aid of ₹13,000.00 lakh was as under:

| SI No | Allocation of Grant-in-aid | ₹in lakh |
|-------|--|-----------------|
| 1 | Grant-in-aid General, Capital Expenditure, Salaries, Other Expenditure and Swachh Bharat | 7153.00 |
| 2 | Grant-in-aid for Subsidies/ financial assistance | 4200.00 |
| 3 | Grant-in-aid for North East Region | 849.00 |
| 4 | Grant-in-aid for Scheduled Caste Sub Plan | 249.00 |
| 5 | Grant-in-aid for Tribal Sub Plan | 549.00 |
| | Total | 13000.00 |

The Board generated a revenue (IEBR) of ₹3,751.59 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the Quality Evaluation Laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of research farms, subscription and advertisement charges, exporters' registration fee, interest on advance, interest on short term deposits, etc., in 2024-25.

Spices Board is mandated with the Export Promotion of spices (52 scheduled spices and their products); Production, Research, Development, and Domestic Marketing of Cardamom (small &

large); and Quality Evaluation and Certification of Spices for Export. To achieve this objective, the Board has been implementing various programmes and activities under the Central Sector Scheme – Sustainability in Spice Sector through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development [SPICED]. The scheme includes various components such as Improving productivity of Cardamom, Post- harvest Quality Upgradation of Spices, Quality Improvement, Enhancing Capacities for Market Expenditure, Trade Promotion, and Technologic Intervention, Research on Small and Large Cardamom, Capacity Building and Skill Development.

The total expenditure of the Board during 2024-25 was ₹13,343.85 lakh, break-up of which is given below:

| Head of Account | Expenditure (₹Lakh) |
|--|---------------------|
| Improving productivity-cardamom | 1031.49 |
| Post-harvest quality upgradation of spices | 1157.20 |
| Quality improvement | 1044.65 |
| Enhancing capacities for market expansion | 1021.65 |
| Trade promotion | 1302.48 |
| Technologic intervention | 44.68 |
| Research on small & large cardamom | 296.25 |
| Capacity building & skill development | 89.16 |
| Establishment | 7356.29 |
| Total | 13343.85 |



The Board has also been implementing certain ongoing projects and programmes with grants received from other Government Departments and national agencies such as, ICAR, ASIDE and others. The details of grants received and expenditure incurred for such projects during 2024-25 are given below :-

| Programmes | Grants Received (₹lakh) | Expenditure (₹lakh) (*) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Area Wide IPM Black Pepper | - | 2.00 |
| ICAR - AICRPS | 21.31 | 33.25 |
| Bayer Project | - | 3.03 |
| Evaluation of Flupyrimin | - | 4.33 |
| WTO-STDF | - | 16.89 |
| DUS Test Centre | 0.75 | 0.15 |
| Assessment of Polysulphate | 6.00 | 5.09 |
| Evaluation of Spinetoram | - | 11.71 |
| Evaluation of Nano Fertiliser | 2.40 | 1.70 |

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| SHM – High Tech Nursery | - | 71.41 |
| Syngenta Fungicide | - | 2.64 |
| Syngenta Insecticide | - | 1.21 |
| Women Scientist Scheme | - | 0.03 |
| ASIDE- TIES- Sikkim | - | 98.47 |
| Ginger Project Bastar | - | 0.88 |
| Myanmar Large Cardamom | - | 2.62 |
| RKVY Andhra Pradesh | - | 5.93 |
| MIDH | - | 28.30 |
| NABARD Sikkim | - | 0.94 |
| Total | 30.46 | 290.58 |

(*) Expenditure includes grants received in the previous years and utilised in FY 2024-25, as well.

The paras in the statutory Audit Report 2024-25 on Spices Board are placed as Appendix I.





04

EXPORT ORIENTED PRODUCTION AND POST-HARVEST IMPROVEMENT OF SPICES

Spices Board is responsible for the overall development of cardamom (small and large) in terms of improving production, productivity, and quality. The Board is also implementing post-harvest improvement programmes for production of quality spices for export. In line with its mandate, Spices Board is implementing the central sector scheme “Sustainability in Spice Sector through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development (SPICED), which includes various development programmes and post-harvest quality improvement programmes namely; component-I) Improving Productivity of Cardamom (small & large), and component - II) Post-harvest Quality Upgradation of Spices.

These programmes are implemented through the extension network of the Board consisting of Regional Offices, Divisional Offices, and Field Offices. The Board is maintaining five Departmental Nurseries in the major cardamom growing areas in Karnataka to cater to the requirements of quality planting materials for the spice growers.

A. Improving Productivity of Cardamom (Small & Large)

The major programmes implemented with an objective to improve the production and productivity in small and large cardamom are as follows;

a. Productivity improvement of cardamom (small)

Small cardamom is grown mainly in the Western Ghats of Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu. Majority of cardamom holdings are small and marginal. The total area under small cardamom during 2024-25 was 70,411 hectares (ha) with an estimated production of 20,696 metric tonnes. The

programmes implemented for the development of small cardamom are given below:

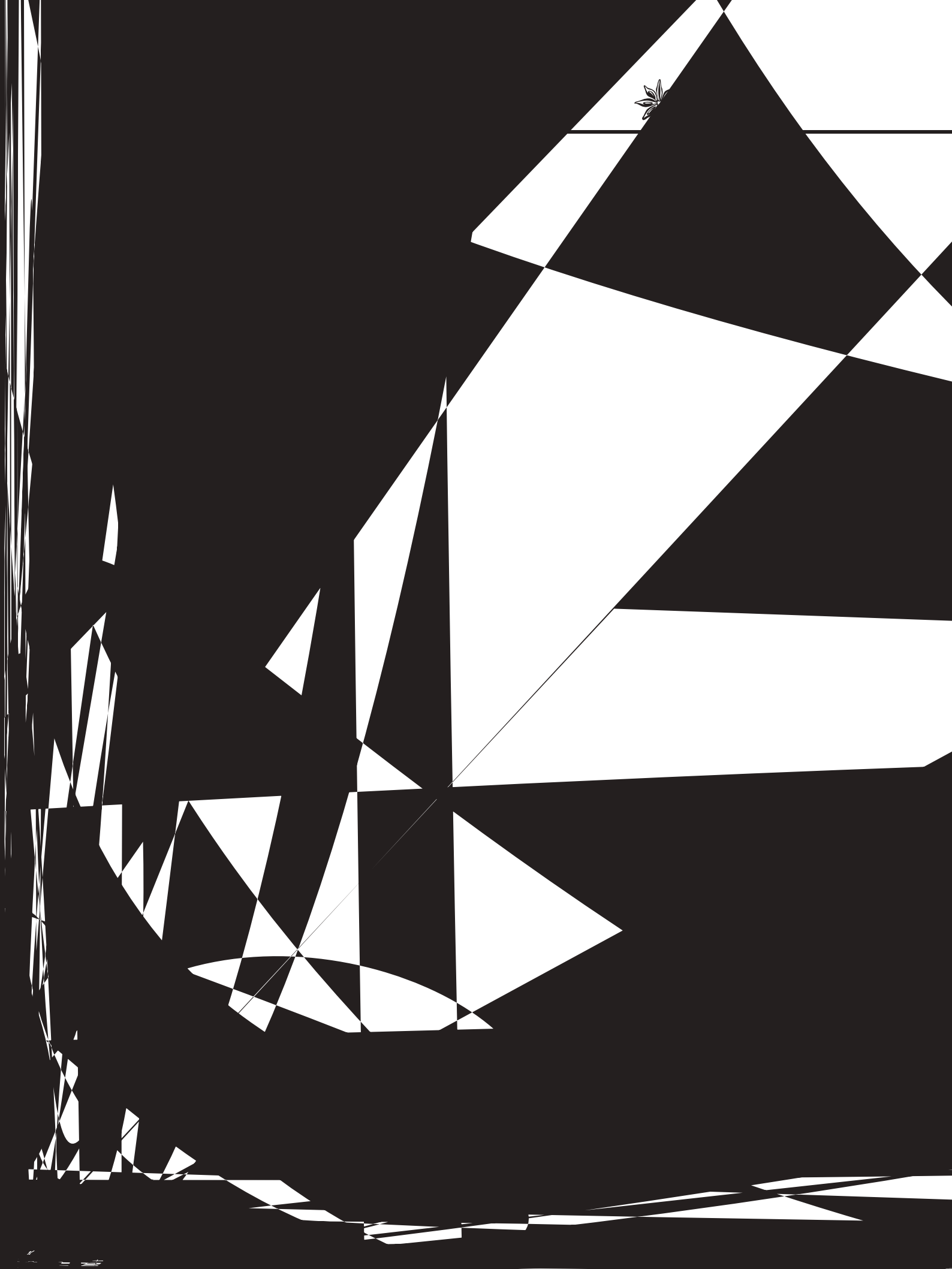
1) Replanting / new planting

The objective of this programme is to motivate the growers to improve production and productivity through systematic replanting of the diseased, old, senile, and uneconomic plantations and to take up area expansion of small cardamom in the states of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka by encouraging small and marginal growers and providing them financial assistance for replantation/new plantation.

(i) Replanting / new planting (Tamil Nadu & Kerala)

The growers are being offered financial assistance of ₹1,00,000/- for General and ₹2,10,000/- for SC and ST farmers per ha in Kerala and Tamil Nadu towards 33.33 per cent and 75 per cent respectively for the cost of replanting and maintenance during gestation period, payable in two equal annual instalments. Registered small and marginal cardamom growers owning up to four (4) ha land are eligible for benefit under this programme.

During 2024-25, financial assistance of ₹366.68 lakh was provided for replanting 746.67 ha of small cardamom (which includes ₹236.14 lakh towards first instalment for replanting of 468.15 ha during 2024-25, ₹130.54 lakh towards second instalment of replanting of 278.52 ha during 2023-24 and backlog cases of 2023-24) benefitting 2670 growers (Female:801, Transgender: 0, SC:43,ST:33).





capacity of irrigation structure should be 25 cubic metres for availing maximum assistance under the programme. Financial assistance offered under the programme is 50 per cent of the actual cost or ₹30,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹45,000/- to SC/ST category whichever is less.

During 2024-25, 78 water storage structures were constructed benefitting 78 farmers (Female: 24, Transgender: 0, SC:1, ST:0) with the financial assistance of ₹23.67 lakh.

(ii) Rainwater harvesting structures

Registered cardamom growers having a land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail the benefits under the programme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Financial assistance at the rate of 33.33 per cent of the actual cost limited to ₹18,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost limited to ₹40,000/- to SC/ST category whichever is less is extended for the construction of 200 cubic metre capacity tank.

During 2024-25, 53 rainwater harvesting structures were constructed benefitting 53 farmers (Female:16, Transgender: 0 SC:1, ST:0) with the financial assistance of ₹8.55 lakh.

(iii) Irrigation pump set

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail the financial assistance under the programme. The scale of assistance offered is 50 per cent of the actual cost or ₹30,000/- whichever is less to General category and 75 per cent of the actual cost limited to ₹45,000/- to SC/ST category.

During 2024-25, 67 irrigation equipment were installed benefitting 67 farmers (Female:21 Transgender: 0, SC:2, ST:0) with the financial assistance of ₹16.98 lakh.

(iv) Micro irrigation / sprinkler / ICT enabled irrigation equipment

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail the financial assistance under the programme. The scale of assistance offered is 50 per cent of the actual cost or ₹63,000/- whichever is less to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹95,000/- whichever is less to SC/ST category.

During 2024-25, 22 sprinkler system were installed benefitting 22 farmers (Female:7 Transgender: 0 SC:0, ST:0) with the financial assistance of ₹12.36 lakh.

4) Weather based insurance for cardamom (small)

The objective of the programme is to protect small cardamom growers against the adverse weather incidences such as deficit or excess rainfall, heat (temperature), relative humidity, etc., which are deemed to adversely affect the production. Registered cardamom growers of small cardamom having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to enrol for the programme. Agriculture Insurance Company of India Ltd (AIC) is the implementing agency of this programme under the aegis of Spices Board. The programme provides assistance of 75 per cent of the premium by Spices Board and 25 per cent by the beneficiary. The Board provides maximum assistance of ₹16,040/ ha (including GST).

During 2024-25, 670 farmers were enrolled under the programme covering an area of 370 ha with financial assistance of ₹62.22 lakh as the Board's share (Female:135).

b). Productivity improvement of cardamom (large)

Large cardamom is mainly grown in the sub-Himalayan tracts of Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Darjeeling, and Kalimpong districts of West Bengal. The total area under large cardamom in Darjeeling and Kalimpong districts



of West Bengal and Sikkim during 2024-25 was 26,617 ha with an estimated production of 6,518 MT. The total large cardamom growing area under Arunachal Pradesh, Manipur, and Nagaland in 2024-25 was 19,399 ha with the production of 3,033 MT. Non-availability of quality planting materials, presence of senile, old, and uneconomic plants and incidence of blight diseases are the major challenges affecting large cardamom production. Keeping this in view, the Board is implementing the following programmes for large cardamom.

1) Replanting / new planting

Large cardamom is grown by small and marginal farmers belonging to weaker sections of the society. The objective of the programme is to motivate the growers to adopt replanting in a systematic way to increase productivity. It is difficult for cardamom farmers to meet the cost of replanting / new planting due to higher investment. The programme provides assistance of 33.33 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of new planting in non-traditional areas and replanting in traditional areas as well as maintenance during gestation period (first and second years) as financial assistance subject to a maximum of ₹33,600/- and ₹75,000/- per hectare respectively, payable in two equal annual instalments.

During 2024-25, financial assistance of ₹265.36 lakh was provided for replanting / new planting 771.18 ha of large cardamom (which includes ₹137.75 lakh towards first instalment for replanting of 411.45 ha during 2024-25, ₹127.61 lakh towards second instalment of replanting of 359.73 ha during 2023-24 and backlog cases of 2023-24) benefitting 3,472 growers (Female:868, Transgender: 0, SC:9, ST:2,985).

2) Planting material production through certified nurseries

Availability of high yielding and disease-free planting materials is one of the major challenges in large cardamom cultivation. In order to produce disease free, healthy, and quality planting materials

for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers in their own field.

During 2024-25, under this programme 342.41 units (i.e., 17,12,050 planting materials) were established covering 604 beneficiary farmers (Female:184, Transgender: 0 SC:3,ST:422) with the financial assistance of ₹97.27 lakh.

3) Development of water sources & focus on micro irrigation

Large cardamom is mainly grown as a rainfed crop. Vagaries of climate often affect the production. The long dry spell from November to March coincides with severe winter resulting in retardation of growth and adversely affecting production. In order to increase water resources as well as to install irrigation equipment in large cardamom plantations for enabling irrigation to combat long dry spells during winter months and to increase the productivity and quality, the Board is implementing programmes in the North Eastern region and Darjeeling district of West Bengal.

(i) Construction of water storage structures

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail benefit under the programme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the financial assistance to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond/ well/ storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic metres for availing maximum financial assistance under the programme. The financial assistance offered under the programme is 50 per cent of the actual cost or ₹30,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹45,000/- to SC/ST category whichever is less.

During 2024-25, under this programme eight water storage structures were constructed covering eight beneficiary farmers (Female:3, Transgender: 0, SC:0, ST:8) with the financial assistance of ₹3.15 lakh.



(ii) Rainwater harvesting structures

Irrigation during summer months is very much essential in large cardamom plantations for getting higher yield. Harvesting rainwater (both direct rainfall as well as diversion of surface run off) for irrigation purpose is becoming popular among the cardamom growers because of its low cost and convenience. Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail benefit under the programme. The assistance will be for a structure of 200 cubic meter capacity lined with HDPE sheet (120GSM). For lesser capacity the assistance will be limited proportionate to the water holding capacity. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. The financial assistance offered under the programme is 33.33 per cent of cost of construction subject to a maximum of ₹18,000/- per structure for General and 75 per cent subject to maximum of ₹40,000/- per structure for SC/ST.

During 2024-25, under this programme 16 rainwater harvesting structures were constructed covering 16 beneficiary farmers (Female:6, Transgender: 0, SC:0, ST: 12) with the financial assistance of ₹5.52 lakh.

(iii) Irrigation equipment (including ICT enabled irrigation equipment)

Use of irrigation equipment help the growers in irrigating better way without much wastage and it is proposed to assist the growers in installing the irrigation pump sets and hose pipes for irrigation. Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail the financial assistance under the programme 'irrigation equipment'. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the financial assistance to an individual is restricted for only one unit. The financial assistance offered under the programme is 50 per cent of cost of equipment subject to a maximum of ₹15,000/- for General and 75 per cent subject to maximum of ₹22,500/- for SC/ST.

During 2024-25, 36 irrigation pump sets were installed benefitting 36(Female:11, Transgender: 0 SC: 0,ST: 28) farmers with the financial assistance of ₹6.70 lakh.

B. Post-harvest Quality Upgradation of Spices

a. Mission clean and safe spices through post-harvest improvement by groups in identified clusters

Main objective of implementing programmes under this component is increasing the export of spices from the country through focused interventions for generating an exportable surplus, meeting the quality and safety specifications of importing countries. Physical, chemical, and microbial contaminants in spices can affect the quality compliance of Indian spices, which can be addressed by adopting Good Agricultural Practices including better technologies for Post-harvest Quality Upgradation. Also, mechanisation of farm activities is proposed to address the issue of shortage of labour. Thrust is also given to equip and sustain the spice FPOs/ farmers clusters to become entrepreneurs, through post-harvest processing, value addition, and marketing.

1) Saffron Production and Export Development Agency programmes

Spices Board established Saffron Production and Export Development Agency (SPEDA) at Srinagar, Jammu and Kashmir for promoting development, marketing, quality, export, and domestic consumption of saffron. The SPEDA is co-chaired by the Secretary, Ministry of Commerce and Industry, and the Chief Secretary, Government of Jammu and Kashmir. During the period under report, the Board has taken steps for the reconstitution of SPEDA. Activities such as quality improvement training programmes, buyer seller meets, were conducted. The Board also organised GI Saffron Mela cum Awareness Programme during 2024-25 and utilised an amount of ₹1.64 lakh for the promotion of GI Saffron.



2) Quality Gap Bridging Group (QBG)

Post-harvest management helps upgrade the quality of spices and plays an important role in achieving exportable surplus. Popularising the adoption of better post-harvest management practices at farm level contributes to making available quality spices, thereby increasing the export of spices from India. The objective of the programme is to capacitate the spices producers to produce spices with quality, safety, and traceability through supporting identified groups.

(i) Post-harvest machine / equipment bank

Registered spice producer's groups in the major spice growing clusters having forward market linkage with exporters can avail the assistance for setting up of two machines/equipment under each sub-component of the post-harvest improvement programme for use among the members of the spice producer's groups. The programme envisages to develop linkage of the groups with the exporters. The groups will be encouraged to enter market linkage arrangements with exporters, for sourcing the spices for exports.

The programme provides an assistance of a maximum of ₹23.5 lakh per spice producers' group for setting up of post-harvest machine /equipment bank with maximum assistance for seed spice thresher at the rate of ₹1,35,000/-, pepper thresher at the rate of ₹34,000/-, turmeric boiler at the rate of ₹3,38,000/-, spices polishers at the rate of ₹1,70,000/-, mint distillation units at the rate of ₹3,38,000/-, leaf/herbal spice distillation units at the rate of ₹6,30,000/-, spice cleaners / graders/ spiral gravity separators at the rate of ₹80,000/, spice washing equipment at the rate of maximum ₹95,000/-, spice slicing machines at the rate of ₹16,000/-, latest post-harvest equipment (tamarind de-seeder, garlic grader, etc.) for spices at the rate of ₹1,50,000/-, spice dehullers at the rate of ₹90,000/-, spice driers at the rate of ₹67,500/-, drying spices on clean

and hygienic surfaces (Silpauline/Tarpauline) at the rate of ₹4,000/-, basic quality testing of spices for aggregation for export at the rate of ₹18,000/-, and drying platforms for FPOs, and market yards at the rate of ₹1,00,000/-

During 2024-25, 42 farmer groups in spices sector were assisted for installing various post-harvest machines with financial assistance of ₹236.32 lakh benefitting 16,186 farmers.

(ii) Post-harvest machineries for farmers from remote areas/NE region/marginalised communities, SC/ST, major export/production hub

1. Seed spice threshers

The harvesting and post-harvest practices followed by some of the seed spice growers are unhygienic which result in contamination of the products with foreign matters like stalks, dirt, sand, stem bits, etc. The seeds are separated by beating the harvested and dried plants with bamboo sticks, rubbing the plants manually by hand, etc. In order to separate the seeds from the dried plants and to produce clean spices, the Board popularises the use of threshers which are operated manually or by using power. Growers having land holding size upto 0.40 ha are eligible to avail the assistance under the programme.

The Board is providing 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the thresher as financial assistance subject to a maximum of ₹75,000/- and ₹1,12,000/- respectively for General and SC/ST farmers.

During 2024-25, assistance was provided for installing 66 power operated threshers in the farmers' fields with total financial assistance of ₹53.20 lakh, benefitting 66 growers (Female:18, Transgender: 0, SC:4,ST: 6).

2. Pepper threshers

The objective of the programme is to motivate the pepper growers to produce good quality pepper for export by promoting installation of pepper threshers for hygienic separation of pepper berries from the



spikes. The programme provides assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the thresher subject to a maximum of ₹19,000/- for General and ₹28,000/- for SC and ST farmers respectively as financial assistance .

During 2024-25, assistance was provided for installing 492 threshers with total financial assistance of ₹93.99 lakh, benefitting 492 growers (Female:172 , Transgender: 0, SC: 17,ST: 107).

3. Turmeric boiler

The programme is intended to assist the turmeric growers to adopt improved scientific methods for processing turmeric using steam boiling units. This provides better colour and quality to the final produce. Spices Board popularises the use of large- scale turmeric boiling units among growers for production of quality turmeric suitable for exports. The financial assistance provided under this programme is 50 per cent for General and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the actual cost of the boiling unit or ₹1,88,000/- for General and ₹2,82,000/- for NE/SC/ST farmers respectively whichever is less.

During 2024-25, a total number of 84 turmeric steam boiling units were installed with financial assistance of ₹183.31 lakh, benefitting 84 growers (Female:30, Transgender: 0, SC: 20, ST: 14).

4. Spice polishers

The programme aims at motivating and assisting the spices growers especially turmeric and small cardamom growers, growers' group, spice producer societies / spice farmer producer company and so on, to adopt polishing of spices by giving assistance to install improved polishers at subsidised rates to produce quality spices suitable for exports. The financial assistance provided under this programme is 50 per cent for General and 75 per cent for NE/ SC/ST farmers for the actual cost of the polisher unit or ₹94,000/- for General and ₹1,40,000/- for NE/SC/ST farmers respectively, whichever is less.

During 2024-25, assistance was provided for 153 spices polishing units (cardamom polisher and turmeric polisher) with financial assistance of ₹125.35 lakh, benefitting 153 growers (Female:38, Transgender: 0, SC: 18, ST: 24).

5. Mint distillation units

The objective of the programme is to motivate the mint growers to set up modern distillation units lined with stainless steel in their fields to improve the efficiency of distillation and quality of the oil for exports. The scheme provides assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the distillation unit subject to a maximum of ₹1,88,000/- for General and ₹2,82,000/- for SC and ST farmers respectively as financial assistance.

During 2024-25, eight mint distillation units were installed with total financial assistance of ₹16.91 lakh, benefitting eight growers (Female:2, Transgender: 0, SC:2 ,ST:0).

6. Spice cleaners/ graders/ spiral gravity separators

The objective of the programme is to popularise the spice cleaners/graders/spiral gravity separators to increase profitability in production of spices by way of mechanisation and to improve the quality of spices for export. The programme provides assistance of 50 per cent of cost of unit, subject to a maximum of ₹44,000/- per unit for General category and 75 per cent subject to maximum of ₹66,000/- per unit for NE/SC/ST farmers.

During 2024-25, a total of 153 spice cleaners/ graders/spiral gravity separators were installed with financial assistance of ₹46.60 lakh, benefitting 153 growers (Female: 33, Transgender: 0, SC:6,ST:35).

7. Spice washing equipment

The objective of the programme is to popularise the spice washing equipment to increase profitability in production of spices by way of mechanisation and to improve the quality of spices for exports. The programme provides assistance of 50 per cent of cost of unit, subject to a maximum of ₹53,000/- per



unit for General category and 75 per cent subject to maximum of ₹79,500, per unit for NE/SC/ST farmers respectively.

During 2024-25, a total of 39 spices washing machines were installed with financial assistance of ₹21.28 lakh, benefitting 39 growers (Female: 14, Transgender: 0, SC: 0, ST:3).

8. Spice slicing machines

The objective of the programme is to motivate the growers to adopt slicing of ginger and turmeric before drying using simple slicing machines to improve the quality. The programme provides assistance of 50 per cent of cost of unit, subject to a maximum of ₹9,000 /- per unit for General category and 75 per cent subject to maximum of ₹13,000, per unit for NE/SC/ST farmers respectively.

During 2024-25, ten spice slicing machines were installed with financial assistance of ₹1.30 lakh benefitting 10 growers (Female: 4, Transgender: 0, SC:0, ST:9).

9. Spice dryers

The objective of the programme is to popularise mechanical dryers among the growers to produce quality nutmeg, mace, clove, etc. The programme provides assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the cost of the dryer subject to a maximum of ₹37,500/- for General and ₹56,250/- for NE/SC/ST farmers respectively as financial assistance.

During 2024-25, assistance was given for setting up of 320 spice dryers with financial assistance of ₹75.13 lakh, benefitting 320 growers (Female:112, Transgender: 0, SC:0, ST:0)

(iii) FPO/QGBG level processing and value addition

The objective of this programme is to promote primary processing and value addition by groups or FPOs in identified clusters to generate an exportable surplus. Assistance is provided to FPOs in setting up of unit(s) for primary processing and value addition of spices, to generate an exportable

surplus and to facilitate forward integration. Financial assistance is provided at the rate of 90 per cent of the establishment cost of small-scale primary processing/value addition units subject to a maximum ceiling of ₹15 lakh/unit.

During 2024-25, assistance was given to two FPOs in setting up of processing units with financial assistance of ₹15.73lakh, benefitting 405 growers.

3) Improved Curing Devices for Small Cardamom

The objective of the programme is to motivate the growers to adopt improved curing devices for drying cardamom to produce good quality cardamom for export. The programme provides assistance of 33.33 per cent to a maximum of ₹1,50,000/- for general and 75 per cent for SC/ST to a maximum of ₹3,37,500/-, 90 per cent for Groups/FPOs subject to a Maximum of ₹4,00,000/-.

During 2024-25, 29 improved cardamom curing devices were set up at total financial assistance of ₹34.48 lakh, benefitting 29 growers (Female:12, Transgender: 0, SC:0, ST:0).

4) Large Cardamom Dryers (Sawo dryer / Modified Bhatti / Approved equivalent dryer)

The objective of the programme is to motivate the farming community to adopt scientific curing methods for improving the quality of large cardamom. The programme provides financial assistance at the rate of 75 per cent for NE/SC/ST and Kalimpong, and Darjeeling districts of West Bengal and 90 per cent for Groups / FPOs with maximum ceiling as follows;

- Individual growers: Large cardamom growers having 0.10 ha to 0.40 ha for 200 kg capacity bhatti or single door sawo / equivalent dryer assistance is ₹30,000/- and for cardamom growers having 0.4 ha to 4 ha for 400 kg capacity bhatti or double door sawo / equivalent dryer assistance is ₹45,000/-
- Groups/FPOs: For 200 kg capacity bhatti or single door sawo / equivalent dryer assistance is ₹36,000/- and for 400 kg capacity bhatti or



double door sawo / equivalent dryer assistance is ₹54,000/-.

During 2024-25, a total of 40 modified bhatti units/sawo dryer were constructed at financial assistance of ₹12 lakh, benefitting 40 growers (Female:10, Transgender: 0 SC:0, ST:27)

5) Inclusive development for SC/ST communities through spice promotion

The programme aims to train and equip the SC/ST community to take up spice cultivation and turn them from primary sellers to entrepreneurs, thereby uplifting the community.

(i) Capacity building through ICAR institutes/SAUs/KVKs/ICRI/similar institutes

The objective of the programme is to empower the aspiring youth in agriculture/farmers belonging to the SC/ST category, upgrade their knowledge and skill in farming/entrepreneurship, and to create a pool of master trainers among the community.

During the year 2024-25, six trainings were conducted in various ICAR institutes/KVKs in five states benefitting 183 growers (Female:55, Transgender: 0 SC:8, ST:170). An amount of ₹10.19 lakh was incurred.

6) Promoting exportable surplus of GI tagged and other spices

The objective of the component is to demonstrate and motivate the growers of North Eastern states for cultivation of various spices with intrinsic qualities and also spices with GI tag viz., Lakadong turmeric, Naga chilli, Hathei chilli, Mizo chilli, Mizo ginger, Dalley khursani, etc., in specific agro-climatic conditions suitable for cultivation of such spices, with a view to facilitate import substitution. Individual registered grower having a land holding size of 0.10 ha to 4 ha is eligible to apply. Minimum area to be planted under the programme to avail assistance is 0.10 ha in a continuous block. Maximum 4 ha is eligible per beneficiary limited to 2 ha per year. Financial assistance is provided at the rate of 50 per cent of cost of planting material subject to maximum of ₹25,000 per ha.

During 2024-25, assistance was provided to 680 farmers of NE states covering 266.6 ha with financial assistance of ₹60.73 lakh (Female:204 Transgender: 0, SC:22, ST:484).

b. Promotion of sustainable production & certification systems like organic, IndGAP, Natural farming, etc.

1) Internal control system (Groups)

Spices Board is promoting organic farming in spices sector by supporting farmer groups/FPOs to establish grower group certification. The farmers who are desirous of adopting organic farming need to go through the procedures of organic certification. Establishing an Internal Control System [ICS] is a pre-requisite for grower group certification (Umbrella certification) in order to prepare these farmers on group formation, organic regulations, certification procedures, training, documentation, internal inspection, etc. The Board proposes to support the grower groups / FPOs, etc., to establish ICS for organic certification and aggregation of the produce. A group/FPO is eligible for financial assistance for three years consecutively or in staggered manner as per availability of funds in the component. The assistance is provided at the rate of 50 per cent of cost of organic certification subject to a maximum of ₹1,12,000/- for groups from other than North East Region and 75 per cent subject to a maximum of ₹1,68,000 for North East Region groups.

Financial assistance of ₹2.49 lakh was provided to three farmer groups during 2024-25.

2) Organic group certification

The objective of the programme is to assist spices growers groups / FPOs in acquiring certification for organic spices farms for promoting export of organic spices. The programme provides assistance of 50 per cent assistance subject to maximum of ₹1,50,000/- for from other than North East Region and 90per cent subject to a maximum of ₹2,70,000/- for NER groups.



Financial assistance of ₹2.03 lakh was provided to three farmer groups during 2024-25.

3) IndGAP & other sustainable certification in production

The objective of the programme is to assist Farmers' Groups/FPO/FPC/Spice Producers' Societies in acquiring IndGAP group certification for spices farms for promoting exports of GAP spices. The programme provides assistance of 90 per cent of the cost of certification subject to a maximum of ₹1,12,500/- per group.

Financial assistance of ₹8.05 lakh has been provided towards certification assistance for five farmer groups during 2024-25

4) On farm production of composts

The objective of this programme is to promote the growers to construct vermicompost units/any farm compost unit in the farm itself to produce quality vermicompost/composts for maintaining soil health to promote organic production. The programme provides 50 per cent assistance for General, 75 per cent for SC/ST and 90 per cent for Groups/FPOs with maximum ceiling (General category: ₹10,000/-; NE/SC/ST: ₹15,000/-; FPOs/SHGs/FIGs/Spices societies: ₹18,000/-).

During 2024-25, assistance was provided to 247 farmers with financial assistance of ₹33.68 lakh (Female:74, Transgender: 0, SC:9, ST: 139).

5) Care and Cure Centres for FPOs on PPP mode to promote IPM/ GAP and sustainable cultivation

The objective of this programme is to support FPO/FPC towards the cost of setting up of Care and Cure Centre and inputs procured from authorised sources in order to promote IPM/GAP and sustainable cultivation. Maximum assistance is limited to ₹2,00,000/- based on the project proposed by FPOs/FPCs. Financial assistance of ₹8 lakh was provided to five FPOs during 2024-25.

C. Extension Advisory Services

Training on transfer of technical know-how to growers on production and post-harvest improvement

of spices is an important factor in increasing productivity and improving quality of spices. This programme envisages technical/extension support to growers on the scientific aspects of cultivation and post-harvest management through personal contact, field visits, group meetings, and distribution of literature for small cardamom (in the states of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka) and for large cardamom (in the states of Sikkim and West Bengal).

Besides extension advisory service, the programmes for production and post-harvest improvement of small and large cardamom and post-harvest programmes of the Board are implemented through the extension network.

During 2024-25, a total of 14,945 extension visits were made and 2,788 group meetings/campaigns were organised for cardamom (small and large) in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Kalimpong, and Darjeeling districts of West Bengal, and other spices growing areas. The total expenditure under extension advisory service was ₹114.53 lakh during 2024-25.

The program envisages engaging spice extension trainees (SET) and young professionals for providing on field extension services by paying a consolidated monthly stipend.

D. Capacity Building Programmes

a. Training Programme for Quality Improvement of Spices (QITP)

Spices Board is regularly conducting quality improvement training programmes for farmers, officials of state agriculture / horticulture departments, traders, members of NGOs, etc., for educating them on scientific methods of pre and post-harvest and storage technologies and updated quality requirements for major spices.

A total of 12,771 personnel were trained under 215 training programmes during 2024-25 at a total expenditure of ₹22.32 lakh (Female: 3434, Transgender: 0, SC: 621, ST: 4,814).



b. Campaign on Clean and Safe Spices

A campaign on 'Clean and Safe Spices' was conducted on 25th February 2025, commemorating the 38th foundation day of the Board. The campaign was designed to sensitise the stakeholders on the risk, corrective actions, and good practises to be followed at various stages of production, processing, value addition, and export of spices. The campaign was conducted across the country for creating awareness to all the stakeholders and public. A total of 735 personnel were trained under the 14 campaigns conducted during 2024-25 across 13 states at a total expenditure of ₹1.68 lakh (Female: 193; Transgender: 0, SC: 70; ST: 124).

c. Outreach programme

An outreach programme visit was organised by the Board for the large cardamom farmers of Uttarakhand. A total of 153 farmers from various parts of Uttarakhand were benefitted through the outreach programme with the financial assistance of ₹2.65 lakh.

d. Special programmes for turmeric

During the year 2024-25, the Board has conducted 17 special capacity building programmes on GAP and GHP of turmeric for farmers and FPO members in 17 locations across 12 states and three food safety and market linkage programmes for turmeric in three major turmeric growing states with expenditure of ₹57.25 lakh benefitting 1,879 stakeholders.

- (i) Capacity building programme on turmeric 1108 (Female: 327, SC:120,ST:471)
- (ii) Market linkage programme: 771 (Female: 244, Transgender: 0, SC:36; ST:171)

E. Externally Funded Projects

a. Strengthening of spice value chain in India and improving market access through capacity building

In order to address the Sanitary and Phytosanitary (SPS) issues in spices, Spices Board had submitted a project proposal in 2014 titled “ *Strengthening of*

spice value chain in India and improving market access through capacity building and innovative interventions”, to the Standards and Trade Development Facility (STDF), an organisation under World Trade Organisation (WTO) that supports developing countries in building capacity to implement international standards, guidelines and recommendations as a means to improve their human, animal and plant health status and ability to gain or maintain access to international markets.

The project was approved by the STDF in October 2018. FAO India was the implementation partner of the project and the budget holder and was responsible for the overall supervision of the project. Spices Board was the local partner of the project and had to ensure the implementation of all local activities and their coordination.

The overall objectives of the project were:

- ❖ Capacity building of stakeholders in spices value chain to expand exports of safe and high-quality spices from India to overseas market.
- ❖ Boost income of small-scale farmers, empower women and other marginalised communities
- ❖ Support efforts to reduce poverty (SDG 1/0 and hunger (SDG 2)
- ❖ The project was implemented in 12 villages across four states focusing four spices namely;
- ❖ Cumin and Fennel in Gujarat and Rajasthan (implemented in four villages in each state)
- ❖ Coriander in Madhya Pradesh (in two villages)
- ❖ Black Pepper in Andhra Pradesh (in two villages)

The project commenced with an inception workshop conducted on 22nd October, 2020. The project was completed by September 2024 in four phases . The activities conducted during fourth phase include:

- ❖ Organised four field visits for selected farmers/ FPOs from the project implementing areas to industries/ processing facilities/spice parks in nearby districts and states benefitting 61 growers(Female: 4,SC:2,ST:10).



- ❖ Conducted four regional workshops for establishing arrangements between spice exporters and FPOs in the state of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Andhra Pradesh resulted in signing of Memorandum of Understanding (MOU) between the Farmer Producer Organizations (FPOs) and exporters.
- ❖ Conducted demonstration programmes on GAP and GHP in post-harvest operation at the four project locations benefitting 636 growers (Female:55,SC:3,ST:124).
- ❖ 144 spice samples were collected and analysis completed through empaneled lab of Spices Board.
- ❖ Four FPOs in the project implementing states were certified under IndGAP certification.

(b) Integrated Project on Production and Post-harvest Management of Black Pepper for Tripura

Human resource development programmes were conducted for pepper farmers during 2024-25 under the integrated Project on Production and Post-harvest Management of Black Pepper for Tripura. The programmes were organised by Spices Board with financial assistance from Government of Tripura.

A total of 492 farmers were trained under four training programmes during 2024-25 at a total expenditure of ₹4.00 lakh (Female: 105, SC: 79, ST: 247).





EXPORT DEVELOPMENT AND PROMOTION

Spices Board is mandated with the export promotion of spices (52 scheduled spices and their products) & production, research, development, and domestic marketing of cardamom (small & large) and quality evaluation & certification of spices for export. To achieve this objective, the Board has been implementing various programmes and activities under the Central Sector Scheme - "Sustainability in Spice Sector Through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development (SPICED)".

The export of spices and spice products from India crossed an all-time high in FY 2024-25. During FY 2024-25, India exported 17,99,267 MT of spices and spice products valued at ₹39,994.48 crore (4,722.65 million US\$) as compared to 8,93,920 MT valued at ₹14,899.67 crore (2432.84 million US\$) during 2014-15, registering an increase of 101 per cent in volume, 168 per cent in rupee terms of value and 94 per cent in dollar terms of value. The export of spices registered a CAGR of seven per cent in volume, ten per cent in value (INR), and seven per cent in value (US\$) since 2014-15.

An interactive meeting was held by Shri Jitin Prasada, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry with the FPO/FPC stakeholders involved in the Saffron Value Chain in Jammu and Kashmir on 11th July 2024. The Minister visited the Saffron Park wherein the post-harvest processing of saffron was demonstrated.

Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India interacted with the stakeholders of spices sector on 21st February 2025 in a meeting organised at Marine Products Exports Development Authority (MPEDA), Headquarters in Kochi, Kerala. The meeting discussed the challenges and opportunities in the spices sector. Key areas of interaction included

strengthening the monitoring of rerouted pepper, advancing value added processing, and expanding organic spice exports. Intercropping of potential spices with other plantation crops, modernising the Quality Evaluation Laboratories, stringent food safety and quality standards fixed by importing countries, especially the European Union, and cultivation of herbal spices in the North East India were also discussed during the various programmes implemented under the components '*Enhancing Capacities for Market Expansion*', '*Trade Promotion*' and '*Technological Interventions*' aim to support exporters in developing infrastructure for processing, value addition and export promotion, with a view to enhance export of processed and value-added spices, which comply with the evolving food safety standards of the importing countries. Besides encouraging adoption of scientific practices and process upgradation, the Board focuses on enhancing compliance with quality and food safety norms across the supply chain of spices.

The major thrust areas under the above-mentioned components are mission value addition, trade promotion, product development and research, setting up of infrastructure for common cleaning, grading, processing, packing and storing (Spices Park) in major spice growing/marketing centres, promotion of organic spices/GI spices, organising Buyer Seller Meets, etc.

A. Enhancing Capacities for Market Expansion

a. Mission Value Addition

1) Technological & Infrastructural Interventions for Processing of Spices (TIIPS)

The programme aims at supporting the exporters for setting up facilities for processing





| SI No | Location/State | Spices Covered | Land Area (Acre) |
|-------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Chhindwara, Madhya Pradesh | Chilli & Garlic | 10.00 |
| 2 | Puttady, Kerala | Pepper & Cardamom | 12.50 |
| 3 | Jodhpur, Rajasthan | Cumin & Coriander | 60.00 |
| 4 | Guna, Madhya Pradesh | Coriander | 100.00 |
| 5 | Sivaganga, Tamil Nadu | Chilli & Turmeric | 75.00 |
| 6 | Guntur, Andhra Pradesh | Chilli | 125.00 |
| 7 | Ramganjmandi (Kota), Rajasthan | Coriander | 30.00 |
| 8 | Rae Bareli, Uttar Pradesh | Mint | 11.79 |

(i) Status of common processing units in Spices Parks

All the Parks have well established common processing units for processing, value addition,

and storage of spices and spice products, which are functioning through the operators identified by the Board. The processing facilities available in each Park along with the name of the operators are given below:

| Location of the Spices Park | Details of processing facilities | Name of the operator |
|-----------------------------|--|--|
| Chhindwara | Garlic drying / dehydration and chilli extraction | M/s Vee natural |
| Guna | Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for seed spices particularly coriander | M/s Mayank Industries |
| Guntur | Cleaning, sorting, grinding and packaging facilities for chillies | M/s Mane Kancor Spices Pvt Ltd |
| Jodhpur | Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for seed spices particularly cumin | M/s Shree Radhey Krishna Spices Pvt Ltd |
| Ramganj Mandi (Kota) | Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for seed spices particularly coriander | M/s Orkla India Ltd |
| Puttady | Cleaning, grading, grinding, packaging facilities for cardamom and pepper | M/s Flavourit Spices Trading Ltd |
| Raebareli | Mint and other herbs oil distillation unit in Park and impact zone | The distillation units are directly operated by Farmers groups |
| Sivaganga | Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for chillies and turmeric | M/s Season Fresh Agro Foods |



Also, the common storage facilities (warehouses) at Spices Park, Jodhpur, Raebareli, and Sivaganga have been leased out to exporters.

(ii) Status of allotment of plots to exporters and status of units established at Spices Parks

All the Spices Parks except Chhindwara and Puttady, have land that is earmarked for allotting to prospective entrepreneurs for developing their own processing units for value addition and high-end processing of spices.

As on 31st March 2025, 25 plots have been allotted to 21 exporters at Spices Park, Jodhpur, of which 13 units are functioning; 37 plots have been allotted to 21 exporters at Spices Park, Guna, of which three units are functioning; 16 plots have been allotted to 15 exporters at Spices Park, Ramganjmandi (Kota), of which one unit is functioning; 51 plots have been allotted to 26 exporters at Spices Park, Guntur, of which seven units are functioning; 17 plots have been allotted to 12 exporters at Spices Park, Sivaganga and seven plots have been allotted to 3 exporters at Spices Park, Raebareli. During the financial year 2024-25, one unit in Spices Park, Jodhpur started functioning.

Also, the Board is in the process of allotting vacant plots in different spices Parks. The plots in Spices Park at Sivaganga and Guna are open for allotment to exporters registered with APEDA, Tea Board and Coffee Board for establishing processing units of food and allied products.

Further, the Board has allotted supporting facilities in the Parks viz., built up area for establishing laboratory, office space, canteen building, bank building, etc., to eligible stakeholders through bidding process.

(iii) Performance of Spices Parks

During 2024-2025, 68774.08 MT spices worth ₹89,951.698 lakh was processed in the common processing units and units

established by the exporters in the Spices Parks of which 19,789.167 MT spices / spices products valued at ₹35,326 lakh was exported / supplied to exporters. In addition, a total of 18,197.04 MT of spices worth ₹26,261.76 lakh was stored in the warehouses at Spices Parks. Also, a total of 1,717 workers / labourers were engaged in the Spices Parks.

(iv) Spice Complex Sikkim

Govt of Sikkim had allotted ten acres of land free of cost at Namcheybong in East District of Sikkim to Spices Board to establish a Spice Complex for development of infrastructure for promoting spices exports from the state. The Executive Committee of Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) in its 13th meeting held on 9th February 2021 accorded approval for the establishment of Spice Complex in Sikkim, at a total financial outlay of ₹26.51 crore, out of which Spices Board's share is ₹8.77 crore and the remaining amount of ₹17.74 crore would be the contribution from TIES. Spices Board signed a MoU with Central Public Works Department (CPWD), Gangtok for establishment of the Spice Complex on a turn-key basis. The work is under progress and is expected to be completed by 31st December 2025.

4) Primary processing equipment for spices

Under this programme, the Board aims at assisting exporters in installing various types of primary processing equipment/ facilities including driers, cleaners, grading equipment, colour sortex, polishing equipment, destalking machines, dehulling equipment, packing equipment, etc., for improving the quality of the produce, so as to pool an exportable surplus of spices and spice products. The scale of assistance is 50 per cent of the cost of equipment and accessories subject to a maximum of ₹10 lakh for general category exporters and 75 per cent of the cost of machinery subject to a maximum of ₹15 lakh for SC/ST exporters and FPO exporters. During 2024-25, assistance of ₹14.80 lakh was provided to two exporters under this programme.



b. Product & Market Development and Branding of Indian Spices

1) Promotion of Indian Spices Logo and Brands

The objective of the programme is to assist penetration of Indian brands in the identified overseas markets, with a clear mark of traceability and food safety through a series of promotional programmes. Under this programme, exporters who have registered their brand with the Board can avail the financial assistance as interest free loan of up to ₹100 lakh per brand. Assistance under the programme covers 100 per cent of slotting / listing fee and promotional expenditure, and 50 per cent of the cost of product development, so as to help the exporters to position specified brands in the identified outlets in selected cities abroad. During 2024-25, the Board released an amount of ₹15.70 lakh to one exporter under the programme.

2) Assistance to Spice Exporters for Sending Samples (ASESS)

Export contracts for spices and spice products in general are concluded based on samples provided to the buyers. Exporters are required to send samples to their customers abroad, for approval and to match the requirements of the buyers. Considering the higher cost of couriering samples and number of samples required to be couriered for securing a contract, the Board provides assistance to exporters to offset the cost of courier charges for sending samples abroad. Assistance under the scheme is provided to newly registered exporters (first registration with Spices Board in the last three years) and exporters falling under micro and small category and exporters with annual turnover not more than ₹50 crore during the previous FY at the rate of 50 per cent of the cost of courier charges subject to a maximum of ₹1.50 lakh per annum for general category and 75 per cent of the courier charges subject to a maximum of ₹2.25 lakh per annum for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, Himalayan States, State notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep).

During 2024-25, assistance of ₹1.30 lakh was provided under this programme to seven exporters.

3) Supporting Product development for Export

Spices are known to have medicinal, cosmetic, nutritional, and health values. A vast body of traditional knowledge about such uses is available in the country. However, sufficient documented evidence / validation studies do not exist to establish the acclaimed properties of spice / spice extracts / spice mixes. The absence of documentation / validation prevents the marketability of such products. If the required documentation/ validation is generated on the basis of scientifically conducted trials and clinical evaluation, products can be formulated with very high value addition and these products can be marketed and patented (if required) in the established markets as alternative medicines, functional foods, nutraceuticals, immunity boosters, etc. Also, there is scope for deriving new end uses and applications from the spices produced within the country. Development of new end products from spices involve scientific research in the areas of unconventional applications, which can further lead to creation of patentable products with higher potential for exports. The scheme offers financial assistance for product research and development, clinical trials, validation of properties, and patenting and test marketing. Registered exporters and R&D institutions having required facilities are eligible to avail assistance under the programme to the tune of 50 per cent of the cost of product development, research, including development of new devices / equipment/ validation of technology subject to a maximum of ₹1.00 crore, if clinical trials (international), patenting and commercial / regulatory approvals (EPA, FDA etc.) are involved. If clinical trials, patenting etc., are not involved the assistance will be limited to ₹25 lakh. The assistance towards cost of equipment, if any, will be considered up to a maximum of 25 per cent of the project cost. Also, for Central/State Universities/ R&D and other institutions of the Government, the scale of assistance is extended up to 100 per cent



of the cost of the project, without any change in the ceiling. During 2024-25, the Board provided assistance of ₹37.40 lakh to four firms under the programme.

4) Assistance for implementation of food safety and quality assurance mechanisms/certifications

Quality and food safety are key aspects for export of spices to international markets. Third party / reputed certifications related to quality and food safety build confidence and trust among the international buyers and consumers and thus help to sustain / enhance the spices exports from the country. In order to encourage the spices exporters to obtain Quality and Food Safety Certifications and Markings, the cost of accreditation/certification of processing units, in-house laboratories, etc., of spices exporters under ISO/ HACCP/ FSSC 22000/ NPOP, etc., (including KOSHER, HALAL, GMP, SQF, BRC, etc.) by recognised agencies, certification by authorised agencies of importing countries / Foreign Buyer Verification Programme (FBVP), etc. are considered.

Under this programme, the Board provides assistance to exporters for implementation of HACCP/ ISO Standards/ Food safety/ Quality Management Systems (FSMS)/ GMP/ NPOP/ Organic Certifications / other certifications and markings related to spices including the Spice House Certification, Indian Spices Logo etc., so as to enable communication of compliance with quality and safety parameters and to build and improve the trust among the global buyers for Indian spices.

The Board provides 50 per cent of the cost of certification/ renewal subject to a maximum of ₹5 lakh for general category exporter during the period. And 75 per cent of the cost of certification / renewal subject to a maximum of ₹7.50 lakh for SC/ ST exporters, FPO exporters and exporters from NE region (including Sikkim, Darjeeling and Kalimpong region of West Bengal) & other Himalayan states/ Himalayan UTs and islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep). During 2024-25, the Board provided assistance of ₹8.57 lakh as stall charges to five exporters.

5) Market research and auxiliary services for export Development

(i) Mandatory sampling and testing

Under the provisions of the Spices Board Act, 1986 and Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, Spices Board is undertaking Mandatory Sampling and Testing of export consignments of some of the spices and spice products to selected destinations based on the requirement of the importing countries, previous incidences of export alerts, risk assessment, etc. During FY 2024-25, the Board continued the mandatory sampling, testing and clearance of spice consignments, with periodic amendments to the parameters and spices tested, in line with the changing requirements.

As part of mandatory sampling and testing programme, the Board analysed 1,64,556 parameters such as Aflatoxin, Illegal dyes, Extraneous matters, Pesticide residues, Salmonella, and EtO in 71,241 samples of spices and spice products meant for export to various countries during 2024-25. Also, the Board issued 14,162 Official Certificates for export consignments of spices and spice products to the EU and UK.

(ii) Testing of Customs samples of spices

The Board is receiving samples of spices and spice products imported into the country under Advance Authorisation Scheme (AAS) through Customs Department for yield assessment and providing recommendation to the DGFT for the fixation of Standard Input Output Norms (SION). During 2024-2025, the Board tested 606 samples in import consignments of spices and spice products received from the customs department and test reports were issued.

(iii) Testing of FSSAI samples of spices

Spices Board being referral lab of FSSAI, the Board undertook testing of samples drawn by the FSSAI for reconfirmation the MRL of specified parameters. During 2024-2025, the



Board tested 18 such samples received from the FSSAI and issued corresponding test reports.

(iv) Testing of private samples of spices

The Board receives private samples of spices and spice products from exporters /farmers / stakeholders to test the quality of their spices / spice products, according to the parameters specified by them.

During 2024-25, the Board tested 346 private samples and issued the test reports.

6) Registration & licensing

(i) Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES)

As per the Spices Board Act, 1986, any person exporting spices from India is required to possess a valid Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES). As per Spices Board (Registration of Exporters) (Amendment) Regulations, 2021, the CRES is valid for three years from the date of issuance.

The issuance of CRES by the Board was migrated to the Common Digital Platform (eRCMC) developed by the Directorate General Of Foreign Trade (DGFT) during 2022-23 and starting from May 2022, CRES was issued through the DGFT platform.

During 2024–25, a total of 4,106 CRES were issued, of which 3,713 were granted to merchant exporters and 393 to manufacturer exporters.

(ii) Cardamom Dealer & Auctioneer license

Any person who wishes to carry on the business of cardamom as auctioneer or dealer shall have a valid licence from the Board, as per the Cardamom Licensing & Marketing Rules, 1987. Accordingly, Auctioneer and Dealer Licenses for Cardamom (Small & Large) are issued by the Board. As part of facilitating ease of doing business, Spices Board has on-boarded the National Single Window System (NSWS) developed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), for the issuance of Cardamom Dealer and Auctioneer

License, with effect from 1st August 2022. The Auctioneer and Dealer Licenses are issued for a block period of the three years and the current block period (2023-26) extends till 31st August 2026.

As of now, the Board has issued 705 Cardamom Dealer Licenses, comprising 688 Small Cardamom Dealer Licenses and 17 Large Cardamom Dealer Licenses. During 2024-25, the Board issued 130 Cardamom Dealer Licenses, of which 116 were issued to small cardamom dealers and 14 to large cardamom dealers.

Currently, there are 18 licensed e-auctioneers and four licensed manual auctioneers for cardamom. During 2024-25, the Board issued two cardamom e- auctioneers licence for small cardamom and one manual auctioneer licence for large cardamom.

(iii) Auction of Cardamom - Establishment of cloud-based live e-auction system

The Board introduced 'Cloud Based Live e-Auction' with effect from 1st November 2021, which enabled virtual linking of both the auction centres at Puttady in Kerala and Bodinayakanur in Tamil Nadu and simultaneous conduct of the e-auction. In this system, the farmers and dealers can take part in the cardamom auctions from any of the auction centre as per their convenience unlike the earlier system, wherein the farmers and dealers had to travel to the respective auction centre for participating in the auction. The Board continued to run the cloud based live e-auction system during FY 2024-25 as well. The cloud based live e-auction system helped increase the buyer participation in the auction, thereby enabling better price realisation. During 2024-25, a total quantity of 23,335 MT of cardamom (small) was sold through e-auction/ manual auction with weighted average price of ₹2575.98/kg.

B. Trade Promotion

a. Participation in Trade fairs/ meetings/ seminars/ trainings

Spices Board functions as an international link between the Indian exporters and the importers



abroad. As part of its initiatives for promotion of Indian spices in international markets and to provide opportunities for exporters, the Board participates in international fairs, exhibitions, etc., to showcase the capabilities of Indian spices to the international buyers.

The Board also encourages exporters to participate in the international trade fairs and exhibitions abroad for promoting exports. The Board supports exporters in setting up their own stalls in international fairs to showcase their capabilities and capacities in the export of spices. Under the programme, an assistance of 50 per cent of the cost of stall rent subject to a maximum of ₹5.00 lakh for General category and 75 per cent of the cost of air fare subject to a maximum of ₹2.25 lakh as well as 75 per cent of the cost of stall rent, subject to a maximum of ₹7.50 lakh is provided for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, Himalayan States, State notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep). During 2024-25, the Board provided assistance to the tune of ₹62.61 lakh under this programme to 22 exporters.

b. Buyer seller meets, seminars and training programmes

In order to impart knowledge to stakeholders on export procedures, import documentation, etc., and to motivate them to enter spices business, the Board has been organising Entrepreneurship Development Training Programmes. Further, to facilitate the market linkages between buyers and sellers, the Board has been conducting Buyer Seller Meets targeting producers, exporters and importers of spices.

1) Buyer seller meets

With a view to promote the export of spices and to strengthen linkages for export sourcing of spices, the Board has been conducting Buyer Seller Meets (BSMs) which shall provide a platform for interaction between the spice growers, exporters, and importers for establishing direct market linkages.

(i) Buyer seller meets

The buyer seller meets facilitate direct interaction between the farmers' groups and exporters, and helps strengthen the export sourcing, besides facilitating information

| SI No | Name of the programme | Date |
|-------|---|-------------------|
| 1 | Buyer Seller Meet for Spices in Uttarakhand | 22 August 2024 |
| 2 | Buyer Seller Meet for Spices at Idukki, Kerala | 11 September 2024 |
| 3 | Buyer Seller Meet for Spices at Gangtok, Sikkim | 25 September 2024 |
| 4 | Buyer Seller Meet for Spices at Hubballi, Karnataka | 25 November 2024 |
| 5 | Buyer Seller Meet for Spices in Odisha | 7 December 2024 |
| 6 | Buyer Seller Meet for Spices in Jammu and Kashmir | 12 December 2024 |
| 7 | Buyer Seller Meet for Spices at Itanagar, Arunachal Pradesh | 23 January 2025 |
| 8 | Buyer Seller Meet for Spices at Ranchi, Jharkhand | 28 January 2025 |
| 9 | Buyer Seller Meet for Spices at Nizamabad, Telangana | 18 March 2025 |
| 10 | Food Safety and Market Linkage Programme, Nagpur, Maharashtra | 23 March 2025 |
| 11 | Food Safety and Market Linkage Programme, Chennai, Tamil Nadu | 24 March 2025 |
| 12 | Food Safety and Market Linkage Programme, Shillong, Meghalaya | 26 March 2025 |



exchange on the quality and safety requirements of the export sector. During 2024-25, the Board conducted the following buyer seller meets.

(ii) Entrepreneurship development programmes

Spices and value-added spice products have been registering a steady growth in world market, thereby enhancing the potential for entrepreneurial ventures in spice processing and value addition. Spices Board, so as to attract, motivate and equip the progressive stakeholders to enter into the spices business,

has been organising Entrepreneurship Development Training Programmes, involving participants from across India. The main purpose of the programme is to sensitize and educate the participants on various aspects of the spice export sector, including export documentation and procedure, quality and safety standards, regulatory requirements for exports, international marketing, export logistics, analysing export data and trends, etc. Details of such programme organised by the Board during 2024-25, are given below:

| Sl No | Name of the Programme | Date |
|-------|---|----------------------|
| 1 | Entrepreneurship Development Programme for spices exports, Unjha, Gujarat | 12-13 August 2024 |
| 2 | Capacity Building for the Spice Industry on EU Regulation for Sampling & Certification, Kochi, Kerala | 06-07 December 2024 |
| 3 | Capacity Building for the Spice Industry on EU Regulation for Sampling & Certification, Unjha, Gujarat | 09-10 December 2024 |
| 4 | Capacity Building for the Spice Industry on EU Regulation for Sampling & Certification, Mumbai, Maharashtra | 12- 13 December 2024 |

c. Geographical Indication Registration

Spices Board has obtained GI tags for five spices viz., Malabar Pepper, Alleppey Green Cardamom, Coorg Green Cardamom, Guntur Sannam Chilli, and Byadagi Chilli from the GI registry and is the registered proprietor of these five GI tagged spices.

C. Technological Interventions

a. Assistance to Spice Incubation Centres for Raising Entrepreneurship (ASPIRE)

The Board is implementing a programme for setting up of “Spice Incubation Centres” in identified expert institutions to support exporters, start-ups, SMEs, and entrepreneurs with innovative ideas. The objective of the programme is to guide and assist them in developing innovative products and processes in the spices sector.

Under this programme, one-time financial assistance of up to ₹10 lakh is provided to the expert institutions for developing necessary infrastructure.

Further, financial assistance of up to ₹10 lakh per incubatee is provided for undergoing incubation on selected project in the Spice Incubation Centres established by the Board in collaboration with the identified expert institutions.

The incubatees and expert institutions are selected through a selection process based on applications received.

At present, the Board has collaborated with the Technology Business Incubator (TBI) operated by the Agri-Business Incubation Society at the Directorate of Agribusiness Development (DABD), Tamil Nadu Agricultural University (TNAU), Coimbatore, and with the Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysore under ASPIRE programme.

M/s Sree Raja Rajeswari Traders has been selected as an incubatee at CFTRI Mysore, under the ASPIRE programme and is currently undergoing incubation for the project titled “Techno-



Commercial Applications of Spice Nutraceutical Nanoemulsions.”

During 2024-25, Board provided assistance of ₹20 lakh to two expert institutions and ₹2 lakh to an incubatee under the programme.

D. International Pepper Community (IPC)

The International Pepper Community is an intergovernmental organisation under the auspices of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP). The Community now includes India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Vietnam as permanent members and Papua New Guinea, and Philippines as associate members. The Community is a non-profit organisation designed as a platform to discuss the common issues and seek solutions for the betterment of global pepper industry. Representative of the member countries hold the office of the Chairman of IPC on rotation basis for a period of one year. IPC has formed different Standing Committees to frame policies and specific strategies in respect of Research & Development, Marketing and Quality Evaluation of Pepper for addressing current and emerging issues.

E. Major Interventions undertaken for Export of Spices

The General Administration of Customs of China (GACC), People's Republic of China (PRC), implemented the 'Regulations on the Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food', and has stipulated for registration of overseas production enterprises of 14 categories of food products, including spices during the year 2021. Accordingly, establishments involved in the production, processing and storage of the aforementioned categories of products, exported to China were formerly required by GACC to be registered in the China Import Food Enterprise Registration (CIFER) system.

During 2022-23, GACC bifurcated the procedure for registration of spices to ground and unground segments and registration of establishments involved in the production, processing, storage, and export of unground/unprocessed spices has been entrusted to the Department of Animal and Plant Quarantine (DAPQ) of GACC. Accordingly, the Board facilitated the DAPQ registration of exporters of unground spices to China and the list of registered exporters is updated periodically by adding new exporters.





TRADE INFORMATION SERVICE

Trade Information Service of the Marketing Department is responsible for the collection, compilation, analysis, and dissemination of statistics relating to exports, imports, area, production, auction, and domestic prices of spices.

The major source of information for compiling the estimated export/import of spices from India is the export/import data provided by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata/ Ministry of Commerce (MoC) website/Daily List of Exports (DLE)/Daily List of Imports (DLI) published by Customs. The Board is compiling the export details of spices on a monthly basis and import details of spices on an annual basis and the figures are disseminated to stakeholders through its website and Ministry/Departments on a regular basis. For this purpose, the Board regularly collects both the DLE and DLI from all major ports like Cochin, JNPT, Chennai, Tuticorin, Mundra, Kolkata, Petrapole, Mohadhipur, Raxual, Amritsar/ DGCI&S, Kolkata and information is also collected through the Regional Offices of the Board.

The Board compiles and disseminates information on prices of spices from major markets in India and abroad on regular basis to the end-users through its website and publications. The major sources for collecting the price details are agencies like India Pepper and Spice Trade Association, Agricultural Produce Marketing Committees, Merchants Associations, International Trade Centre, Geneva, International Pepper Community, Indonesia. All this information is also collected through online/offline mode through the Regional Offices of the Board and subscription to the international agencies.

The Board is responsible for the production development of cardamom (small & large), and the area, production and productivity of cardamoms are estimated by the Trade Information Service by the support of the field sample study conducted through

the field set up of the Board. Area and production of other spices are collected from the State Economics and Statistics/Agriculture/Horticulture Departments/DASD for compilation. Information on area and production of all spices has been disseminated through the Board's publications as well as the website to the stakeholders and policymakers.

As per the Registration of Exporters (Regulations), all the registered exporters of spices have to submit their quarterly export returns to the Board. Trade Information Service is compiling the Quarterly Export Returns submitted by the registered exporters and maintaining the database of exporter wise export of spices. By using this database, the details of leading exporters of each spice are compiled and used for official purpose/ dissemination to stakeholders based on their request.

Spices Board is conducting e-auction for trading of cardamom through e-auction centres developed by the Board at Bodinayakanur and Puttady. The details on daily auction quantity and average price of cardamom are compiled and published on a daily basis through the Board's website. The consolidated details on auction sale and average prices are compiled and disseminated through the Board's publication.

Weekly domestic prices of different spices for different markets centres are compiled and published through the publication of the Board namely *Spices Market* on a weekly basis (on website) for the benefit of stakeholders of the industry.

A. Area and Production of Spices

The area and production of cardamom (small) and cardamom (large) for 2024-25 compared to 2023-24 are given in Table I & II. The area and production of other spices are given in Table-III.



Table-I: Area and Production of Cardamom (Small)

| State | 2023-24 | | | | 2024-25 | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | Total Area (ha) | Yielding Area (ha) | Production (MT) | Productivity (Kg/ha) | Total Area (ha) | Yielding Area (ha) | Production (MT) | Productivity (Kg/ha) |
| Kerala | 40345 | 30949 | 22868 | 738.90 | 40345 | 30095 | 18310 | 608.41 |
| Karnataka | 25135 | 14666 | 867 | 59.17 | 25135 | 14694 | 902 | 61.40 |
| Tamil Nadu | 4930 | 2781 | 1495 | 537.73 | 4930 | 2727 | 1484 | 544.24 |
| Total | 70410 | 48396 | 25230 | 521.33 | 70410 | 47516 | 20696 | 435.57 |

Source: Estimate by Spices Board.

Table-II : Area and Production of Cardamom (Large)

| State | 2023-24 | | | | 2024-25 | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | Total Area (ha) | Yielding Area (ha) | Production (MT) | Productivity (Kg/ha) | Total Area (ha) | Yielding Area (ha) | Production (MT) | Productivity (Kg/ha) |
| Sikkim | 23312 | 17453 | 5280 | 302.50 | 23312 | 17550 | 5429 | 309.33 |
| West Bengal | 3305 | 3165 | 1069 | 338.00 | 3305 | 3187 | 1089 | 341.79 |
| Arunachal Pradesh | 12131 | 7078 | 1806 | 255.14 | 12438 | 7289 | 1864 | 255.65 |
| Nagaland | 6631 | 4431 | 1128 | 254.64 | 6694 | 4473 | 1165 | 260.47 |
| Manipur | 217 | 64 | 5 | 76.50 | 267 | 64 | 5 | 79.89 |
| Total | 45596 | 32191 | 9288 | 288.54 | 46017 | 32563 | 9552 | 293.33 |

Source: Estimate by Spices Board

Table-III: Major Spice Wise Area and Production in India

| Spices | 2023-24 | | 2024-25 * | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| | Area (ha) | Production (MT) | Area (ha) | Production (MT) |
| Pepper | 312902 | 126038 | 254597 | 77533 |
| Chilli | 965612 | 2909844 | 921540 | 2693265 |
| Ginger (fresh) | 194243 | 2333000 | 193258 | 2246292 |
| Turmeric (dry) | 292830 | 1063224 | 290939 | 1116124 |
| Coriander | 604075 | 836524 | 627008 | 869443 |
| Cumin | 1302336 | 894565 | 1094382 | 723795 |
| Celery | 4657 | 6882 | 4590 | 6636 |
| Fennel | 216019 | 376049 | 129858 | 243666 |



| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Fenugreek | 158203 | 249523 | 147000 | 226853 |
| Garlic | 388676 | 3315545 | 405115 | 3422491 |
| Tamarind | 35593 | 132429 | 39563 | 138113 |
| Clove | 1847 | 1015 | 1887 | 1031 |
| Nutmeg | 25743 | 18940 | 26204 | 19012 |
| Grand total including others | 5056599 | 12483215 | 4686713 | 11995594 |

Source: Directorate of Arecanut & Spices Development, Kozhikode; (*) :1st Advance Estimate

B. Auction Sales and Prices of Cardamom (Small)

The state-wise auction sales and weighted average price of cardamom (small) for 2024-25 (August 2024 – July 2025) and 2023-24 (August 2023- July 2024) are given in Table-IV.

Table IV: Auction Sales & Prices of Cardamom (Small)

(Qty. in Tonnes, Price in ₹/kg.)

| Centre | 2023-24 (August -July) | | 2024-25 (August –July) | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Quantity Sold | Wt. Avg Auction Price | Quantity Sold | Wt. Avg Auction Price |
| Kerala & Tamil Nadu (e-auction) | 29119 | 1763.89 | 23315 | 2575.94 |
| Karnataka | 11 | 1335.40 | 4 | 2229.23 |
| Maharashtra | 106 | 1916.09 | 17 | 2728.54 |
| Total | 29237 | 1764.43 | 23335 | 2575.98 |

Source: Reports received from licenced auctioneers

C. Prices of Cardamom (Large)

The average wholesale prices of cardamom (large) at Gangtok and Siliguri Markets for 2023-24 and 2024-25 are given in Table V.

Table V: Prices of Cardamom (Large)

(Price in ₹/kg)

| Centre | Grade | 2023-24 | 2024-25 |
|----------|----------|---------|---------|
| Gangtok | Badadana | 930.21 | 1481.25 |
| Siliguri | Badadana | 1177.90 | 1687.17 |

D. Prices of Other Major Spices

The average domestic prices of major spices are given below. These prices were collected from secondary sources like Chamber of Commerce,

Indian Pepper and Spice Trade Association, Market reviews prepared by the Merchants Associations, etc. Prices of major spices in important market centres are given in Table VI.



Table VI: Prices Of Major Spices in Important Market Centers

(Price in ₹/kg)

| Spice | Market | 2023-24 | 2024-25(*) |
|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| Black Pepper(MG-1) | Cochin | 572.83 | 656.78 |
| Chillies | Guntur | 161.30 | 124.85 |
| Turmeric | Chennai | 109.43 | 152.08 |
| | Nizamabad | 95.25 | 119.58 |
| Coriander | Chennai | 103.29 | 99.31 |
| | Ramganj Mandi | 75.23 | 72.60 |
| Cumin | Chennai | 554.08 | 374.33 |
| | Unjha | 425.70 | 235.64 |
| Fennel | Chennai | 279.00 | 159.81 |
| Fenugreek | Chennai | 101.30 | 115.44 |
| Garlic | Chennai | 105.55 | 174.71 |
| Poppy seed | Chennai | 1407.21 | 1407.96 |
| Ajwain seed | Chennai | 188.40 | 175.89 |
| Mustard | Chennai | 85.26 | 84.84 |
| Tamarind | Chennai | 113.43 | 137.05 |
| Saffron | Delhi | 166562.50 | 212145.83 |
| Clove | Cochin | 901.03 | 843.07 |
| Nutmeg (with shell) | Cochin | 229.89 | 242.26 |
| Nutmeg(without shell) | Cochin | 425.53 | 495.92 |
| Mace | Cochin | 779.04 | 917.80 |

(*) Provisional

E. Export Performance of Spices from India

The export of spices and spice products from India crossed an all-time high in FY 2024-25. During FY 2024-25, India exported 17,99,267 MT of spices and spice products valued at ₹39,994.48 crore (4,722.65 million US\$) as compared to 15,39,692 MT valued at ₹36,958.80 crore (4,464.17 million US\$) during 2023-24, registering an increase of 17 per cent in volume, 8 per cent in rupee terms of value, and 6 per cent in dollar terms of value.

The spice wise analysis shows that the export of pepper, cardamom (small& large), ginger, turmeric, cumin, celery, fennel, fenugreek, tamarind, spice

oils & oleoresins and curry powder & paste has registered increase both in quantity and value in 2024-25. In the case of coriander, there is a decline of 44 per cent in volume, 33 per cent in rupee terms and 35 per cent in dollar terms of value. In the case of chillies, there is an increase of 19 per cent in volume, decline of nine per cent in rupee terms and 11 per cent in dollar terms. In the case of nutmeg & mace, there is a decline of eight per cent in volume, 12 per cent in rupee terms and 14 per cent in dollar terms of value. In the case of mint products, despite the decline of one per cent in volume of export, the export value has increased by three per cent in rupee terms and one per cent in dollar terms of value as compared to last year.

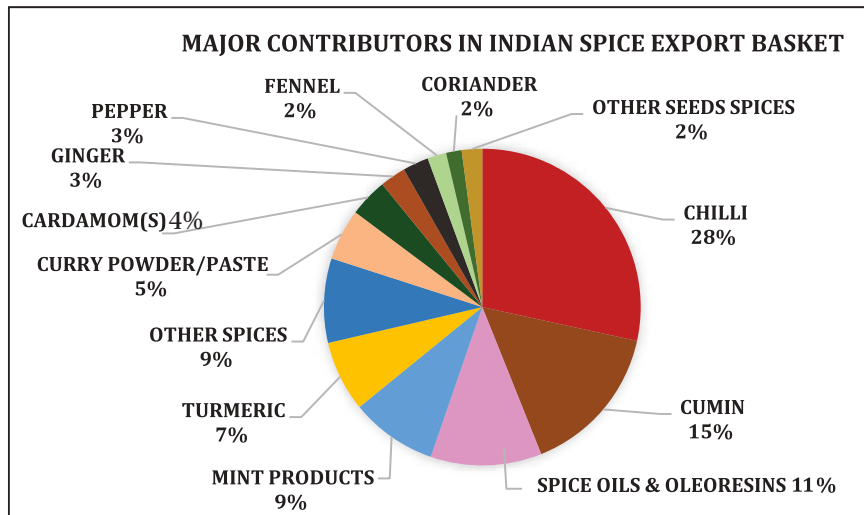




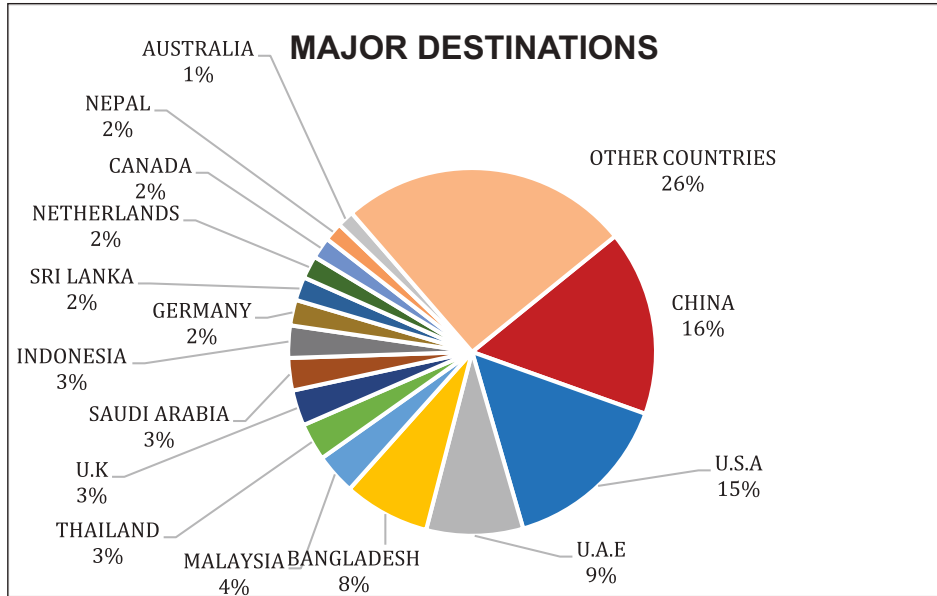
F. Major Contributors & Destinations during 2024-25

During 2024-25, the major contributors in spice export basket in terms of value were chilli (28%), cumin(16%), spice oil & oleoresins (11%), mint products (9%), turmeric (7%), curry powder/paste (5%), small cardamom (4%) ginger and pepper (3%), fennel and coriander (2%), which together contributed to more than 90 per cent to the total export earnings from spices.

The major export destinations for Indian spices were China (16%), USA (15%), UAE (9%), Bangladesh (8%), Malaysia (4%), Thailand (3%), UK (3%), Saudi Arabia (3%), Indonesia (3%) Sri Lanka (2%), Germany (2%), Netherlands (2%), Canada(2%), Nepal (2%), Australia (1%) Japan (1%), Russia (1%), Singapore (1%), France (1%), Mexico (1%), Vietnam (1%), Morocco (1%), South Africa (1%), and Korea (1%) contribute more than 85 per cent of the total export earnings of spices from the country



| Item | Value (Mn \$) | % Share |
|-------------------------|----------------|---------|
| Chilli | 1342.52 | 28 |
| Cumin | 732.35 | 16 |
| Spice Oils & Oleoresins | 535.92 | 11 |
| Mint Products | 417.8 | 9 |
| Turmeric | 341.54 | 7 |
| Other Spices | 406.54 | 9 |
| Curry Powder/ Paste | 247.59 | 5 |
| Cardamom (S) | 184.65 | 4 |
| Ginger | 124.78 | 3 |
| Pepper | 124.54 | 3 |
| Fennel | 90.93 | 2 |
| Coriander | 74.84 | 2 |
| Other Seeds Spices | 98.65 | 2 |
| Total | 4722.65 | |



| Country | Value (Mln \$) | % Share |
|-----------------|----------------|------------|
| China | 769.58 | 16 |
| USA | 711.16 | 15 |
| UAE | 401.73 | 9 |
| Bangladesh | 357.96 | 8 |
| Malaysia | 169.73 | 4 |
| Thailand | 154.98 | 3 |
| UK | 148.24 | 3 |
| Saudi Arabia | 134.6 | 3 |
| Indonesia | 134.41 | 3 |
| Germany | 106.37 | 2 |
| Sri Lanka | 97.55 | 2 |
| Netherlands | 94.81 | 2 |
| Canada | 88.88 | 2 |
| Nepal | 77.24 | 2 |
| Australia | 69.5 | 1 |
| Other Countries | 1205.91 | 26 |
| Total | 4722.65 | 100 |



PUBLICITY AND PROMOTION

During the period between April 2024 to March 2025, the Publicity and Promotion Section carried out various activities for enhancing the reputation of Spices Board and for promotion of Indian spices aiming at increased export of spices from the country. Every promotional avenue was leveraged to ignite public interest in Indian spices, value-added spice products, culinary applications of spices, and their potential health contributions. Information on the activities and schemes of Spices Board were also disseminated using various channels during the period 2024-25.

The major highlights of 2024-25 include participation in trade fairs / exhibitions, advertisement campaigns, online promotional campaigns, and printing and publication of magazines, brochures, etc.

A. Participation in Exhibitions/Trade Fairs

Attending trade shows and exhibitions is a powerful way to connect with different players in the global spice industry. During the financial year, the Board ensured its participation in major trade fairs and the list of fairs attended is given below;

List of Domestic Fairs Participated by Spices Board

| SI No | Event Name | Place | Event Date |
|-------|--|---|----------------------|
| 1. | Annapoorna Inter Food 2024 | IICC, New Delhi | 5-7 June 2024 |
| 2. | International Seminar on Spices 2024 | College of Agriculture, KAU, Vellayani, Trivandrum | 5-7 June 2024 |
| 3. | Biofach India 2024 | India Exposition Mart Ltd (IEM), Greater Noida, Delhi - NCR | 3 - 5 August 2024 |
| 4. | CII Eastern Region EXIM Conference 2024 | Kolkata | 20 August 2024 |
| 5. | Anuga Select India 2024 | Bombay Exhibition Centre, Mumbai | 28-30 August 2024 |
| 6. | CII Kerala Global Ayurveda Summit and 11 th edition of the CII Kerala Health Tourism 2024 | Kochi, Kerala | 29-30 August 2024 |
| 7. | World Food India 2024 | Pragathi Maidan, New Delhi | 19-22 September 2024 |
| 8. | Fi India 2024 | Bangalore International Exhibition Centre, Bengaluru | 25-27 September 2024 |
| 9. | Shining Uttar Pradesh 2024 | Varanasi | 27-29 September 2024 |



| | | | |
|-----|--|-------------------------------|---------------------------|
| 10. | Industry Interaction Meet with Secretary Commerce, Govt. of India (MoU signing ceremony between Spices Board and 'House of Himalayas Ltd.' & 'State Horticulture Mission (Uttarakhand)') | Dehradun | 09 October 2024 |
| 11. | SARAS Mela | Leisure Valley Park, Gurugram | 13 - 29 October 2024 |
| 12. | India International Trade Fair | Pragati Maidan, New Delhi | 14-27 November 2024 |
| 13. | 21 st Kolkata Foodtech-2024 | Kolkata | 29 November - 01 Dec 2024 |
| 14. | SIAL India 2024 | New Delhi | 5-7 December 2024 |
| 15. | Coffee Conference 2024 by Karnataka Growers Federation | Sakleshpur | 23 December 2024 |
| 16. | Indus Food 2025 | Greater Noida, NCR | 8-10 January 2025 |
| 17. | Silver Jubilee Foundation Day Celebrations of ICAR-NRCSS | Ajmer | 19 January 2025 |
| 18. | Republic Day Celebrations at District Administration, Alluri Sitharama Raju district | Paderu | 26 January 2025 |

List of International Fairs Participated by Spices Board

| Sl. No. | Event Name | Place | Event Date |
|---------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Shanghai International Condiment and Food Ingredients Exhibition 2024 | Shanghai, China | 28-30 August 2024 |
| 2 | Fine Food Australia 2024, | Melbourne, Australia | 2-5 September 2024 |
| 3 | World Food Moscow 2024 | Moscow, Russia | 17-20 September 2024 |
| 4 | SIAL Paris 2024 | Paris, France | 19-23 October 2024 |
| 5 | Food Ingredients North America 2024 | Las Vegas, USA | 30-31 October 2024 |
| 6 | Gulfood Manufacturing 2024 | Dubai, UAE | 5-7 November 2024 |
| 7 | Food Ingredients Europe 2024 | Frankfurt, Germany | 19-21 November 2024 |
| 8 | Foodex Japan 2025 | Tokyo, Japan | 11-14 March 2025 |
| 9 | IFE Manufacturing 2025 | London, UK | 17-19 March 2025 |



B. Online Promotional Campaigns

The publicity department made use of the various social media platforms like X (Twitter) Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn for promotion of Indian spices and Spices Board's activities in 2024-25. Designed to educate the online viewers, the social media campaigns created awareness on spices including its botanical and geographical information, trade data, therapeutic and culinary aspects, etc.

C. Spice Xchange India- Spices Board's B2B Portal

Launched on 20th January 2022, Spice Xchange India (www.spicexchangeindia.com) serves as the Spices Board's innovative 3D virtual portal, strategically designed to bridge market gaps exacerbated by the COVID-19 pandemic. This B2B platform is poised to unlock substantial business prospects for Indian spice entrepreneurs. Offering round-the-clock virtual office spaces, an AI-driven recommendation system, market insights, and access to global spice trade data, Spice Xchange India aims to streamline business operations and enhance accessibility. Recognised as a pivotal initiative by the Board, this portal has been supporting entrepreneurs in the spices sector throughout the 2024-25 period.

D. Periodicals

a. Spice India

The periodical publication, Spice India is being published in five different languages; English,

Hindi, Malayalam, Kannada, and Tamil, as a monthly. The periodicals were published regularly during this period.

b. Foreign Trade Enquiries Bulletin

The Spices Board curates and releases a bulletin known as the Foreign Trade Enquiries Bulletin (FTEB), consolidating trade inquiries sourced from overseas trade fairs, emails, and direct inquiries to the Board's offices. This bulletin serves to facilitate the export of spices by providing valuable trade leads and opportunities. Subscribers receive this publication via email for easy access and utilisation.

c. Other Publications

Brochures, pamphlets, and panels related to spices, use of spices, value added spice products, etc., were printed during 2024-25.

E. Release of Advertisements

Advertisements on vacancies in Spices Board, tenders, etc., were released during the year. Besides these, advertisements on general information on Spices Board and for promotion of cardamom and advertorials were also released through various newspapers and magazines.

F. Press Releases

Press releases detailing the export performance and trends, initiatives, activities, and major events organised by Spices Board, etc., were released during FY 2024-25.





QUALITY IMPROVEMENT

The Quality Evaluation Laboratory (QEL) of Spices Board at Kochi was established as the Board's first of its kind laboratory in the year 1989. QEL, Kochi is certified under ISO 9001 Quality Management System since 1997, ISO 14001 Environmental Management System since 1999 by the British Standards Institution (BSI), U.K and is also accredited under ISO/IEC:17025 Laboratory Quality Management System since September 2004 by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), Quality Council of India (QCI), Govt. of India. Quality being considered the prime commitment, QEL, Kochi has always maintained and continues to maintain its credentials by consistently upgrading the quality systems. The lab is also certified under the latest upgraded systems, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 by the BSI, and accredited under ISO/IEC 17025:2017 (NABL-FSSAI Integrated) by the NABL.

With the objective that spices exported from India conform to specifications laid down by appropriate national/ international organisations and also to provide the customers, timely, reliable, and accurate test results, Spices Board has expanded its reach throughout India by establishing Regional Quality Evaluation Laboratories. Seven Regional QELs are now in operation at major exporting centers, viz. Chennai, Guntur, Mumbai, New Delhi, Tuticorin, Kandla, and Kolkata, and basic testing facility for cumin and other seed spices at Spices Park, Jodhpur and laboratory for testing pesticide residues in small cardamom at Myladumpara, Idukki. The laboratories at Kochi, Mumbai, Guntur, Chennai, New Delhi, Tuticorin, and Kandla are accredited under ISO/IEC 17025:2017 by the NABL, and QEL Kolkata is in the process of obtaining accreditation.

QELs undertake analysis of samples under the Board's mandatory sampling and testing of export consignments, provide analytical services to the Indian spice industry and help monitor the quality of spices produced and processed in the country. The laboratories are equipped with sophisticated instruments to undertake the analysis as per the requirements of the importing countries. The documents pertinent to analytical services of the laboratory, including the generation of worksheets and submission of analytical results, are made online through a software system called "QUADMAS" and the same is being constantly updated.

A. Analytical Services

The scope of testing of Quality Evaluation Laboratories is available on the Spices Board website under the main head – Quality and sub-head - Analytical Services and Fees. During the financial year 2024-25, the QELs of the Board continued providing services for the following analysis under the mandatory testing of export consignments of spices and spice products:

1. Testing for aflatoxins and sudan dyes (I to IV) in chilli (crushed, powder and ground), chilli seed, curry powder, curry masalas, curry pastes, and turmeric powder and its products (except sliced).
2. Testing for aflatoxins in chilli whole, turmeric (whole and sliced), ginger and its products, nutmeg and its products, mace and its products, and ready-to-eat items.
3. Testing for pesticides (114 pesticides) in curry leaves.
4. Testing for extraneous matter and other seeds in cumin seeds.



5. Testing for ethylene oxide (EtO) in chilli, ginger, pepper, pimenta (allspice), vanilla, cinnamon and cinamon-tree flowers, cloves (whole fruit, cloves and stems), nutmeg, mace, cardamoms, seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin/ caraway, juniper berries, saffron, turmeric, & other spices, food supplements containing botanicals, mustard seeds, mustard flour, mustard meal and prepared mustard, thyme, laurel/ bay leaves/ curry leaves, basil, rosemary, sage, parsley, tarragon, celery, spice mix (masalas, curry gravy) ready - to - eat items, ready - to - cook products, sauces and preparations, mixed condiments, and mixed seasonings.
6. Testing for *Salmonella* in chilli (whole, crushed, and ground), chilli seed, curry powder and curry masalas, curry pastes, and cumin seeds and ground.
7. Testing for pesticide residues (Triazophos, Iprobenfos, Profenofos, Chlorpyrifos, Ethion, Methyl Parathion, Parathion and Phorate) in chilli (whole, powder, seed, crushed and

- ground), curry powder and curry masalas, curry pastes, cumin seeds, cumin (crushed and ground), turmeric (whole, dried, sliced/ split and powder), cardamom (whole and ground), black pepper (whole and ground), and fenugreek (whole and ground).
8. Testing for pesticide residues (Carbosulfan, Chlorpyrifos, Carbendazim, Cyfluthrin, Beta-Cyfluthrin, Cypermethrin, Beta-Cypermethrin, Malathion, Disulfoton, Acephate and Profenofos) in cumin (seed, ground, crushed) for consignment for export to China and 190 pesticides for consignment for export to the EU
9. Analysis of piperine and oleoresin content in imported black pepper consignments.

QEL, Kochi included EtO as a parameter in its analytical service for mandatory testing with effect from 1st June 2024. The laboratory had analysed a total of 1,79,654 parameters including aflatoxin, illegal dyes, pesticide residues, extraneous matter, other seeds, EtO and *Salmonella* during the financial year 2024-25.

| QEL | No. of Samples Received | No. of Parameters Tested | No. of Mandatory Samples Tested |
|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kochi | 18983 | 37675 | 34537 |
| Kandla | 18147 | 37527 | 37342 |
| Chennai | 20526 | 26950 | 20417 |
| Mumbai | 19292 | 36865 | 32780 |
| Narela | 2839 | 6232 | 5964 |
| Tuticorin | 4815 | 10196 | 10190 |
| Guntur | 11200 | 19319 | 18455 |
| Kolkata | 3913 | 4684 | 4665 |
| Jodhpur | 103 | 206 | 206 |
| Total | 99818 | 179654 | 164556 |

Rejections of spice exports due to food safety and quality issues from importing countries were monitored and reviewed to assess the need for expansion of the scope of mandatory sampling and testing of export consignments.

B. Human Resources Development Programme

During the period, as a part of improving the technical capabilities of the QEL staff and to meet the requirements of various Quality Systems



adopted by the laboratories, the following national/international training programmes/workshops were attended by the scientific and technical staff:

1. Scientist C, Senior Chemist, and Junior Chemist from QEL, Kochi attended the 'Internal auditor Training Programme on ISO 9001:2015 Quality Management System' conducted by Kerala State Productivity Council, Kalamassery, Kerala, from 25 June 2024 to 26 June 2024.
2. Junior Chemists from QEL, Kochi attended a training on 'Method Validation, Verification and Measurement Uncertainty as per ISO/IEC 17025:2017' conducted by Sophisticated Test and Instrumentation Centre (STIC), Cochin University for Science and Technology (CUSAT), Kochi from 22 July 2024 to 23 July 2024.
3. Scientist C, QEL, Chennai attended a workshop on 'Crop Grouping Principles of Data Generation and Maximum Residue Limit (MRL) setting in India' at Habitat Centre, New Delhi on 26 July 2024.
4. Scientist C, QEL, Chennai attended FAD 9 (Spices Technical Committee), 'One-day Workshop-cum-Brainstorming Session for Technical Committee Members' at Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi on 20 August 2024.
5. Scientist C, QEL, Kochi attended a 'Workshop on the Analysis of Mineral Oil Components in Food' conducted by Hydrocarbon Solutions, Bengaluru on 30 August 2024.
6. Scientist C, QEL, Guntur attended 'NABL Assessors' Training Course based on ISO/IEC 17025:2017' at Hotel The Chancery Pavilion, Bengaluru, Karnataka from 18 November 2024 to 22 November 2024.
7. Scientist A, QEL, Chennai attended the 'National Mass Spectrometer Conference' conducted by Spinco Chennai and Shimadzu Japan at ITC Grand Chola, Chennai on 20 November 2024.
8. Senior Chemist and Junior Chemist from QEL, Kochi attended "Capacity Building Programme on EU Regulations for sampling and certification of spices" at Monsoon Empress, Kochi from 06 June 2024 to 07 June 2024.
9. Scientist C, QEL, Kandla attended "Capacity Building Training Programme on EU regulations for Sampling and Certification for the Spice Industry" at Unjha, Gujarat from 09 December 2024 to 10 December 2024.
10. Scientist C, QEL, Mumbai, and Scientist A, QEL, Chennai attended the "Capacity Building Programme on EU Regulations for Sampling and Certification of Spices" at Navi Mumbai from 12 December 2024 to 13 December 2024.
11. Scientist C, QEL, Chennai attended a training programme on "ISO Online Standards Development" conducted by BIS- National Institute of Training Standardisation (NITS), Noida on 18 December 2024.
12. Junior Microbiologist, QEL, Kochi attended a virtual training on 'Method Verification and Validation for Microbiological Testing, conducted by Training and Capacity Building (TCB) Division, QCI on 28 December 2024.
13. Junior Chemist, QEL, Kolkata attended a virtual training on "Method Validation and Verification for Chemical Analysis (Covering Pesticide Residue, Contaminants and Nutritional Analysis)" from 20 January 2025 to 21 January 2025.
14. Scientist C, QEL, Chennai attended a virtual training on "ISO 13528 2022 Statistical Methods for use in Proficiency Testing" from 10 February 2025 to 11 February 2025.
15. Scientist C, QEL Kochi attended "Better Training for Safer Food (BTSF) Training on Sampling and Analysis of Mycotoxins in Food" at the National Institute of Health, Rome, Italy, from 10 February 2025 to 21 February 2025.
16. Junior Microbiologist, QEL, Chennai attended a virtual training on "Method Verification and



Validation for Microbiological Testing as per the ISO 16140-3 standard' conducted by Training and Capacity Building Cell, QCI, on 28 February 2025.

C. Training Programmes

a. Training programmes conducted for the industry

1. QEL, Kochi conducted three training programmes for the officials from spices industry; (a) Training Programme on Physical, Chemical Analysis of Spices/Spice Products from 29 April 2024 to 03 May 2024, (b) Training Programme on GC-MS/LC-MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Spices and Spice Products from 20 January 2025 to 24 January 2025 and (c) Training Programme on Analysis of Mycotoxins and Illegal Dyes in Spices and Spice Products from 20 January 2025 to 24 January 2025. A total of 13 participants from various spice export/processing units, private testing laboratories, and national research institutes attended the training programmes.
2. QEL, Chennai conducted an awareness programme on EtO regulations (online session) for stakeholders in the spices sector on 11 July 2024, which had 60 participants.

b. Training programmes for which the laboratory staff attended as resource personnel

1. Scientist C, QEL, Kochi was a panel speaker for the Workshop on Monitoring of Pesticide Residues at National Level, conducted at Indian Council for Agricultural Research (ICAR), Delhi on 08 August 2024.
2. Scientist C, QEL, Kochi was an invited speaker for the DBT programme on aromatic plants conducted by Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute (JNTBGRI), Palode, Trivandrum, on 27 August 2024.

c. Student internship/academic project works

QEL, Kochi provided guidance/ dissertation facilities to two students of Post Graduation, three

students of Under Graduation, and internship facilities to one student of Under Graduation and one student of Post Graduation from different colleges/universities.

D. Participation in Meetings of National and International Importance

1. Scientist C, QEL, Kochi attended a review meeting on 'Monitoring of Pesticide Residues in National Level' at Delhi on 07 May 2024.
2. Scientist C, QEL, Kochi attended the 32nd meeting of ISO/TC-34/SC-7 Spices Committee at AFNOR, Paris, France, from 17 June 2024 to 20 June 2024.
3. Scientist C, QEL, Kochi attended a 'Working Group Meeting on ISO standard for saffron' (Online) on 25 July 2024.
4. Scientist C, QEL, Chennai attended the FAD 9 one-day workshop-cum-brainstorming session for Technical Committee Members by BIS at Faridabad on 20 August 2024.
5. Scientist C, QEL, Chennai attended the 'Committee meeting for 2nd Global Food Safety Summit' at Nirman Bhavan, New Delhi on 21 August 2024.
6. Scientist C, QEL, Chennai attended a meeting with the Central Insecticides Board and Registration Committee (CIB&RC) Secretary regarding extension of label claims in spices at Krishi Bhawan, New Delhi on 21 August 2024.
7. Scientist C, QEL, Chennai attended the 10th meeting (virtual mode) of FAD27 (Pesticide Residues analysis Sectional Committee) as convener of Panel 2 for the development of an analytical method for pesticide residue analysis in spices on 27 August 2024.
8. Scientist C, QEL, Kochi attended the FAD 9 (Spices Technical Committee) meeting at BIS, New Delhi on 26 September 2024.
9. Scientist C, QEL, Kochi attended a virtual meeting on the 'EU's decision on lowering of MRLs of various pesticides to the limit of





purchased a Vertical Laminar Air Flow Unit for sub-sampling in the Microbiology section.

2. QEL, Mumbai augmented the analytical infrastructure by adding a new LC-MS/MS (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry) system. The new LC-MS/MS is used for the analysis of synthetic food dyes and pesticide residues.

I. CODEX, ISO, and IS Related Activities

1. Scientist C, QEL Kochi is functioning as the Chair for EWG on the CODEX draft standard for dried and dehydrated coriander.
2. Scientist A, QEL Chennai is functioning as the Co-chair for EWG on the CODEX draft standard for vanilla.
3. Scientist C, QEL Guntur is a member of the EWG on the CODEX draft standard for sweet marjoram.
4. Scientist C, QEL Kandla is a member of the EWG on the CODEX draft standard for cinnamon.
5. Scientist C, QEL Kochi is the convenor of ISO/TC 34/SC 7/WG 9, is coordinating the revision of ISO standards 951-1 and 951-2 – black and white pepper.
6. Scientist C, QEL Kochi is the project leader for the revision of ISO 5562 turmeric (ISO/TC 34/SC 7/WG 10)
7. Scientist C, QEL Kochi is the project leader for the revision of ISO 11027 method of analysis of piperine in black pepper.
8. Scientist C, QEL Kochi is a member of ISO/TC 34/SC 7/AHG 1 horizontal standard for the herb and spice adulteration detection.
9. Scientist C, QEL Kochi and Scientist C, QEL Chennai are members of ISO/TC 34/SC 7/WG 7 on *Zanthoxylum Pericarpium*.
10. Scientist C, QEL Kochi is a member of ISO/TC 34/SC 7/WG 8 on dried lime.
11. Scientist C, QEL Kochi, Scientist C QEL Narela, and Scientist C, QEL Chennai are members of ISO/TC 34/SC 7/WG 11 on saffron.

12. Scientist C, QEL Kochi, and Scientist A, QEL Chennai, are members of ISO/TC 34/SC 7/WG 12 on vanilla.

13. Scientist C, QEL Kochi is a member of ISO/TC 34/SC 7/WG 13 on lemon grass.

14. Scientist C, QEL, Kochi is a member of FAD 9/ Panel 1 for the revision of specifications for oleoresins of chilli, ginger, black pepper, and turmeric.

15. Scientist C, QEL Kochi is a member of the technical evaluation committee for the FAD 9 Research and Development project on the Study of Asafoetida for determining its quality and safety parameters.

J. Strengthening of Analytical Laboratory Network for Spices (ALNS) through Laboratory Empanelment Scheme

Food quality and safety have emerged as key differentiators in the highly competitive global food market. While India holds the distinction of being the world's largest producer, consumer, and exporter of spices and spice products, maintaining and advancing this leadership position requires sustained efforts to enhance product safety, quality assurance, and processing infrastructure. To this end, the Spices Board India continues to play a pivotal role in monitoring and controlling the quality of spice exports through a combination of mandatory and voluntary testing programmes. These activities are carried out through the Board's network of Quality Evaluation Laboratories (QELs), strategically located across the country.

In a bid to strengthen and expand its quality and safety testing framework, the Board launched an initiative in 2022 to empanel private and government laboratories accredited under ISO/IEC 17025:2017. These laboratories are assessed for their capabilities to test specific parameters mandated by the Board and are integrated into its laboratory ecosystem to support ongoing testing efforts. The primary objective of this empanelment scheme is to reduce the turnaround time (TAT) for



ANNUAL REPORT 2024-25



testing, by ensuring laboratory accessibility near key spice-producing regions and major export hubs. Moreover, this initiative enables the Board to promptly meet testing requirements raised by importing countries and harness the technical expertise and advanced infrastructure of the private sector for the overall development of India's spice export industry.

As of now, the Board's eight QELs, along with the empanelled laboratories, form a cohesive testing framework, the Analytical Laboratory Network for Spices. Within this structure, QELs serve as the core institutions conducting testing, while the empanelled laboratories operate as secondary

support units to augment capacity and geographic reach. To institutionalise the empanelment process, the Board published a comprehensive *Manual on Laboratory Empanelment Scheme* in 2022, detailing eligibility criteria, roles, responsibilities, and procedural guidelines. This manual was further revised in 2024 to align with emerging industry needs and regulatory challenges. In 2023, the Board assigned the NABL, under QCI, to verify compliance with the empanelment requirements as part of their integrated assessment process. At present, 11 laboratories have been empanelled for mandatory testing activities, and further expansion of the network is actively underway.





CODEX CELL AND INTERVENTIONS

A. Overview on Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)

The Codex Alimentarius Commission (CAC) is an international, intergovernmental body under the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) and World Health Organisation (WHO), with membership of over 189 countries, based in Rome and tasked with formulating internationally accepted standards pertaining to food. The food standards developed by Codex are recognised by the World Trade Organisation (WTO) as international reference points for the resolution of disputes concerning food safety and consumer protection. The CAC conducts its work through various Codex committees, hosted by different member countries of Codex.

Considering the fact that international spice trade was being affected by the lack of worldwide harmonised standards, a proposal for the constitution of a new Codex committee for Spices and Culinary Herbs was initiated in Codex by India in 2012, at the behest of Spices Board. The Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) was approved at the 36th Session of the CAC held at the FAO Headquarters, Rome during July 2013. The committee got established with the support of over 105 member countries; with India as the host country and Spices Board as the host organisation.

The scope of work of the CCSCH committee includes harmonisation of global standards for quality parameters in spices and culinary herbs, taking into consideration the international and national legislations, other available standards and specifications. These Codex standards are voluntary and are used by member countries to harmonise and align their national regulations.

Codex standards are also referred by WTO in arbitration of international trade disputes.

The CCSCH Committee is hosted and chaired by India, with Spices Board India as its permanent Secretariat. Dr M.R. Sudharshan (Retired Director Research, Spices Board) is the present Chairman of this Committee.

So far, seven sessions of the committee have been organised by Spices Board on behalf of India. The CCSCH1 session was held in 2014 at Kochi, CCSCH2 in 2015 at Goa, CCSCH3 in 2017 at Chennai, and CCSCH4 in 2019 at Thiruvananthapuram. Due to COVID-19 pandemic, two sessions were held virtually, viz. CCSCH5 in fully virtual mode during April 2021 and CCSCH6 with a full physical head table and delegates attending online, during September- October 2022. The seventh session was held at Kochi during January 2024.

B. Adoption of New Standards for Spices and Culinary Herbs Adopted by Codex

The 47th session of the Codex Alimentarius Commission (CAC47) held at Geneva, Switzerland during November 2024 adopted three more spice standards developed by the CCSCH committee viz., turmeric, small cardamom and the group standard for dried or dehydrated fruits and berries – allspice, juniper berry, and star anise. Presently, a total of 14 full-fledged spice standards comprising of 16 spices are published and available under Codex.

C. Codex Committee on Spices and Culinary Herbs- 8th Session

The eighth session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH8) is scheduled to be held during 13-17 October 2025. Currently, development



of five new Codex standards on spices, viz., vanilla, sweet marjoram, coriander, large cardamom, and cinnamon, are progressing to be taken up in the upcoming session. Spices Board Scientist on behalf of India is chairing the electronic working group (EWG) on the development of coriander standard. Also, scientists from Spices Board are participating as members in the EWG for other spice standards that are currently being developed. Communication has been initiated with Ministry of Commerce (MoC) during December 2024, for seeking approval to organise the eighth session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs.

D. Codex Committee on Contaminants in Foods -17th session

The 17th session of Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF17) held during April 2024 at Panama City was attended by Spices Board official who had functioned as the chair of the electronic working group on development maximum limits for mycotoxins in spices. During the meeting, committee recommended to advance the sampling plan for testing mycotoxins in spices to the next step in Codex procedure, and also agreed to the India's proposals on decision rule and aggregate sample weight.

Development of maximum levels (MLs) for Lead contaminant spices also progressed under this committee session. The 47th Session of the Codex Alimentarius Commission (CAC47) held at Geneva, Switzerland during November 2024 adopted Lead MLs for dried aril, dried floral part, dried fruits and berries, dried paprika and sumac, dried Sichuan pepper and star anise, dried rhizomes and root, and dried seeds. MLs for lead in dried bark and dried culinary herbs were also adopted. CAC47 noted India's concern about the approach taken for setting group MLs for spices, which might lead to uneven distribution of samples, resulting in potentially unrepresentative MLs. CAC47 also encouraged member countries to respond to the call for data to facilitate discussion and decision-making at CCCF18 (2025).

Presently, Spices Board scientist on behalf of India is chairing the electronic working group on the subject 'sampling plans for total aflatoxins and ochratoxin A in certain spices (dried chilli pepper, nutmeg, and paprika)'.
'

E. Techno-scientific Committee for Monitoring Export Rejections

A techno-scientific committee was constituted in Spices Board for monitoring export rejections of Indian spices and other technical matters concerning quality and safety of Indian spices. Till March 2025, 15 sessions have been convened which analysed the root causes for the export rejections that occurred during this period and submitted recommendations to the Board.

F. National Committee on Spices Quality and Safety (NCSQS)

Spices Board India, under the Ministry of Commerce and Industry, has constituted an advisory committee, viz., the 'National Committee on Spices Quality & Safety' (NCSQS) with representatives from various departments, institutions and stakeholders of the spice sector to address the challenges and technical issues affecting the Indian spices and their exports, including quality and safety concerns.

The third session of the National Committee on Spices Quality and Safety (NCSQS3) was held on 24 October 2024 in hybrid mode. The session was chaired by the Director (Research), Spices Board. Eminent experts from the regulatory sector like Secretary CIB & RC, Advisor Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) along with the members of the committee across the Indian spice sector attended the session. The committee discussed the key issues faced by spices sector, like expansion of label claims of pesticides for use in spices and regulatory status of ethylene oxide in India under FSSAI, and charted out specific action plans, and the works are currently progressing.

Codex cell assists in organising the meeting, preparing agenda, minutes of the meeting, etc.



G. ISO TC34/SC7

The ISO TC34/SC7 is a subcommittee under International Organisation for Standardisation (ISO) that develops ISO standards for spices, culinary herbs and condiments. Director Research, Spices Board by designation is the chair of this ISO subcommittee. The 32nd meeting of ISO/TC 34/SC7 and related working group was held during 17 to 20 June 2024 in Paris, France. Dr A.B. Rema Shree, Director (Research), Spices Board attended and chaired the meeting. A scientist from the Quality Evaluation Laboratory at Kochi also attended the meeting as the member of the committee.

Work on new ISO standards, and the revision of some of the existing ISO standards are progressing in this committee. Also, 51 ISO standards were reviewed by the committee. The committee agreed to launch new work item proposal for eight specifications/test methods for development of new standards. Spices Board scientists on behalf of India are leading various working groups constituted for development/revision/new work proposals for spice standards. At present, 80 ISO spice standards have been published under the responsibility of the TC 34/SC7 committee.

H . Spices, Culinary Herbs and Condiments Sectional Committee, FAD 9

Spices, Culinary Herbs and condiments sectional committee FAD-9 deals with

- Development of Indian Standards (IS) of Spices, Culinary Herbs and Condiments
- General methodology for quality evaluation including nutritional aspects, and
- Liaison with ISO/TC 34/SC 7 Spices, Culinary Herbs and condiments subcommittee.

Dr A. B. Rema Shree, Director (Research), Spices Board India is the Chairperson of this committee and chaired four sessions during this period; FAD9 23rd meeting on 19 April 2024, FAD9 24th meeting on 26 September 2024, FAD9 25th meeting on 04th December 2024, and FAD9 26th meeting on 20 March 2025.

The committee session finalised the list of Indian Standards which are due for revision in order to commence action and to undertake modified adoption of draft Indian standards for finalisation. An R&D project that was approved for the Study of Asafoetida to determine the quality and safety parameters for developing the standard, was reviewed.





EXPORT ORIENTED RESEARCH

Indian Cardamom Research Institute (ICRI) focused its research efforts on crop improvement, biotechnology, crop production, crop protection, and post-harvest studies. The focal areas of research were nutrient management and soil analysis, crop protection strategies employing Integrated Pest and Disease Management techniques for both small and large cardamom. Moreover, ICRI extended the fruits of its research as technologies to farmers and targeted groups through extension activities like advisory services, hands on training on bioagent production, scientist-farmer interface sessions, mobile spice clinics, webinars, workshops, training programmes and dissemination via audio-visual media and publications. Emphasising sustainability, ICRI spearheaded efforts to minimise pesticide usage in cardamom cultivation. It advocated the adoption of Integrated Pest Management (IPM), and Integrated Nutrient Management (INM) systems, as well as organic farming practices. Further, enhancing its capabilities, ICRI established a cutting-edge Quality Evaluation Laboratory at Myladumpara. In order to cater to the needs of spice farmers, with the assistance of State Horticulture Mission, Kerala, ICRI established twelve numbers of hi-tech polyhouses with automation for irrigation as well as relative humidity control for multiplication of black pepper and cardamom sucker nursery in the field. In addition, numerous collaborative research programmes were undertaken in the focal areas of research with Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Rubber Board, Kerala University of Digital Sciences, Innovation, and Technology, Kerala, National Information Centre (NIC), and pesticide manufacturers.

A. Crop Improvement

a. Small cardamom

A high yielding, superior, climate resilient small cardamom variety, ICRI 10 (ICRI Sugandha Bharathi) developed by ICRI, Spices Board, Myladumpara was released by the Kerala State Variety Release Committee on Agricultural and Plantation Crops during its 29th meeting held on 12 November 2024 at Thiruvananthapuram, which was chaired by Dr B. Ashok IAS, Agriculture Production Commissioner and Principal Secretary (Agriculture), Government of Kerala. The variety possesses prostrate panicles having a yield potential of 3,500 – 4,000 kg / ha under moderate management. The dry recovery of capsules is 23.5 per cent. Almost 80 per cent of the dried capsules are above seven (7) mm size and possess pale green colour. The plants are tolerant to drought conditions, diseases, thrips, and borer infestation. About sixty demonstration plots of the new variety have been established in the cardamom tracts of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka.

Mass multiplication of elite clones was carried out for experimental purpose and also to supply to farmers from ICRI Regional Station, Sakleshpur. MCC 260-(1000 nos), SHC 1-(500 nos) and SHC 2 – (500nos) and ICRI 5 – (500 nos) were supplied to needy farmers in Karnataka.

b. Large cardamom

Three large cardamom germplasm accessions, *Rambhangey*, *Darupatthey*, and *Golsey*, were collected from Darjeeling and Kalimpong



districts of West Bengal and Mangan district of Sikkim and also recorded passport data as per guidelines of Indian Council of Agricultural Research- National Bureau of Plant Genetic Resources (ICAR-NBPGR), New Delhi. In the evaluation of germplasm for superior traits, accession SCC 212 was found to be tolerant to blight disease. Under the hybridisation programme, eight hybrid lines were developed and are currently under various stages of evaluation for growth performance and disease resistance. Additionally, in a screening study involving ten genotypes under both controlled and artificially induced drought conditions using PEG 6000 (Polyethylene Glycol 6000), the Golsey cultivar exhibited the highest level of drought tolerance.

B. Biotechnology

Genetic diversity studies were conducted on 150 selected accessions of small and large cardamom using various molecular markers. Molecular characterisation and comparison of different landraces or farmers' varieties with ICRI varieties have been done. Transcriptome sequencing for small and large cardamom was carried out to identify disease-related genes, and differentially expressed related genes were screened. Molecular characterisation of *Fusarium* isolates from small cardamom of different locations were carried out. Gene sequencing of fifteen *Fusarium* isolates was carried out using selective primers. Development of viral diagnostics and specific primers for virus indexing has been initiated for speedy and accurate detection of viruses in seedlings and field-grown plants of small and large cardamom. DNA fingerprinting profiles of Indian cardamom and those of Guatemalan cardamom were studied.

C. Agronomy and Soil Science

a. Small cardamom

Dr K. G. Jagadeesha IAS, Secretary, Spices Board launched the 'CardsApp,' during "Spice Up Your Business: Stakeholders Conclave and Buyer Seller Meet" held at ICRI, Myladumpara

on 11th September 2024. This app with online fertiliser recommendation system provides vital soil test results, including a Soil Fertility Map, from samples collected across 19 villages in Udumbanchola and Idukki taluks - the regions known for cardamom cultivation potential. The project was undertaken in collaboration with Rubber Board and Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology. The app with online fertiliser recommendation system is expected to play a crucial role in increasing productivity by offering data-driven insights to farmers. The free android version of the CardSApp is available in play store and web page version is available in the link: <https://cardsapp.spicesboard.org.in/>, which is an online fertiliser recommendation system for small cardamom.

About 7,332 soil fertility parameters were tested from 935 soil samples of Cardamom Hill Reserve of Idukki district in Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka and recommendations were given for judicious application of fertilisers. Additionally, 528 soil fertility parameters from 44 soil samples in Sikkim were tested and reports provided for soil nutrient management. A total 377 soil samples from 226 farmers were analysed for available nitrogen and revenue of ₹40,716 was generated.

Application of 'Poly sulphate' which is a single source fertiliser with four nutrients at the rate of 200 kg/ ha resulted in significant improvement in yield and yield increase was about 37 per cent compared to standard practice of NPK application alone.

Regression models are developed to interpret the relationship of weather variables with growth parameters in cardamom. Combined application of recommended dose of fertiliser (RDF) and foliar spray of Nano urea recorded better growth and yield attributes as compared to foliar application of nano fertiliser alone or RDF under Karnataka conditions. Growth and yield attributes were significantly superior in



treatments where cardamom power mix (IISR Micronutrients Formulation for Cardamom) was used (189.9 kg/ha) as Compared to recommended package of practice under Karnataka conditions.

A research paper entitled 'Empowering farmers with site specific fertiliser recommendations: the case of Udumbanchola taluk Idukki utilising CardSApp' authored by Manoj Oommen, John Jo Varghese, Amith Mohan, Anuja V.R., Hareesh M., Pradeep B, T. Radhakrishnan, M.D. Jessy, A.B. Rema Shree received the best research paper award for the oral presentation under the sub theme Innovative Production Systems during the International Seminar on Spices, organised by Kerala Agricultural University, Vellayani during 5 -7 June 2024.

b. Large cardamom

A nursery study was conducted to evaluate suitable potting mixture for large cardamom. The polybag nursery plants potted with 1:1:1 mixture of forest soil, FYM, and vermicompost along with 10 g of *Vesicular Arbuscular Mycorrhiza* recorded to be the superior among the nine treatments evaluated.

D. Plant Pathology

a. Small cardamom

The commercially available new molecules of fungicides such as; Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3%, Propiconazole 13.9% + Difenconazole 13.9%, Pydiflumetofen 6.89% + Difenconazole 11.49%, Kasugamycin 6% + Thifluzamide 26%, and Hexaconazole 4% + Zineb WP 68% were evaluated against major fungal pathogens of small cardamom such as *Fusarium oxysporum*, *Phytophthora meadii*, *Colletotrichum gloeosporioides* and *Rhizoctonia solani*. The results showed that *P. meadii* was completely inhibited by Azoxystrobin + Tebuconazole, and Propiconazole + Difenconazole in all tested concentrations (0.1, 0.2, 0.3 %) and also by Hexaconazole + Zineb (0.3%). Azoxystrobin +

Tebuconazole (0.2% and 0.3%) also showed the complete growth inhibition of *F. oxysporum*. Results also proved that Azoxystrobin + Tebuconazole (0.3%) and Propiconazole + Difenconazole (0.2% and 0.3%) inhibited 100 per cent mycelial growth of *C. gloeosporioides*. In the case of *R. solani*, full inhibition was achieved with Azoxystrobin + Tebuconazole at all concentrations (0.1, 0.2, 0.3%), and with Propiconazole + Difenconazole (0.3%).

A preliminary study in cardamom under nursery condition revealed that a bio-consortium consisting of VAM and *Trichoderma* is effective in controlling the *Fusarium* wilt of cardamom. During the study on degradation of pesticides through bacterial bioagents, a total of 34 bacterial isolates having ability to degrade the pesticide Chlorpyrifos were isolated from 12 soil samples collected from various localities of Idukki district. The top 10 isolates were shortlisted for further studies.

Ten bacterial isolates were obtained from phyllosphere and rhizosphere of small cardamom to study the antagonistic activity against major pathogens such as *Fusarium oxysporum*, *Rhizoctonia solani*, and *Colletotrichum gloeosporioides*.

Hard gelatin capsule formulation of *T. harzianum*, which can retain the spores up to six months, was developed. It would eventually decrease the cost of transportation by reducing the volume for the end users. Two technologies were released during the 35th Annual Group Meeting (AGM) of All India Coordinated Research Project on Spices (AICRPS) held at Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University (CCS HAU), Hisar which involve the use of fungicides for the control of rhizome rot and leaf blight of cardamom.

b. Large cardamom

Assessment of disease incidence in large cardamom was undertaken through



systematic surveillance. Fixed plot survey was conducted at the ICRI farms in Kabi and Pangthang. The incidence of major diseases such as *Colletotrichum* blight, rust, and *Fusarium* dry rot were recorded. Roving surveys were also conducted across farmers' fields in Sikkim, West Bengal, and Arunachal Pradesh. Diseased and symptomatic samples were collected, and the associated pathogenic microbes were isolated for identification. Isolation, maintenance, and both in vitro and in vivo screening of indigenous beneficial microorganisms (IBMs) were undertaken to assess their efficacy against fungal pathogens. Comprehensive surveys on viral diseases, wilt, and *Fusarium* dry rot were conducted across major large cardamom growing regions of India. Bioagents such as *Trichoderma* spp., *Pseudomonas* spp., *Metarhizium* spp., and *Beuvaria* spp. were mass multiplied at Pangthang Farm.

E. Entomology

a. Small cardamom

The mass production of the Entomo Pathogenic Nematode (ICRI EPN -18) (*Galleria* cadavers) was continued. A total 68,400 *Galleria* cadavers were supplied to farmers of Kerala and Tamil Nadu, in addition to ICRI farm, Myladumpara and Regional Research Station (RRS), Gangtok, Sikkim for the bio management of cardamom root grubs.

For label expansion of new molecules for the management of major insect pests in small cardamom, evaluated Acephate 95% SG in different agro climatic zones covering Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu and report submitted to Central Insecticides Board and Registration Committee (CIB&RC) through M/s Rallis India Ltd, Bengaluru. The molecule was approved by CIB&RC in the 67th meeting of the Central Insecticides Board (CIB) held on 10 December 2024 for use in small cardamom against major insect pests viz., thrips and shoot borer.

Report of research trial on Spinetoram 12 % SC was submitted to CIB &RC through M/s Corteva Agriscience Pvt Ltd., Hyderabad for label expansion for use in small cardamom against major insect pests.

The three native strains of entomopathogenic fungus viz., *Metarhizium* spp. were isolated from root grubs infesting cardamom. Snails and slugs outbreak was recorded in different cardamom plantations of Idukki district of Kerala during the reporting period and were identified by Zoological Survey of India, Pune. The common snail species found in small cardamom in Idukki is *Macrochlamys indica* Godwin Austen and slugs species is *Mariaella dussumieri* Gray. The Giant African Snail (GAS) (*Achatina fulica*), which is an invasive pest, incidence also recorded in a few plantations in the Idukki district.

b. Large cardamom

The study on insect pests and their natural enemies in large cardamom was continued through pest surveillance in both fixed plots and roving surveys conducted across farmers' fields in Sikkim, Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal, and Arunachal Pradesh. As part of indigenous technical knowledge (ITK) validation, the application of ash solution was tested for its efficacy in pest control.

Surveillance on capsule borer infestation revealed a variation from 0–15 per cent across locations, with the highest incidence observed in the Seremna cultivar (4–15%). The identification of pest-tolerant lines revealed that leaf caterpillar incidence ranges from 0.27 per cent in Hario Golsey to 6.69% in ICRI Sikkim-1, shoot fly incidence ranges from 4.22 per cent in Varlangey to 11.94 per cent in Seremna and stem borer incidence showed a general decline, with the highest recorded at 0.38 per cent in Golsey. Capsule borer remained most prevalent in Seremna, with



approximately 15 per cent infestation. Study on the bio-ecology of thrips under varying shade levels found that infestation reached 14.29 per cent under polyhouse conditions, where temperature and humidity are higher compared to room temperature.

F. Transfer of Technology

a. Small cardamom

Twenty four mobile spice clinic programmes were conducted in various locations in cardamom tracts in South India and 459 farmers were benefitted. Twenty-six exposure visits were organised from different colleges, universities and farmers' organisations. A total of 1098 students and farmers were benefitted. About 128 technical advisory services were provided from ICRI Myladumpara for farmers and other stakeholders.

Cardamom suckers of ICRI5 and MCC 260 (13,613Nos.), and improved varieties of black pepper rooted cuttings (12964 Nos.) were produced at ICRI Myladumpara and supplied to the farmers. Bioagents such as *Pseudomonas fluorescence* (Liquid) 1,612 litre, *Trichoderma harzianum* (Liquid) 1198 litre were mass multiplied and supplied to farmers. Nine hundred and thirty-five (935) soil samples were tested for 5,610 nutrient parameters at ICRI, Myladumpara and recommendations given for judicious application of fertilisers. Produced and supplied 6,8400 Entomo Pathogenic Nematode (EPN) cadavers to farmers for the sustainable management of roots grubs in cardamom.

Dr K.G. Jagadeesha IAS, Secretary, Spices Board inaugurated the ICRI- Kisan Seva Kendra, a dedicated farmer facilitation centre during the during "Spice Up Your Business: Stakeholders Conclave and Buyer Seller Meet" held at ICRI, Myladumpara on 11 September 2024. The ICRI- Kisan Seva Kendra aims to support the spice farmers and

provide solutions to various challenges in the agricultural sector.

An MoU has been signed between Spices Board and ICAR- IISR for facilitating the supply of various bio control agents and planting materials from ICAR- IISR, Kozhikode through ICRI- Kisan Seva Kendra for the benefit of spice growers. ICRI Regional Station, Sakleshpur supplied planting materials of small cardamom (2964 nos) and black pepper (366) during the reporting period. Bioagents viz., *Trichoderma* liquid (577 lit), *Trichoderma* solid (416 kg) and *Pseudomonas* liquid (981 litres) were also supplied to the farmers.

b. Large cardamom

During 2024-25, nine spices clinics were conducted covering various aspects of large cardamom in Sikkim, and Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal. As part of the farm advisory service, 162 large cardamom fields were visited, and necessary agro-advisories were provided for plantation improvement. ICRI-Regional Research Station, Gangtok participated in an exhibition at College of Agriculture Engineering and Post-harvest Technology (Central Agricultural University) where research activities and achievements in large cardamom were showcased.

G. Post-harvest Technology

a. Small cardamom

The post-harvest studies revealed that the AI-assisted colour sorting effectively segregates capsules with more weight and more number of seeds, ensuring premium quality monitoring and grading solutions within very short time.

The research studies highlighted the significance of post-harvest operations like washing during pre-curing process and polishing in enhancing the physical (bulk density g/l) and chemical quality (essential oil (%), oleoresin (%)) parameters of cardamom



capsules and significant reduction in acid insoluble ash content. Studies proved that balanced application of secondary nutrients along with NPK is essential in producing cardamom capsules with better physical as well as chemical quality aspects.

b. Large cardamom

The effectiveness of different packing materials for better storage and improved shelf life of cured large cardamom capsules was evaluated using gunny bags, polythene-lined bags, and hermetic storage bags as treatments. Periodic enumeration of fungal and bacterial populations was conducted at three-month intervals to assess microbial growth and the relative preservation efficacy of each packaging material. The study is ongoing, and data analysis is in progress to determine the most suitable packing method for maintaining quality and extending shelf life.

H. Quality Evaluation Laboratory

A total of 106 small cardamom samples were analysed for the identification and quantification of pesticide residue content during the reporting period for 5,092 parameters. The samples comprised of advisory service at farm gate level (52 nos), and research samples for monitoring of pesticide residues at farm gate level (54 nos). None of the samples were detected with the pesticide content beyond the maximum residue limit (MRL) for Saudi Arabia and Japan. On analysis, it was found that ICRI released varieties of small cardamom distinctly differed for phytochemical constituents like flavonoids, phenols, and terpenes in the comparative study for biochemical characters.

I. Externally Funded Projects

a. Small cardamom

An externally funded project entitled “Evaluation of bio-efficacy of new molecule ISOCYCLOSERAM 10% w/v DC (100 DC) against major pests on small cardamom” was sanctioned for ₹18.00 lakh for implementation during the reporting period in association with M/s Syngenta India Ltd., Coimbatore, Tamil Nadu.

b. Large cardamom

An externally funded project under the All India Coordinated Research Project on Spices (AICRPS), supported by ICAR–Indian Institute of Spices Research, was successfully implemented. Under the crop improvement component, activities such as germplasm collection, characterisation, evaluation, and conservation, along with the co-ordinated Varietal Trial (CVT) on large cardamom were undertaken. A special programme titled “*Development of a Model Large Cardamom Nursery Village in Sikkim*” was successfully implemented at Radhu Khandu village in the Dentam area, benefitting 30 farmers.

Published eight extension booklets in English and Nepali covering various aspects of large cardamom viz., Good Agricultural Practices for Large Cardamom Sucker Nursery, Good Agricultural Practices for Large Cardamom Seedling Nursery, Integrated Pest and Pollinator Management (IPPM) in Large Cardamom, and Organic Approaches for Insect Pest and Disease Management in Large Cardamom Nursery.





IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) was enacted by the Parliament and the assent of the President was obtained on 15 June 2005. The objective of the Act is to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The citizens can have access to the information of the Board under the provisions of the Right to Information Act except certain information as notified under Section 8 of the Act and can obtain the information about the Board on payment of a prescribed fees.

The Board effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board designated the Library and Information Officer as the Co-ordinating Central Public Information Officer for co-ordinating the dissemination of information by CPIOs. An Assistant Co-ordinating Central Public Information Officer in Head Office also was nominated. Seven Central Public Information Officers (CPIOs) in Head Office and one Central Public Information Officer (CPIO) in the Research Station at Myladumpara, Idukki were designated

under Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005 to disseminate information under Right to Information Act, 2005. The Director (Research) is nominated as Appellate Authority of the Board to hear appeals under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 and the Library and Information Officer, Spices Board is nominated as the Nodal Officer for ensuring compliance with the proactive disclosure guidelines of the RTI Act 2005. The Deputy Director (EDP), has been designated as the 'Transparency Officer' of the Board to oversee the implementation of obligations under Section 4 of the RTI Act. The Board has disclosed every information required to be disclosed *suo motu* in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act, 2005] through the Board's official website. During 2024-25, a total of 104 RTI applications (through physical and the online portal) and 13 appeals were received under the RTI Act and information disseminated to all the cases within the stipulated time. Three Central Information Commission (CIC) hearings were held during this period. An amount of Rs.150/- was received as RTI registration fee. The Quarterly RTI Returns (first quarter to fourth quarter) were updated in the Central Information Commission's website as scheduled.





WAY FORWARD

India, widely celebrated as the Land of Spices, is the world's largest producer, consumer, and exporter of spices and spice products. With cultivation spanning over 75 distinct spices across varied agro-climatic zones, Indian spices are exported to more than 180 countries, comprising over 225 unique products. Over centuries, India has established itself as a trusted global supplier of a diverse array of spices and value-added spice products. The sector contributes approximately nine per cent to India's total agricultural exports and over 41 per cent to horticultural exports.

The country's agro-climatic diversity enables spice production in almost every state. During 2024-25, India produced around 12 million MT of spices and exported over 1.80 million MT, accounting for roughly 15 per cent of total domestic production. The interventions of the Spices Board have significantly boosted exports, increasing from US\$ 229.90 million in 1987 to US\$ 4.72 billion in 2024-25. Compared to the previous year, spice exports recorded a 17 per cent increase in volume, eight per cent growth in value in rupee terms, and six per cent in dollar terms. Between 2014-15 and 2024-25, India's spice exports grew by 101 per cent in volume, 168 per cent in rupee value, and 94 per cent in dollar value by registering a CAGR of seven per cent in volume, 10 per cent in rupee value, and seven per cent in dollar value.

The global spices and seasonings industry is positioned at the intersection of tradition and innovation. While firmly rooted in centuries old culinary practices, the sector is rapidly evolving to address modern health trends, increasing consumer awareness, and globalisation. This transformation is being shaped by shifting consumer preferences, ever evolving international regulations, climate-related challenges, and rapid technological

advancements. These trends underscore the urgent need for the Indian spice industry to intensify its focus on quality, authenticity, sustainability, and transparency to successfully harness emerging opportunities and mitigate associated challenges.

As global consumer demand for ethnic flavours, functional foods, and clean-label products in on the rise, the market for natural, health-promoting ingredients is expanding steadily. However, the sector also face challenges such as adulteration, labelling inconsistencies, evolving regulatory frameworks, ethical sourcing, food safety concerns, etc. To sustain and strengthen India's global leadership, the spice industry must adopt a forward-thinking strategy that focuses on export promotion, technological advancement, and inclusive, sustainable growth. Exporters who prioritise quality, traceability, and sustainability are likely to gain a competitive edge in this evolving marketplace.

India has also taken proactive steps to support organic farming, recognising the imperative of aligning with global sustainability norms. The launch of the 8th Edition of the National Programme for Organic Production (NPOP) in 2024 represents a major milestone in India's commitment to sustainable agriculture. The updated guidelines under NPOP reflect global best practices in organic production and processing, ensuring Indian organic spices continue to meet international standards of quality, safety, and consumer trust.

However, persistent challenges remain, particularly in achieving social sustainability across the supply chain. A considerable proportion of India's spices are produced by smallholder farmers, many of whom face financial constraints and lack access to infrastructure and post-harvest facilities. Without adequate institutional support, these farmers



may turn to chemical inputs or shift to more lucrative crops, thereby affecting the availability of sustainably grown, high-quality spices.

To address these issues, there is increasing emphasis on improving traditional farming practices. Initiatives are being implemented to provide farmers with better training, access to technology, and improved storage and processing facilities. These interventions are intended to increase price realisation at the farm level, reduce reliance on intermediaries, and ensure fairer income for primary producers.

The sector is also responding to the growing global emphasis on environmental sustainability. With stringent regulations in place, buyers are increasingly seeking certifications like Fairtrade, Rainforest Alliance, and compliance with regulatory frameworks of their respective countries. Indian producers are adopting practices such as organic, integrated pest management, and sustainable agricultural methods to ensure compliance and remain competitive.

Nevertheless, the financial and administrative burdens linked with compliance, certification, and supply chain traceability can be challenging especially for small and marginal farmers. These challenges may restrict access to premium international markets such as the EU, where regulatory requirements are stringent. Institutional and policy support will be crucial in enabling these producers to make the transition towards sustainable and compliant agricultural systems.

Although this shift is expected to result in higher product prices and consolidation within the spice sector, it will also reflect fairer compensation for farmers and the true cost of responsible production. Exporters, processors, and aggregators must play an active role in supporting this transition. To truly benefit from the evolving global demand, Indian stakeholders must adopt sustainability frameworks that align with international market expectations.

Despite steady growth in spice exports, the share of value-added products in India's export basket

has remained relatively unchanged at around 50 per cent in recent years. This presents an untapped opportunity, particularly in fast-growing sectors such as nutraceuticals, cosmetics, and pharmaceuticals. Key obstacles include limited technological advancement and inadequate processing infrastructure. Bridging these gaps is vital for enhancing India's share in the global market for high-value spice products.

The global food industry is now heavily influenced by transnational food and beverage corporations, which have played a pivotal role in shaping demand for new products across markets. In parallel, the convenience food segment-comprising Ready-to-Eat (RTE), Ready-to-Cook (RTC), and Ready-to-Drink (RTD) categories-has seen rapid expansion, driven by urbanisation, changing lifestyles, and increasing demand for quick and easy food solutions. The post-pandemic period further accelerated this trend, with consumers favouring products that offer extended shelf life and minimal preparation.

In this evolving context, spices play a critical role not only in enhancing taste and aroma but also in contributing to product shelf life and nutritional value, owing to their natural preservative and bioactive properties.

In view of these emerging trends, the Spices Board is implementing the central sector scheme "Sustainability in Spice Sector through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development (SPICED)", aimed at developing a robust, sustainable, and export-ready spice ecosystem.

Through the SPICED scheme, support is extended to farmers for improving production and productivity of cardamom (small & large), adopting organic and sustainable cultivation practices, and post-harvest quality improvement; to exporters for developing infrastructure for value addition, processing, and quality assurance; to start-ups and innovators for new product development, branding, and enhancing market linkages.



Through its consolidated efforts, the Spices Board is targeting to achieve USD 10 Bn exports of spices and spice-based products by enabling a sustainable and safe export supply chain focused on innovative and value-added products. The Board also aims at achieving export of US\$ 6.5 billion of value-added spice products in the export basket increasing its share from the current level of 50 per cent to 65 per cent. For this, the proposed focus areas of intervention are;

1. Enhancing Value Addition Capacity by Upgrading and strengthening India's spice manufacturing infrastructure to facilitate higher-end value addition and increase the share of processed spice exports.
2. Establishment of Spice Incubation Centres by partnering with leading institutions to support exporters, entrepreneurs, start-ups, and Farmer Producer Organisations (FPOs) in transforming innovative ideas into market-ready spice products and technologies, with a focus on exports.
3. Adoption of Advanced Technologies to promote technological innovation through incubation support, digitisation, and adoption of modern processing tools. It is also proposed to enhance connectivity between spice growers and exporters through technology-based platforms to facilitate traceability and direct sourcing for exports.
4. Support development of new spice-based products and applications aligned with changing global consumer preferences
5. Conduct detailed studies on potential export markets and formulate strategies to strengthen India's presence in both new and existing segments.
6. Launch promotional campaigns in coordination with Indian embassies in target export destinations.
7. Promote GI-tagged spices and unique Indian varieties to differentiate Indian spices and spice products in the global marketplace.
8. Implement robust quality assurance programmes to ensure compliance with international standards and upgrade quality evaluation laboratories to meet global regulatory requirements.
9. Focus on post-harvest practices to enhance the availability of export-quality spices and value-added products.
10. Implement targeted programmes for spices from the Northeastern region, GI varieties, and those with high intrinsic value, including initiatives to support import substitution.
11. Strengthen trade promotion efforts, including the creation of international market linkages and targeted branding of Indian spices.
12. Undertake applied research to support the spice sector in areas such as bio-prospecting, climate-resilient practices, patenting, and commercialisation of innovative products, with a focus on export readiness.
13. Conduct training and capacity-building programmes for stakeholders across the spice value chain to address emerging global requirements, enhance knowledge transfer, and support sustainable sectoral growth.

Global trends in food processing are evolving, and a nuanced understanding of international market dynamics is critical. Aligning production with shifting consumer preferences and regulatory expectations requires coordinated efforts from all stakeholders, including farmers, processors, exporters, and policymakers. A continued focus on maintaining and enhancing quality and safety standards across the spice value chain is crucial to ensure that the Indian spices meet the stringent requirements of global markets. Upholding these standards will help build a strong brand identity for Indian spices, associated with quality, safety, and trust and thereby strengthen India's position in the global spice trade.





Reply for the Separate Audit Report on the accounts of Spices Board for the year ended 31st March 2025

| A | BALANCE SHEET | |
|-------|--|--|
| A.1 | LIABILITIES | Reply |
| A.1.1 | EARMARKED / ENDOWMENT FUND - ₹339.16 crore (Schedule -3) | |
| | <p>i) Depreciation on fixed assets procured from earmarked/endowment funds/grant in aids was being accounted as expenditure in Income and Expenditure Account instead of treating the depreciation charge as adjustment/utilization in earmarked/endowment funds/related grants. Thus, the balance of Earmarked/Endowment funds, deficit for the year and Corpus/Capital Fund were not correctly stated in the accounts. However, due to non-availability of details of assets procured from earmarked/endowment funds and assets procured from grants in aid, audit could not quantify the financial impact of the incorrect accounting of depreciation charge.</p> | <p>(i) Since the Assets procured from the Endowment Fund have already been booked against the Grant-in-Aid received from the Govt of India, the depreciation is also charged against the grant and not to the Endowment Fund. The assets procured from the Grant-in-aid and Endowment Fund could not be identified, separately and hence the Board finds it difficult to segregate the depreciation for the assets procured from Endowment Fund. However, during the period from 2023-24 the assets procured under TIES, NHM, etc., (External Funds) are being booked against Endowment Fund. The Board could not take any corrective action due to the reason that the Assets procured from Grant-in-aid and Endowment Fund could not be segregated in old cases.</p> <p>(ii) The Earmarked Funds ASIDE (Assistance to State for Developing Export Infrastructure and Allied Activities) is an Assistance from Ministry of Commerce and Industry in addition to the Grant-in-Aid. The Assets procured from these funds are taken as the assets of the Board and not included as expenditure from the ASIDE funds shown in Endowment Fund balance. Though the Endowment Fund under ASIDE shows closing balance, the same is not actually with the Board under that particular Endowment Fund. The fund balance available in the ASIDE Endowment Fund is utilised for procurement of assets and the same has been included in the total assets of the Board and booked against Grant-in-Aid received for that particular year. The Board could not take any corrective action due to the reason that the Assets procured from Grant-in-aid and Endowment Fund could not be segregated in old cases.</p> |



| | <p>ii) Earmarked/Endowment funds were meant for a specific purpose. The assets for Spices Parks under ASIDE scheme were procured in previous years utilizing the funds of 115.83 crore but use of assets was not expensed against the endowment funds.</p> | <p>The Board is not having sufficient funds in its Pension Fund as per the actuarial valuation report of 2021 and hence could not meet the pension payments exclusively from the Pension Fund.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|----------|------------------|-------|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|----------------------------|--------|-------|-------|--------|--|-------|---------|---------|-------|---|
| | <p>Further, annual pension liabilities of ₹24.94 crore and expenses incurred for the upkeep and maintenance of Quality Evaluation Labs (QELs) amounting to ₹29.34 crore for the current year were met by utilising grants-in-aid from Government of India, though the Board has earmarked funds for pension and the upkeep and maintenance of QELS. In another instance, analytical charges amounting to ₹12 crore received during the year were transferred to earmarked endowment funds i.e. Pension Fund (10 crore) and “Quality Standard in Export of Spices” (₹2 crore) (Note 1 of Schedule 57-Notes to Accounts) directly without accounting as income in the Income and Expenditure Statement.</p> <p>Spices Board did not take any corrective action in this regard despite the repeated comments in previous years 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> | <p>As regards upkeep and maintenance of Quality Evaluation Labs (QEL), the Board expects a significant capital expenditure for refurbishment of equipment in Labs for the unforeseen breakdown of costly equipment which will lead delay in generating quality reports for export consignments.</p> <p>This procedure is unavoidable to sustain the quality standard in export. The Board anticipate a substantial capital expenditure for the same and hence, earmarking fund to meet the expenses and not for the routine expenditure of the Labs.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>A.1.2</p> | <p>Current Liabilities and Provision – Provisions : ₹325.37 Crore (Schedule 7B)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>i) The Spices Board conducted an Actuarial valuation of Employee - related Liabilities and arrived at figure of ₹348.72 crore as on 31.03.2021 against which it has provided for ₹325.31 crore as on 31.03.2025 as detailed below:</p> <table border="1" data-bbox="277 1549 815 1938"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pension</th> <th>Gratuity</th> <th>Leave Encashment</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actuarial value as on 31.03.2021</td> <td>319.07</td> <td>18.54</td> <td>11.10</td> <td>348.72</td> </tr> <tr> <td>Provision as on 31.03.2025</td> <td>272.21</td> <td>29.70</td> <td>23.40</td> <td>325.31</td> </tr> <tr> <td>Shortfall (Excess) w.r.t to 31.03.2021 valuation</td> <td>46.86</td> <td>(11.16)</td> <td>(12.30)</td> <td>23.41</td> </tr> </tbody> </table> | | Pension | Gratuity | Leave Encashment | Total | Actuarial value as on 31.03.2021 | 319.07 | 18.54 | 11.10 | 348.72 | Provision as on 31.03.2025 | 272.21 | 29.70 | 23.40 | 325.31 | Shortfall (Excess) w.r.t to 31.03.2021 valuation | 46.86 | (11.16) | (12.30) | 23.41 | <p>The Observation of Audit is noted.</p> |
| | Pension | Gratuity | Leave Encashment | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuarial value as on 31.03.2021 | 319.07 | 18.54 | 11.10 | 348.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provision as on 31.03.2025 | 272.21 | 29.70 | 23.40 | 325.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shortfall (Excess) w.r.t to 31.03.2021 valuation | 46.86 | (11.16) | (12.30) | 23.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



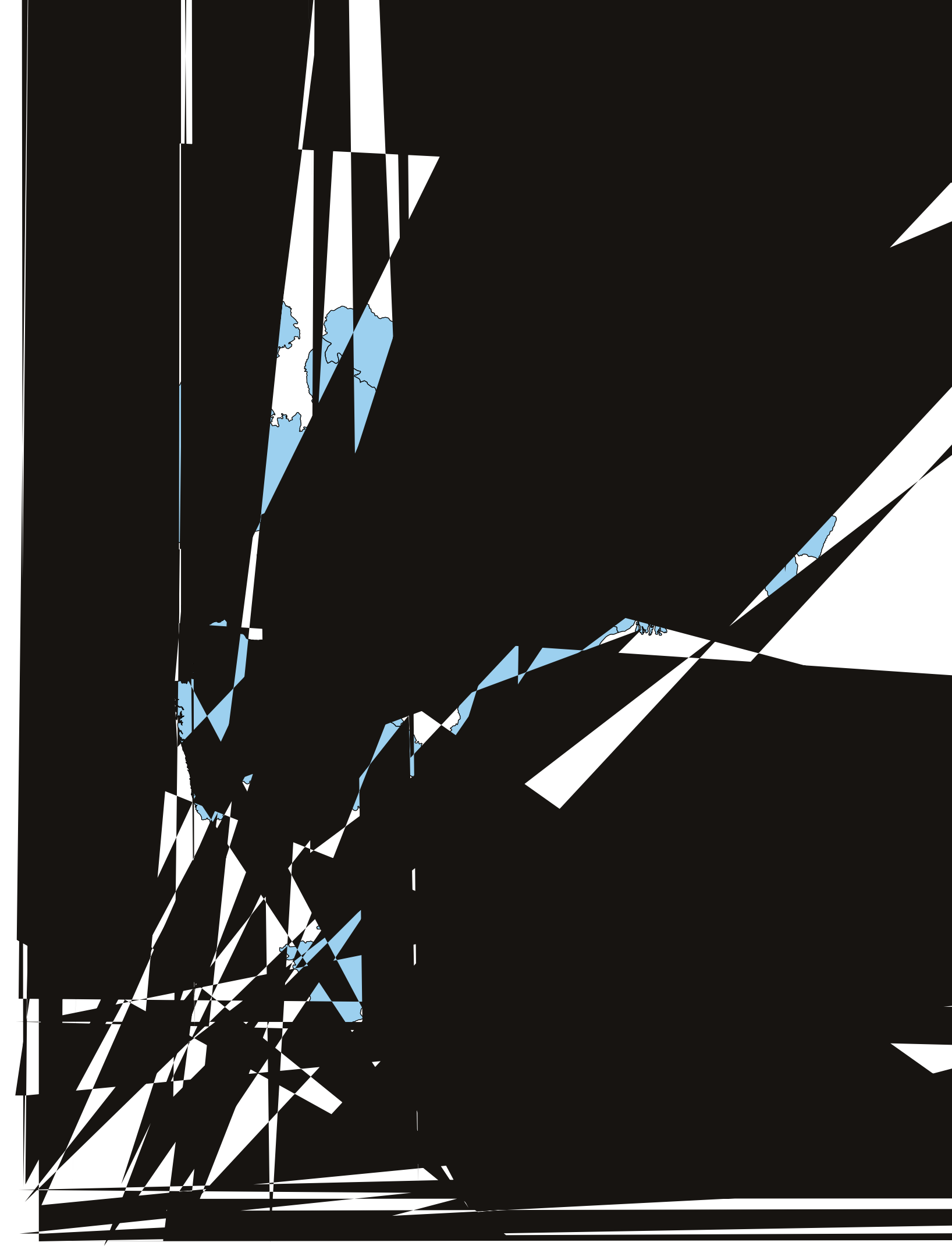
| | | |
|--------------|--|---|
| | <p>The non-provisioning of the actuarial liability has resulted in understatement of provisions for Employees Benefits and deficit for the year by 23.41 crore (net).</p> <p>ii) As per Accounting standard 15 (Para 58) the detailed actuarial valuation of the present value of defined benefit obligations may be made at intervals not exceeding three years. However, the last actuarial valuation was carried out in 2020-21, i.e., a period exceeding three years as on 31.03.2025.</p> | |
| A.2 | Current Assets, Loan, Advances, etc., Current Assets- ₹316.41 crore (Schedule 11 A) | |
| | <p>The above does not include ₹0.87 core being the accumulated rent receivable from Flavourit Spices Trading Limited (FSTL) for the leased facilities of Spices Board. Thus, the Current Asset and Corpus/Capital Fund were understated by ₹0.87 core. This issue was highlighted in the SAR 2023-24 also.</p> | <p>The observation of Audit is noted. The dues from FSTL shall be incorporated in the Annual Accounts of the Board during the current financial year (2025-26)</p> |
| A.2.2 | Current Assets, Loan, Advances, etc.,- Loan and Advances - ₹26.72 crore (Schedule 11B) | |
| | <p>The above includes long pending advances of ₹6.72 crore being carried over from 2017-18 onwards. The Board was unable to identify and recover these amounts as the breakup of the advances was not traceable. Considering the passage of time and the absence of relevant records, a provision for advances should have been created.</p> <p>The non-creation of provision resulted in overstatement of advances and understatement of deficit for the year by ₹6.72 crore. This matter was pointed out in SAR 2023-24.</p> | <p>The observation of Audit is noted. In this connection it may please be noted that the Board had already settled some of the long pending advances viz Advance for purchase of Machinery Rs. 58.01 lakhs, Pay Advance Rs. 4.72 lakhs, Mobilisation Advance Rs. 39.00 lakhs and TA Advance Rs. 4.91 lakhs during the year 2024-25. The Board is trying to identify those advances from the earlier software. If the Board could locate the details of those unsettled advances from the previous software, action shall be initiated to settle those advances.</p> |



| | | |
|--------------|---|--|
| B. | Income and Expenditure Account | |
| B.1 | Income | |
| B.1.1 | Grant from Govt. of India-Plan - ₹130.00 crore (Schedule 13) | |
| | <p>The above includes grants of ₹1.01 crore (₹1. crore grant for creation of capital assets other expenditure and ₹0.01 crore (Grants for creation of Capital Assets - NE) received from the Ministry of Commerce and Industry. The Board, instead of accounting the above grants as per para 8 of Accounting Standard 12 – Government Grants, accounted the grant amount as income in Income and Expenditure Account under income approach.</p> <p>This has resulted in over statement of the grants in aid from GOI – Plan in Income and Expenditure Account. understatement of deficit and understatement of Earmarked/ Endowment Fund by ₹1.01 crore as on 31 March 2025.</p> | <p>The observation of Audit is noted. Necessary modification in this regard shall be made in the annual accounts for the year 2025-26. The Income and Expenditure Account for the current financial year shall be prepared by crediting Grant in aid to the account after deducting the amount utilised for acquisition of Capital Assets.</p> |
| C. | Receipts and Payments Account - NIL | |
| D. | Accounting Policies - NIL | |
| F. | General - NIL | |
| F | <p>Management Letter Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.</p> | Observations noted |
| G | <p>(i) Adequacy of Internal Control Out of the 85 accounts classified under Current Accounts with Banks, for 41 cases of confirmation balance (₹10,56,60,233.60) were without showing whether it is Current account or Savings bank account. In 11 cases (amounting to ₹95,55,445) of confirmation balance were shown as Savings Bank Account. As on 31 March 2025, the book balance of Central Bank of India, Hyderabad Branch, was ₹53,083, whereas the balance as per the bank confirmation was ₹8,377. The reconciliation of balances were not done.</p> | Observations noted |



| | | |
|----------|--|--------------------|
| | <p>(ii) Adequacy of Internal Audit System: As per the records furnished to audit, internal audit was not conducted during the year 2023-24 and 2024-25 in any of the 82 branch offices and HO of Spices Board. This issue was commented in SAR of 2023-24 also.</p> | Observations noted |
| | <p>(iii) System of Physical verification of fixed assets: The Board had carried out physical verification of fixed for all the 83 units during the year 2024-25.</p> | |
| | <p>(iv) System of Physical verification of inventory: The physical verification and valuation of inventory has been</p> | Remark Only |
| | <p>(v) Regularity in payment of statutory dues: The Board has regularly deposited all statutory dues like GST, TDS, CPF etc</p> | Remark Only |
| | <p>(vi) Other matters relating to functioning of the entity: NA</p> | Remark Only |
| H | <p>Grants in aid Opening balance of grants – in – aid was nil. Grants – in – aid received during the year from Government of India were amounting to ₹130 crore. The same was fully utilized during the year.</p> | Remark Only |





Promoting Heritage, Hygiene & Health



Spices  India
FLAVOURFULLY YOURS

Now open at:

Spices India
Lulu Mall, Edapally,
Kochi-682 024, Kerala
Tel: 0484-4073489